R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 13
01 से 15 अप्रैल 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

सजा बनी संजीवनी!

राहुल गांधी का तेवर और विपक्ष का जोश रोक पाएगा मोदी लहर?

कांग्रेस की सियासी शहादत पर कब तक एकजुट रह पाएगा विपक्ष?

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

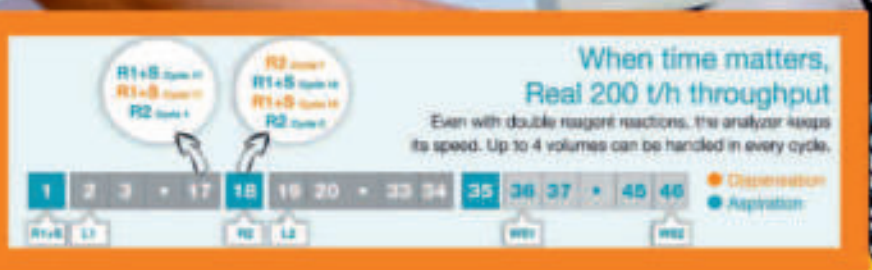

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

भर्राशाही

9 | वाकई! मप्र अजब है...

वाकई मप्र अजब है, गजब है। इसका ताजा नजारा हाल ही में संपन्न बजट सत्र में सामने आया। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम संसदीय परंपरा के विपरीत जाकर निर्देश देते पाए गए। नियमानुसार किसी भी...

राजपथ

10-11 | भाजपा-कांग्रेस...

मप्र में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव अब के चुनावों से अलग होगा। क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच जहां मुख्य घमासान होगा, वहीं दिल्ली, पंजाब के साथ कई राज्यों में करिश्मा दिखा चुकी आम...

पर्यावरण

15 | मप्र की नदियों का घुट रहा दम

मप्र की नदियों का दम घुट रहा है। इन नदियों में इतना कचरा बहाया जा रहा है कि उसे साफ करने में नदियां हांफ रही हैं। उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। इनका पानी नहाना तो दूर आचमन लायक भी नहीं बचा है। यह नदियां जैविक प्रदूषण से...

राजकाज

18 | मप्र में किंगमेकर बनेंगे किसान

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 और कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर काम कर रही हैं। दोनों पार्टियों के जिम्मेदार अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि मप्र में उसी की सरकार बनेगी जिसका साथ किसान देंगे।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

फिल्म दलाल का यह गीत आपने सुना ही होगा- ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी... कुछ इसी तरह की स्थिति इस समय भारतीय सियासत में देखने को मिल रही है। मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। राहुल की इस सियासी शहादत ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इससे विपक्ष के खेमे में उबाल आया है।

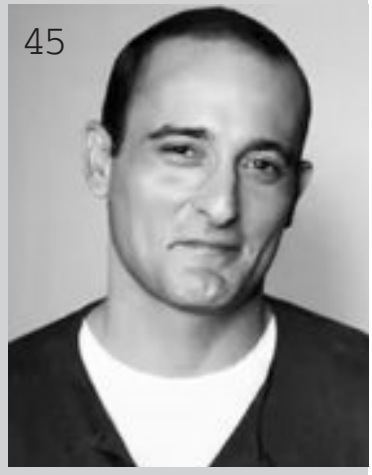

राजनीति

30-31 | जीत का मुद्दा किसान या...

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इन तीन प्रदेशों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने को हैं, ऐसे में यहां सभी दल अपना-अपना जोर आजमा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी दल, अपनी रणनीति बनाने में लगे...

महाराष्ट्र

35 | महाराष्ट्र में करवट ले...

महाराष्ट्र में आए उपचुनाव के नतीजों ने आगामी चुनावों में भाजपा को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। कसबा सीट पर 28 साल पुराना किला महाविकास अघाड़ी ने तोड़ दिया है। कसबा पेठ सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज्यादा परेशान कर...

बिहार

38 | अपने ही जाल में उलझ गए...

अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने रातोंरात एनडीए का दामन छोड़ राजद का हाथ थाम लिया और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी। कांग्रेस को साथ लेकर महागठबंधन की सरकार बना ली। तब उन्हें उम्मीद थी कि उनको...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

...आराम से सो जा भगवान करेंगे पास।

गत दिनों सोशल मीडिया पर ये पंक्तियां खूब वायरल हुईं...

लिखना पढ़ना छोड़ दे बंदे, नेकियों पर रख आस,
चादर उठा और आराम से सो जा भगवान करेंगे पास।

दरअसल, ये पंक्तियां मप्र में बोर्ड परीक्षाओं के लीक हुए पर्चों के संदर्भ में वायरल की गई थीं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होते रहे और सरकार दावा करती रही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। दरअसल, सरकार का कहना था कि परीक्षा से कुछ देर पहले अगर पेपर लीक होता है तो इसे लीक नहीं माना जाएगा। यह बात खुद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही। जब पेपर लीक हो रहे थे, तब प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। संभवत ये पहला मौका था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक मामला सदन में गूंजा हो। ये भी मिसाल है कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस मामले में दो दिन के भीतर दो अलग-अलग बयान दिए। बाद में इस मामले में अपने ही बयान से पलटते हुए कह दिया कि 10वीं और 12वीं का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लिहाजा दोबारा परीक्षाएं करवाए जाने का सवाल खड़ा नहीं होता। जबकि एक पखवाड़े में 10वीं और 12वीं के 14 पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं। इस मामले में 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि ये गिरफ्तारियां किसलिए की गई हैं। दरअसल, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार जितने प्रयास कर रही है, वे सारे विफल हो रहे हैं। न स्कूलों में शिक्षक हैं, न बिल्डिंग है, तो पढ़ाई कहां से होगी। यानी सबकुछ भगवान भरोसे है। उस पर यह साल चुनाव का है। ऐसे में सरकार यह नहीं चाहती है कि छात्रों का रिजल्ट खराब हो। क्योंकि अगर परीक्षा परिणाम खराब होंगे तो सरकार विपक्ष के घेरे में आ जाएगी। इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबकुछ जानते हुए सरकार आंखें बंद किए हुए है। पेपर लीक मामले में नौबत यहां तक आ गई कि ऑनलाइन पेपर भी बेचा गया। बीकॉम के एक छात्र को सोशल मीडिया पर पेपर बेचने के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया है। दमोह में भौतिकी का पेपर लीक होने के मामले में चपरासी की गिरफ्तारी की गई। भोपाल के 4 शिक्षक भी पेपर लीक मामले में आरोपी के तौर पर धरे गए। इसके अलावा परीक्षा में लापरवाही की वजह से मप्र बोर्ड ने 46 केंद्र अध्यक्षों समेत 19 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मप्र विधानसभा के बजट सत्र में पेपर लीक मामले को लेकर सदन से विपक्ष का बहिर्गमन भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने इसको लेकर सरकार पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। लगातार 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। उधर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरोप लगाया कि पेपर लीक का भ्रम फैलाकर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। जब सुबह 8:30 बजे परीक्षा में बच्चे हॉल में बैठ गए, उसके बाद ही यह प्रश्न पत्र बाहर आए। इसके अलावा जो भी पर्चे वायरल हुए थे, वह फर्जी पाए गए हैं। एक भी प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले बाहर नहीं गया। यह एक गिरोह है जो योजनाबद्ध तरीके से सरकार के सिस्टम को बदनाम करना और बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। दरअसल मप्र में पेपर लीक होना और परीक्षार्थी की जगह मुन्नाभाई का एग्जाम देना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। लेकिन यह चर्चा सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहती।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 13, पृष्ठ-48, 1 से 15 अप्रैल, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बेरोजगारों का बजट

सरकार का इस बार का बजट बेरोजगार युवाओं के लिए खास है। सरकार ने नई योजनाएं लाकर युवाओं को काम दिलाने का भरोसा दिलाया है। इससे मप्र को विकसित करने में युवाओं का भी अहम योगदान होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए यह प्रयास अच्छा साबित होगा।

● **निधि राजपूत,** जबलपुर (म.प्र.)

बारिश से किसान बेहाल

गर्मी के मौसम में बारिश होने से कई किसानों ने अपनी फसलों को खो दिया है। सरकार को किसानों के लिए जल्द से जल्द मुआवजे का इंतजाम करना चाहिए। जिससे उनकी बर्बाद फसलों का खामियाजा उन्हें मिल पाए। बेमौसम हुई बारिश से किसान परेशान है।

● **प्रियंक चतुर्वेदी,** भोपाल (म.प्र.)

नदियों की सफाई

नदियां मप्र की पहचान हैं। प्रदेश की नदियों को स्वच्छ बनाए रखना सरकार के साथ-साथ हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे यहां की नदियों को देश ही नहीं विदेशों से भी देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए इसे स्वच्छ व साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है।

● **हेमराज कुशवाहा,** इंदौर (म.प्र.)

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मप्र ऐतिहासिक स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों और धार्मिक स्थलों सहित कई पर्यटन स्थलों से भरपूर है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने महाकाल जैसे प्रमुख मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान देते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया है। इस निवेश से पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रसन्नता का विषय है कि राज्य शिक्षा का केंद्र भी बन गया है और इस प्रकार के प्रावधान युवाओं को रोजगार दिलाने में भी सहायक होंगे। शिवराज सरकार के इस कदम से मप्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश सहित विदेशों से भी टूरिस्ट यहां विजिट करेंगे।

● **राघव कुमार,** विदिशा (म.प्र.)

चुनावों की आहट

मप्र सहित देशभर के कई राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों की आहट तेज हो रही है। राज्यों के राजनीतिक दल लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां तरह-तरह की घोषणाओं से किसानों, युवाओं और आम जनों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। वैसे जनता को पता है कि उसे किसके साथ जाना है। आजकल लोग समझदारी के साथ ही फैसला करते हैं। और अपने हित की सरकार को चुनते हैं। उन्हें पता है उनके लिए कौन सही है।

● **जगदीश सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

अवैध कटाई रोके सरकार

हमारा प्रदेश हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रदेश में बीते तीन-चार सालों में अवैध कटाई के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी मुख्य वजह वन अधिकार पत्र वितरण और सरकार द्वारा वनों के जरिए स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित किया जाना है। इस प्रकार की अवैध कटाई से जहां प्रदेश की सुंदरता खराब हो रही है, वहीं जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **नगमा खान,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

धामी के दो साल, हिंदुत्व के साथ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा किया। इस अवसर पर हुए मुख्य आयोजन में धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अटलजी ने बनाया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड से बेहद लगाव है और उत्तराखंड उनकी कर्म और तपस्थली दोनों रही है। धामी ने उत्तराखंड को 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का अपना संकल्प दोहराया और धामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पिच तैयार कर ली और इस साल जुलाई में समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने का ऐलान किया। चैत्र नवरात्र में सार्वजनिक छुट्टी करके और महिलाओं को नियुक्ति पत्र देने तथा पूरे राज्य में चैत्र नवरात्रि पर देवी के मंदिरों में सरकारी खर्चे पर पूजा करके हिंदू पत्ते का दांव खेला। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को एक-एक लाख रुपए चैत्र नवरात्र में पूजा अर्चना के लिए दिए गए और पहली बार उत्तराखंड में चैत्र नवरात्र में सरकारी खर्चे पर देवी के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।

कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे केसीआर!

तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के आवास पर बीआरएस के मंत्रियों की गुप्त बैठक के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच गठबंधन हो सकता है। सूत्रों की मानें तो बैठक के दौरान बीआरएस मंत्री सत्यवती राठौड़, सविता इंद्रा रेड्डी सहित अन्य मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में आगामी चुनावों और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बीआरएस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें ऐसे समय लग रही हैं जब कांग्रेस ने केसीआर की बेटी के कविता पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हमला बोला है। गठबंधन की चर्चा पर जानकारों का कहना है कि यह बैठक कांग्रेस और बीआरएस के बीच सांठगांठ की ओर इशारा करती है। इससे पहले खुद कविता कह चुकी हैं कि उनके कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की संभावना है। इसे लेकर कांग्रेस के कोमाट्रेडी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि अगर हमारा गठबंधन होगा तो बीआरएस के साथ ही होगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और बीआरएस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए साथ आ गई हैं।

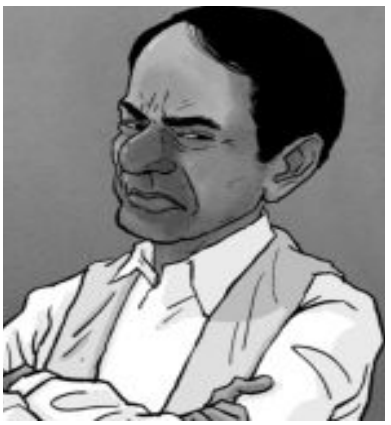

कैंब्रिज की लड़ाई में भाई-भाई

वरुण गांधी अपनी पार्टी को लेकर नरम दिख रहे हैं। पीलीभीत के सांसद अपने सूबे और केंद्र की डबल इंजन सरकारों के प्रति जिस तरह का आलोचनात्मक रवैया दिखा रहे थे, वह अब नदारद है। ताजा संकेत उन्होंने राहुल गांधी से अपने अपरोक्ष अलगाव की बात कहकर दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय लोकतंत्र के विषय पर बोलने का निमंत्रण ब्रिटेन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें भी मिला था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे अपने लोकतंत्र की खामियों की चर्चा पार्टी फोरम और देश के भीतर ही दूसरे फोरम पर करना उचित समझते हैं। विदेश की धरती पर नहीं। वरुण ने जानकारी तब दी है जब राहुल गांधी कैंब्रिज के अपने भाषण को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं। वरुण गांधी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त किसानों की समस्याओं की चर्चा कर राहुल का परोक्ष समर्थन किया था। तब उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई गई थी। हालांकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा का समर्थक बता राहुल ने उनसे कन्नी काट ली थी। 2024 के चुनाव को करीब देख अपना टिकट बचाने के लिए वरुण को राहुल के विरोध का यह समय जंचा होगा।

दूर होंगे गिले-शिकवे

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की एक मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। वैसे भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में गिने-चुने लोग ही बचे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और पुरानी शिवसेना गिले-शिकवे भुलाकर एक बार फिर साथ आ सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके संबंध खराब हैं। सदन में भी चर्चा के दौरान भाजपा नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे से इशारों में साथ आने को कहा। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उद्धव जी एक बार फिर शांति से विचार करें। इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने संकेतों में उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया है। दरअसल, बीते साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी और फिर भाजपा के साथ सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस को इस टूट-फूट का मास्टरमाइंड माना जाता है।

हाथ कब मिलाएंगे ?

भाजपा और संघ परिवार का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे। विरोधी दल अपनी तरफ से जोड़ते थे-पर तारीख नहीं बताएंगे। आज ऐसी ही खिल्ली उनकी उड़ रही है जो दावा तो करते हैं कि 2024 में भाजपा को दिल्ली की सत्ता से हटाएंगे, पर आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। भाजपा से परेशान तो ये सभी दल हैं। उदाहरण भी देते हैं कि जिस तरह 1977 और 1989 में विपक्षी दलों की एकता से ही तब भाजपा से भी ज्यादा ताकतवर रही कांग्रेस को सत्ता से हटाया था। पर, एकता करने को राजी नहीं। दिल्ली में अडाणी के विरोध में हुए प्रदर्शन से राकांपा और तृणमूल के नदारद रहने से इसकी फिर पुष्टि हुई। बसपा पहले ही भाजपा से ज्यादा कांग्रेस और सपा को कोसती रही है। तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वाइएसआर कांग्रेस हो या बीजू जनता दल, इनमें कोई भी कांग्रेस की छतरी के तले आने को तैयार नहीं। जबकि यूपीए में शामिल दलों की स्पष्ट सोच है कि उन्हें 1996 के संयुक्त मोर्चे के प्रयोग पर भरोसा नहीं।

गुत्थी सुलझ गई, पर उलझा दी गई

गत वर्ष प्रदेश के एक बड़े विभाग में काम करने वाली एक लड़की ने किराए के मकान की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद मीडिया ट्रायल कुछ इस तरह हुआ कि तरह-तरह के कयास लगाए गए। कयासों के कारण मामला इस तरह उलझा कि लोग उसे भूलते चले गए। जान जाने वाले की जान चली गई, लेकिन जिम्मेदार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दरअसल, जिस लड़की ने आत्महत्या की थी, वह मंत्रालय में पदस्थ थी। लड़की प्रदेश के एक अन्य महानगर की रहने वाली थी, इसलिए वह यहां एक किराए के मकान में रहती थी। उसकी मौत के बाद कई तरह की कहानियां गढ़ी गईं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच की और आत्महत्या की गुत्थी भी सुलझा दी, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण अफसरों ने उसे इस कदर उलझा दिया कि मामले को ही बंद करना पड़ा। जानकारी के अनुसार लड़की की आत्महत्या के पीछे उसका एक अधिकारी के साथ मधुर संबंध था। ये साहब उद्योग विभाग के ही हैं और मालवा के एक बड़े जिले में पदस्थ हैं। लड़की जब भोपाल आई तो उक्त अफसर भी कभी-कभार भोपाल आते और श्यामला हिल्स स्थित एक आलीशान होटल में विश्राम करते थे। पुलिस ने अपनी विवेचना में जब सीडीआर निकाली तो सारी हकीकत सामने आ गई, लेकिन आला अफसरों ने इस मामले को दबवा दिया।

आखिर जोड़ी टूट गई

अपने कर्तव्यों के कारण पुलिस कठोर कदम उठाती है इस कारण उसे पत्थर दिल माना जाता है। लेकिन हकीकत इससे दूर है। पुलिस वालों के दिल में प्यार उमड़ता है। ऐसे ही 2 आईपीएस अधिकारी मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनमें से एक पुरुष और एक महिला है। पिछले कुछ महीनों से इनकी यारी के किस्से चटखारे लेकर सुने और सुनाए जा रहे थे। ये दोनों राजधानी भोपाल में पदस्थ थे। लेकिन गत दिनों उस समय इनकी जोड़ी टूट गई जब पुलिस विभाग में अधिकारियों का बड़ा तबादला हुआ। हालांकि आईपीएस अधिकारियों का तबादला बहुप्रतीक्षित था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन्हें इस तरह अलग-थलग किया जाएगा। दरअसल, सरकार के पास इनकी शिकायतें पहुंची थीं। दोनों के प्यार के किस्से सार्वजनिक होने लगे थे और इनके प्रेम संबंध को एकसूत्र में बांधने की कोशिश एक एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी कर चुके थे। लेकिन महिला अधिकारी तैयार नहीं हुईं। क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थीं। इसलिए सरकार ने इन्हें अलग करने के लिए तबादला फॉर्मूला अपनाया। वहीं एक महिला अफसर को भी उनकी मनमानी का सबक सिखाया गया। अपने बंगले पर 3 दर्जन से अधिक जवानों को पदस्थ करने के मामले में सुर्खियों में आई मैडम को भी दूसरे जिले में भेज दिया गया। इनके अलावा सरकार की कृपा पर राजधानी में वर्षों तक पदस्थ रहे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को भी नर्मदा किनारे भेज दिया गया।

इंजीनियरों को सिखा रहे इंजीनियरिंग

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, 1997 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी जबसे निर्माण करने वाले विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, विभाग का चरित्र ही बदल गया है। आलम यह है कि साहब निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की खुद जांच पड़ताल करने लगे हैं। कभी सड़क खुदवाकर तो कभी किसी बिल्डिंग के कॉलम को फोड़वाकर उसकी गुणवत्ता जांचते हैं। साहब के इस रूप ने विभाग के इंजीनियरों के साथ ही ठेकेदारों को पसोपेश में डाल दिया है। गौरतलब है कि साहब जिस विभाग में पदस्थ हैं, उस विभाग में ठेकेदारों और इंजीनियरों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर खेल होता है। बताया जाता है कि साहब जबसे विभाग में पदस्थ हुए हैं, उनके डर के मारे इंजीनियर घबराए हुए हैं, वहीं ठेकेदार भी परेशान हैं। साहब की कार्यशैली देखकर लोगों का कहना है कि चुनावी साल में साहब की यह सख्ती सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि वर्तमान समय विकास कार्यों का है और सरकार दनादन विकास कार्य करवा रही है। ऐसे में अगर साहब की सख्ती इसी तरह बनी रही तो इंजीनियर और ठेकेदार गुणवत्ता के नाम पर कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि साहब ऐसे में क्या करते हैं। हम यहां बता देना चाहते हैं कि साहब खुद एक इंजीनियर हैं और निर्माण कार्यों की सारी बारीकियों और तकनीक को बखूबी जानते हैं।

मैडम से परेशान मातहत

प्रदेश में कई अफसर ऐसे होते हैं जिनसे उनके मातहत परेशान रहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र के एक जिले के अधिकारी बड़े साहब की मैडम से परेशान हैं। सूत्रों का कहना है कि 2012 बैच के आईएएस अधिकारी की धर्मपत्नी एक एनजीओ चलाती हैं। बताया जा रहा है कि साहब जबसे जिले के कलेक्टर बने हैं, उन्होंने अधिकारियों से कह दिया है कि मैडम का विशेष ध्यान रखा जाए। इस पर पहले तो अफसरों ने हां कह दिया, लेकिन अब वे परेशान रहने लगे हैं। दरअसल, साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि मैडम के एनजीओ को अधिक से अधिक काम दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि अफसरों ने इसके लिए मैडम के एनजीओ को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, लेकिन स्थिति यह है कि मैडम की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही है। वे आए दिन जिले के अधिकारियों को तलब कर लेती हैं और उनसे नियमों को ताक पर रखकर एनजीओ के लिए काम मांगने लगती है। अफसरों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कभी भी उनके ऊपर तलवार लटक सकती है। ऐसे में वे पसोपेश में हैं।

कुनबे में असंतोष

कुलीनों का कुनबा कहे जाने वाली पार्टी में इस समय अंदर ही अंदर अलग-अलग खिचड़ी पक रही है। इसका नजारा गत दिनों उस समय देखने को मिला जब पार्टी के मुखिया ने संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्वालियर-चंबल अंचल से आने वाले एक नेताजी जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, आपा खो गए और कहने लगे कि सरकार में हमारी तनिक भी बखत नहीं है। निगम मंडलों में जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, उसमें हमसे सलाह-मशविरा भी नहीं किया गया है। नेताजी के इस रूप को देखते हुए बैठक में शामिल केंद्र सरकार के एक मंत्री और प्रदेश के एक कद्दावर नेता भी उनके समर्थन में कूद पड़े। अपनी ही सरकार के खिलाफ नेताओं की नाराजगी देखकर पार्टी के मुखिया भी हतप्रभ रह गए। फिर क्या था उन्होंने सत्ता और संगठन के नेताओं को जमकर फटकार लगाई और साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि टीम बनाकर काम करें। दरअसल, यह स्थिति उस प्रदेश की है जहां सत्ता और संगठन का समन्वय अन्य राज्यों में पार्टी के लिए मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए मेरे ऊपर भी दबाव बनाया गया था। लेकिन मैं उस दबाव से झुका नहीं, क्योंकि किसी बेगुनाह को दोषी बनाना हमने उचित नहीं समझा। अगर मैं दबाव में झुक गया होता तो न जाने हमारे साथ क्या-क्या हुआ होता।

● **अमित शाह**

भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वह कृत्रिम है। आप सिर्फ उस भारत से इस भारत आए हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हमें अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। जरूरत नहीं कि हम मन से उसे छोड़ें, हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव बना रहे। हम सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते।

● **मोहन भागवत**

आईपीएल के 16वें संस्करण का पहला मैच हम भले ही हार गए, लेकिन स्टेडियम में जिस तरह का माहौल था, उससे यह साफ हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है। 40 पार होने के बाद भी माही भाई ने जिस तरह के शॉट लगाए, उससे क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण साफ-साफ दिखा। इस आईपीएल में अभी कई नजारे दिखेंगे।

● **रविंद्र जडेजा**

अडानी तो सिर्फ मोहरा हैं। उनकी कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अडानी मात्र 10 फीसदी के कमीशन पर इन कंपनियों को संभाल रहे हैं। इसीलिए सरकार अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है।

● **अरविंद केजरीवाल**

मुझे साउथ इंडस्ट्री में काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि बॉलीवुड की तुलना में ये इंडस्ट्री काफी फेंडली और एक्सेप्टिंग है। साउथ इंडस्ट्री में ज्यादा मौके मिलते हैं। यहां आपको कई तरीके की फिल्में और रोल मिलते हैं, साथ ही यहां वर्क एथिक की बहुत अहमियत है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हों। हालांकि ज्यादातर आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को ज्यादातर लोग अच्छी तरह से जानते समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि साउथ इंडस्ट्री में जल्द ही आपको बड़ा मुकाम मिल जाता है। इसलिए मेरा फोकस साउथ इंडस्ट्री पर अधिक रहता है।

● **काजल अग्रवाल**

वाक्युद्ध

राहुल गांधी को कोर्ट ने जो सजा दी है उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। लेकिन हमें लगता नहीं है कि वे सबक लेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसे नेताओं की फौज है, जो उन्हें पसंद नहीं करती है। इसलिए राहुल गांधी जब भी गलत बयानबाजी करते हैं, पूरी पार्टी उनकी हां में हां मिलाती है। अगर पहले ही उन्हें सचेत करते तो ये नौबत नहीं आती।

● **संबित पात्रा**

जिस तरह राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त की गई है, उसकी टाइमिंग यह दर्शाती है कि भाजपा उनसे किस कदर डरी हुई है। यही डर है कि राहुल गांधी को बेवजह के मामले में दो साल की सजा दिलवाई गई फिर उनकी सदस्यता रद्द की गई। लेकिन इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। भाजपा को हम सबक सिखाएंगे।

● **रणदीप सुरजेवाला**

वाकई! मप्र अजब है गजब है...

वाकई मप्र अजब है, गजब है। इसका ताजा नजारा हाल ही में संपन्न बजट सत्र में सामने आया। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम संसदीय परंपरा के विपरीत जाकर निर्देश देते पाए गए। नियमानुसार किसी भी मामले में अगर अध्यक्ष को लगता है तो वे सरकार को उस पर अमल करने का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन 20 मार्च को एक ध्यानाकर्षण के मामले में अध्यक्ष ने आसंदी से रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने का निर्देश दे डाला। अध्यक्ष के इस निर्देश को सुन संवैधानिक परंपरा के जानने वाले लोग हक्के-बक्के रह गए। कुछ विधायक तो यह कहते सुने गए कि संसदीय परंपरा के संरक्षण की बात करने वाले अध्यक्ष खुद संसदीय परंपरा को भूल गए।

दरअसल, 20 मार्च को भाजपा विधायक शरदेंदु तिवारी, पंचूलाल प्रजापति और कुंवर सिंह टेकाम ने ध्यानाकर्षण के जरिए यह मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नाराजगी जताई थी और आसंदी से हटाने के निर्देश दिए थे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन को आप हटा दें। उन्होंने कहा कि आसंदी से कह रहा हूं, इसे निर्देश मान लें या आग्रह, राज्य सरकार की बदनामी क्यों करवा रहे हैं। इसके बाद मंत्री सारंग ने अध्यक्ष से कहा कि आपने जो निर्देश या आग्रह कहा है उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

दरअसल, 20 मार्च को जब ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई तो ध्यानाकर्षण लगाने वाले विधायकों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया और कहा- इसमें गंभीरता इसलिए है कि उनको अधिकारिता है या नहीं, यह प्रश्न अब गौण हो गया है। प्रश्न यह है, जब उनका पत्र 20.12.2022 को, कार्यपालन यंत्री के यहां से पत्र गया, 3 लाख रुपए के एस्टीमेट के साथ कि आप इन्हें स्वीकृति दें। उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। आगे किस कमेटी को भेजा, कहां भेजा, उसको कोई जानकारी नहीं है। उनसे जाकर कैंसर का इलाज करवा लिया तो कार्योत्तर स्वीकृति का आपका एक नियम है, उस नियम के तहत फिर भेजा। जब मैंने 16 तारीख को आपको पत्र भेजा, यदि आपने मेरा पत्र देखा होगा तो उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि इसी तरह से कई घटनाएं हुई हैं। 3 लाख रुपए की स्वीकृति भेजी गई थी, परंतु अभी तक न तो स्वीकृत किया गया, न ही निरस्ती की कोई सूचना दी गई है। यदि आपने निरस्त किया है तो सूचना कर देना चाहिए था।

उल्टा यह हुआ, आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि समय-समय पर संसद सदस्यों, विधायकों के पत्रों के पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही का निर्धारित अवधि में उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमों में आमंत्रित करने, उनसे प्राप्त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करने, निर्देश पालन करने, संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

आगे यह मार्क किया गया है सुविधा समिति की बैठक 11.10.2021 को, अध्यक्ष द्वारा, सदस्यों के पत्रों के निराकरण होने में विलंब होने पर, विभाग द्वारा, जारी निर्देश का उल्लंघन करने पर, अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुन: निर्देशित किया जाता है, शासन द्वारा जारी निर्देशों को अपने अधीन, जिला कार्यालयों, अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इससे यह तय होगा कि हमारा सामान्य विधायक, सांसद पत्र लिखता है, 15 दिनों के भीतर आपने क्या कार्यवाही की, उसकी जानकारी देना है।

उल्टा उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस को बुलाकर वार्ता की। प्रेसवार्ता लेते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रकरण कार्यालय में 2 फरवरी को प्राप्त हुआ। अगले दिन उसकी मार्किंग की गई, ऐसे प्रकरणों की स्वीकृति के लिए, एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी द्वारा ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिया जाता है। ऐसे किसी भी प्रकरण में कोई हीला-हवाली नहीं की जाती, प्रकरण प्रक्रिया में है। ये नेता की तरह अपना बयान दे रहे हैं और वह भी असत्य कथन कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें 2 फरवरी को पत्र प्राप्त हुआ। तो यह जो रसीद है, आपने शायद रसीन देखी होगी। इसमें 22.12.2022 को आपके डीन कार्यालय की पावती है। 22.12.2022 को आपने पावती दी कि वह पत्र आपको मिल गया। 22.12.2022 से 2 फरवरी तक क्या हुआ? हमने तो यह नहीं लिखा, हमने तो केवल यह लिखा कि आप निर्णय कर दो, स्वीकृत हुआ या जो कुछ करना है कर दो। मेरा आग्रह है कि उनके विरूद्ध तमाम शिकायतें हैं। इसके पूर्व भी अनीता मिश्रा के प्रकरण में मैंने आपको धन्यवाद इसलिए दिया कि आपने त्वरित कार्यवाही की। इसमें मेरा आग्रह है मैं आसंदी से कह रहा हूं आप इसे आग्रह समझ लें या निर्देश समझ लें। आप उस डीन को वहां से हटा लो, आप सरकार की क्यों बदनामी करवा रहे हैं, मेरा केवल इतना कहना है।

● **कुमार राजेंद्र**

पहली बार अध्यक्ष ने दिया निर्देश

जानकारों का कहना है कि मप्र के संसदीय परंपरा में पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष ने किसी अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है। गौतम ने अनियमितताओं की शिकायत पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने के निर्देश दिए। इसके पहले अध्यक्ष गौतम ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी इससे से जुड़े एक मामले में पत्र लिखा था। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश हैं कि विधायकों और सांसदों के पत्रों के बारे में अधिकारियों को कार्रवाई से जुड़े वापसी पत्र देते हुए जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन डीन ने ऐसा नहीं करते हुए एक प्रेस वार्ता की और उसमें नेताओं की तरह बयान जारी किए और जो बयान दिया, वह भी असत्य था। इस संबंध में अध्यक्ष गिरीश गौतम के निर्देश पर मंत्री सारंग ने कहा कि इस बारे में सरकार आगे कार्रवाई करेगी। इसके पहले विधायक तिवारी ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में कहा कि मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के बारे में लगातार सदन में विषय उठ रहा है, इस बारे में कब तक कार्रवाई पूरी होगी।

मप्र में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव अब के चुनावों से अलग होगा। क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच जहां मुख्य घमासान होगा, वहीं दिल्ली, पंजाब के साथ कई राज्यों में करिश्मा दिखा चुकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां इनका गणित बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव जीतने के लिए कमजोर विधायकों का टिकट हर हाल में काटा जाएगा।

भाजपा-कांग्रेस को मिलेगी बड़ी चुनौती

मप्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में जहां दिग्गज नेता गुटबाजी से घिरे हुए हैं। वहीं भाजपा में भी समन्वय का अभाव है। इस बात का खुलासा खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल प्रवास के दौरान किया है। इसलिए बचा हुआ समय दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भरा है। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले सीटों और प्रत्याशियों को लेकर किए जा रहे पार्टियों के अंदरूनी सर्वे बाहर आने लगे हैं। इसी के हवाले से राजनीतिक दलों के जिम्मेदार बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस-भाजपा दोनों ही पार्टियों ने जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने का निर्णय लिया है। दोनों पार्टियों के ऐसे उम्मीदवारों की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, जो वर्तमान में विधायक हैं परंतु उनका प्रदर्शन खराब है। दोनों पार्टियों के प्रभारी नेताओं ने पिछले दौरे में इस बात के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं कि स्वयं के बजाय पहले पार्टी को प्राथमिकता में रखें। विधायक हों या बड़े नेता सभी को पार्टी की बात माननी होगी। टिकट वितरण में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बता दें कि मप्र की 15वीं विधानसभा के मतदान 28 नवंबर 2018 को संपन्न हुए थे। चुनावों के परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आए थे। कांग्रेस ने 15 वर्षों से मप्र की सत्ता पर काबिज भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सदन में सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस ने बसपा, सपा और निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाई। हालांकि विडंबना रही कि अंदरूनी घमासान की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ महज डेढ़ साल ही सत्ता का सुख भोग सके और एक बार फिर भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई।

गौरतलब है कि 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी **राजनीतिक दलों** ने तेज कर दी है। दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप और वादों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा (116) नहीं छू पाई थी। कांग्रेस को 1 करोड़ 55 लाख 95 हजार 153 मत प्राप्त हुए थे। कुल मतों का प्रतिशत 40.9 रहा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने 229 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 114 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली। वहीं भाजपा को 1 करोड़ 65 लाख 42 हजार 980 मत प्राप्त हुए थे। भाजपा को कांग्रेस से एक प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए। कुल मतों का प्रतिशत 41 रहा। भाजपा ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। चुनाव में भाजपा के टिकट पर 109 विधायक बने। इस तरह भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 19 लाख 11 हजार 642 वोट लाई थी। कुल 5 प्रतिशत वोट बसपा को मिले थे। 227 सीटों पर लड़ने वाली बसपा को महज दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी को भी 4 लाख 96 हजार 25 वोट मिले। कुल वोटों का प्रतिशत 1.3 प्रतिशत रहा। सपा ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट जीतने में सफल हो सकी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 22

मंत्रियों से संतुष्ट नहीं कार्यकर्ता

मप्र में भाजपा ने 200 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस मिशन की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी है। लेकिन प्रदेश में निकाली गई विकास यात्रा ने मंत्रियों की सक्रियता और परफॉर्मेंस की पोल खोलकर रख दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है। विकास यात्रा के दौरान मंत्रियों के क्षेत्र में ही सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। खासकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों की शिकायत की है। संघ और संगठन के पास पहुंची शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन-फानन में बैठक बुलाकर मंत्रियों को फीडबैक दिया और हिदायत दी है कि एक माह के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर लें, वरना गाज गिरनी तय है। संघ और संगठन को मिले फीडबैक के अनुसार अधिकतर मंत्रियों के खिलाफ शिकायत यह है कि उन्होंने प्रभार वाले जिलों को उपेक्षित छोड़ दिया है और अपने जिले में केवल अपनों को महत्व दे रहे हैं। संगठन और संघ को मिली शिकायतों के अनुसार मंत्री अपने जिलों के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। भाजपा छोड़ने वालों का कहना है कि वे वर्षों से जिनसे संघर्ष कर रहे थे, वे भाजपा में आ गए।

लाख 18 हजार 230 वोट प्राप्त किए। कुल वोटों का प्रतिशत 5.8 रहा। चार निर्दलीयों को जीत नसीब हुई। इसलिए इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि बहुमत के आंकड़े से अधिक सीटें जीती जाए ताकि मजबूत स्थिति में सरकार बना सकें।

2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा लगातार रणनीति बनाकर काम कर रही है। वहीं पार्टी के रणनीतिकार वर्तमान विधायकों की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा केंद्रीय नेतृत्व और संघ लगातार मंथन और समीक्षा में जुटे हुए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार अभी तक मिले फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी में लगभग 40 प्रतिशत चेहरे बदले जा सकते हैं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 60 प्रतिशत विधायकों को ही टिकट मिलेगा, बाकी सभी नए चेहरे होंगे। जिन चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है वह जीतने वाले ही होंगे। गौरतलब है कि विगत दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी का वास्तविक हाल मालूम करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश को मप्र के विशेष दौरे पर भेजा था। वे चार दिन रहकर सत्ता-संगठन सहित अन्य क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं से मिले और चुनावी फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से भी वन-टू-वन चर्चा की। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने संघ की सर्वे रिपोर्ट भी सभी के सामने रखी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सतीश के पास मप्र से संबंधित कोई प्रभार नहीं है। इसी कारण पार्टी ने उन्हें निष्पक्ष रिपोर्ट पाने के हिसाब से मप्र भेजा था। चार दिनों में उन्होंने भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अलग-अलग बातचीत भी की। बताया जाता है कि उन्होंने वन-टू-वन में खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को फटकार भी लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर परफॉर्मेंस नहीं सुधरा है तो टिकट कटना तय मानिए।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन के शीर्ष पदाधिकारी निरंतर जिलों का दौरा कर जानेंगे कि उनकी पार्टी के मौजूदा मंत्रियों और

विधायकों की क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच छवि कैसी है? इसके साथ ही बूथों के डिजिटलाइजेशन के साथ त्रिदेव (बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट) की वर्किंग और शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच फीडबैक की रिपोर्ट भी तैयार होगी। यदि कोई नेता किसी विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावा करता है और कहता है कि उसे 51 प्रतिशत से अधिक वोट मिलेंगे ही, तब भी परीक्षण होगा। पार्टी जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल कराएगी। ये काम मैदानी पदाधिकारी करेंगे। पार्टी के बूथ और मंडल स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। वहीं, दावा करने वाले नेता की मजबूती संगठन को बताएंगे। वे बताएंगे कि संबंधित दावेदार की कैसी साख है और वह चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पा सकते हैं। इसमें बूथ कमेटियां ग्रामीणों से रेंडम फीडबैक लेंगी। पार्टी के पास अब तक प्रारंभिक सर्वे में जो जमीनी ब्यौरा सामने आया है, उसके आधार पर पार्टी कई विधायकों का टिकट तो काटेगी ही, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे नेता होंगे, जो तीन बार से ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तीन बार के विधायकों को लेकर सर्वे में नकारात्मक फीडबैक मिला है।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सभी तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले लगभग 35 प्रतिशत विधायकों का टिकट खतरे में है। कांग्रेस ने जिन विधायकों के प्रदर्शन के बारे में बात की है, उनमें से ज्यादातर नए विधायक हैं। कुछ क्षेत्रों में पुराने नेता और विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस को प्रदर्शन की जानकारी सर्वे और **गोपनीय रिपोर्ट** से प्राप्त हुई हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए 230 सीटों में से कांग्रेस उन 70 सीटों पर फोकस करेगी, जहां लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता इन सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यहां प्रत्याशी की पहले घोषणा भी की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगातार हारने वाली सीटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की है। इन सीटों पर वरिष्ठ नेता अधिक ध्यान देंगे। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मंडलम, सेक्टर के पदाधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठकों में कार्यकर्ताओं से संभावित प्रत्याशी को लेकर भी राय ली जाएगी।

● **सुनील सिंह**

कांग्रेसी दिग्गजों में रार

2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कमलनाथ सत्ता में वापसी की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे कांग्रेस के नेताओं में रार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के दिग्गज नेताओं में इस कदर रार बढ़ गई है जिससे लगता है कि कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। प्रदेश में एक तरफ चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है, वहीं कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। कभी वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बीच मतभेद सामने आते हैं, तो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और नाथ के बीच दूरियां दिखाई देती हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रश्न उठते हैं तो कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन के बाद कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर बात उठती है। जीतू पटवारी जहां अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष पदनाम का उपयोग कर रहे हैं। जबकि, नई कार्यकारिणी में इसका उल्लेख नहीं है। उधर, पटवारी को विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित करने के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो दिया गया पर जिस तरह आक्रामक होकर पार्टी को दबाव बनाना था, वह नहीं बनाया गया।

क्या आप मार सकेगी सेंध?

कुछ ही महीनों में मप्र में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर रहती है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। कांग्रेस ने कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया और अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और सत्ता की कुंजी एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आ गई। दिलचस्प ये है कि भाजपा कांग्रेस की इस सीधी टक्कर में आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुट गई है। यहां भी उसका चुनावी दंगल गुजरात की तर्ज पर सजता हुआ दिख रहा है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के बाद आम आदमी पार्टी का काफिला मप्र जा पहुंचा है।

मप्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और भाजपा ही अदल-बदलकर सत्ता में आती हैं। ऐसे में लोगों को लगता है अब चुनावी रण में आम आदमी पार्टी की एंट्री से जनता को एक नया विकल्प मिल गया है। बीते कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सुर्खियों में है। मामला उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ा है। दरअसल, दिल्ली की नई शराब नीति में हुए घोटाले पर बवाल हो रहा है। भाजपा केजरीवाल और आप पर निशाना साध रही है। वहीं, आप इसे दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर हमला बता रही है। इसके साथ ही आप नेता दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है? क्या ये दिल्ली-पंजाब की तरह अन्य राज्यों से भी कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश है? क्या भाजपा के कांग्रेस मुक्त अभियान को आप आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। अभी लोकसभा में उसके 53, राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। देशभर में कांग्रेस के 692 विधायक और 43 एमएलसी हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी अपने जन्म के बाद महज 10 साल में दो राज्यों में सरकार बना चुकी है। कई राज्यों में उसकी मजबूत दावेदारी है।

अभी आप के 10 राज्यसभा सांसद हैं और 156 विधायक हैं। राजनीतिक जानकर कहते हैं, जहां भी कांग्रेस सत्ता में रही है, वहां आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी है। दिल्ली, पंजाब इसके उदाहरण हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मप्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से होती है। यहां भी आम आदमी पार्टी ने खुद का तेजी से विस्तार करना शुरू किया। उत्तराखंड में आप को सफलता नहीं मिली, लेकिन पूरे चुनाव में आप की चर्चा खूब रही। अब केजरीवाल की नजर हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर थी। यहां भी आप ने कांग्रेस को किनारे करके मुख्य लड़ाई आप और भाजपा के बीच में करने की कोशिश शुरू कर दी थी। देखा जाए तो तीन बिंदु ऐसे हैं कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी का बढ़ना कांग्रेस के लिए खत्म होने का संकेत है। पहला, पंजाब में भाजपा की स्थिति पहले भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहां की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी कुछ खास नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ही यहां कांग्रेस का विकल्प बनी।

वह भी ऐसी कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ ही हो गई। इस बार चुनाव में पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 77 से 18 पर आकर सिमट गई। भाजपा को दो और शिरोमणि अकाली दल को **तीन सीटों** पर जीत मिली। 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 20 सीट पर जीत मिली थी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को साफ कर दिया। दूसरा, गोवा-मप्र में भी आम आदमी पार्टी मजबूत होती दिखी। गोवा में पहली बार आम आदमी पार्टी के दो विधायक चुनाव जीते। इनमें एक सीट पर 2017 में कांग्रेस जबकि दूसरे पर एनसीपी की जीत हुई थी। मतलब दोनों सीटों पर गैर भाजपाई दलों को नुकसान हुआ। गोवा की करीब 25 ऐसी सीटें थीं, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट काटा। इसका फायदा भाजपा को मिल गया।

● **अरविंद नारद**

सिंगरौली में दिखा दम

वहीं, मप्र की बात करें तो यहां पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। सिंगरौली में आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने भाजपा के उम्मीदवार को हराया। रानी भाजपा की नेता रह चुकी हैं। हालांकि, जब ओवरऑल आंकड़ों को देखते हैं तो यहां भी आम आदमी पार्टी ने करीब 60 से ज्यादा वार्डों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। बुरहानपुर, खंडवा और उज्जैन में मेयर सीट पर भाजपा की जीत हुई। इन तीनों सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई। बुरहानपुर में एआईएमआईएम प्रत्याशी को 10 हजार से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह उज्जैन में भाजपा उम्मीदवार केवल 736 वोटों से जीती। अब यह माना जा रहा है कि जहां कांग्रेस-भाजपा की लड़ाई हो, वहीं आप की एंट्री होती है। आमतौर पर कई राज्यों में कांग्रेस को आसानी से मुस्लिम वोटर्स का साथ मिल जाता है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल इसी को तोड़ने में जुटे हैं। जहां-जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है, वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। ऐसी स्थिति में भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा जाता है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस को लड़ाई से ही गायब कर दिया जाता है। अब केजरीवाल 2023 के मप्र के चुनाव में दल-बल के साथ उतर चुके है। गत दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में आयोजित एक रैली में चुनावी बिगुल फूंकते हुए ये घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब की तर्ज पर ही मप्र में अगर उनकी सरकार आई तो बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं को मुफ्त कर दिया जाएगा।

आयुष्मान का फिर से ऑडिट

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों के उपचार में गड़बड़ी करने वाले इंदौर के सात अस्पतालों का योजना में संबद्ध होने के दिन से ऑडिट किया जाएगा। इसमें उपचारित मरीजों से भी पूछताछ की जाएगी। सभी मरीजों की केस शीट निकालकर पड़ताल की जाएगी। जांच में यह देखा जाएगा कि वास्तव में मरीज उपचार के लिए भर्ती हुआ था या अस्पताल ने फर्जी तरीके से भर्ती दिखाकर दावा राशि ले ली। गड़बड़ी मिली तो वसूली करने के साथ ही एफआईआर समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योजना का संचालन करने वाले राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसी माह इंदौर के सात अस्पतालों की जांच की थी, जिसमें कई अनियमितताएं मिली थीं। कुछ अस्पतालों ने भर्ती के लिए जितने मरीजों का पंजीयन पोर्टल पर दिखाया था, उतने मरीज नहीं मिले। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अस्पतालों की बकाया दावा राशि भी रोक दी गई है।

ऑडिट के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों से पूछताछ होगी। मरीज की जो बीमारी केस शीट में बताई गई है उसके लिए भर्ती करने की जरूरत थी या नहीं। बिल बढ़ाने के लिए मरीज को बेवजह गहन चिकित्सा इकाई में तो नहीं रखा गया। भर्ती के दौरान जो फोटो पोर्टल पर अपलोड किया गया, वह ओपीडी या किसी शिविर का तो नहीं है। राज्य **स्वास्थ्य प्राधिकरण** ने जिन सात अस्पतालों की जांच की है, उनमें अभी सिर्फ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की आयुष्मान भारत योजना से संबद्धता निलंबित की गई है। बाकी अस्पतालों से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद इन अस्पतालों की संबद्धता निलंबित या समाप्त करने का निर्णय हो सकता है। गड़बड़ी से जितनी कमाई की गई है, उसका तीन से पांच गुना तक अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रदेश में व्यापक स्तर पर निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना के नाम पर आयुष्मान घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध मप्र के 620 निजी अस्पतालों में से 120 ने 200 करोड़ का घोटाला किया है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित नामी-गिरामी अस्पताल शामिल हैं। आयुष्मान घोटाला सामने आने के बाद भोपाल और जबलपुर के कुछ अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात का खुलासा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार कराई गई जांच रिपोर्ट में किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग अब इन अस्पतालों पर अर्थदंड लगाकर वसूली कर रहा है। विभाग द्वारा 15 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। विभाग द्वारा अब तक कुल 104 अस्पतालों को नोटिस जारी किया जा चुका है। भोपाल के वैष्णव मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने के साथ ही अस्पताल में आयुष्मान की संबद्धता और पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 620 निजी अस्पतालों को बीते तीन साल में 1048 करोड़ 98 लाख का भुगतान किया गया। भुगतान में अधिकांश निजी अस्पतालों में वित्तीय फर्जीवाड़ा और ज्यादा बिलिंग की शिकायतें मिली हैं। गौरतलब है कि 2019-20 में 141 करोड़ 72 लाख 55 हजार 807, 2020-21 में 265 करोड़ 14 लाख 56 हजार 297 और 2021-22 में 642 करोड़ 11 लाख 377 रुपए का भुगतान किया गया।

मप्र में आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले सामने आने के बाद भी अधिकारी और विभागीय मंत्री गंभीर नहीं हैं। सितंबर के बाद से अस्पतालों की औचक जांच ही नहीं की गई है। जून और सितंबर में आकस्मिक निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी यह स्थिति है। अस्पताल जो दावा करते हैं उसे ही सही मानकर भुगतान कर दिया जाता है। इस बारे में अधिकारियों का तर्क है कि योजना में कार्यरत डॉक्टरों का स्थानांतरण हो गया। नया स्टाफ मिला पर उन्हें योजना को समझने में समय लगा। इसके अलावा पहले जो जांचें हुई थीं, उनमें कार्रवाई करने में अमला जुट गया। इस कारण नई जांचें शुरू नहीं हो पाईं। जून और सितंबर में भी योजना में संबद्ध 550 से ज्यादा अस्पतालों में 130 की ही जांच हो पाई। इसके पहले योजना की शुरुआत से 2021 के अंत तक सिर्फ 49 अस्पतालों की ही औचक जांच कराई गई थी। बता दें कि जांच में यह सामने आ जाता है कि अस्पताल जो बीमारी बताकर मरीज का इलाज कर रहा है, वास्तविक में वह है या नहीं। सामान्य वार्ड में रखे जा सकने वाले मरीज को आईसीयू में तो नहीं रखा है। वास्तविक में वह मरीज भर्ती भी है या नहीं। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में इस योजना में बीमित प्रति व्यक्ति 1100 रुपए प्रीमियम लगता है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40 प्रतिशत राज्य सरकार लगाती है। योजना में गड़बड़ी की निगरानी केंद्रीय स्तर से भी की जाती है। इसके बाद भी यह स्थिति है।

● **बृजेश साहू**

अन्य अस्पतालों पर भी जल्द होगी कार्रवाई

आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी मिलने पर योजना का संचालन करने वाले राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत संबद्धता निलंबित कर दी है। निलंबन अवधि में अस्पताल योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार नहीं कर पाएगा। इंडेक्स के अलावा इंदौर के छह अन्य अस्पतालों में प्राधिकरण की टीम ने जांच की थी। इन अस्पतालों में भी अनियमितताएं मिली थीं। यहां से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद इनकी संबद्धता खत्म करने का निर्णय भी हो सकता है। जिन अस्पतालों के दस्तावेजों में धोखाधड़ी साबित होगी, उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आनलाइन पोर्टल के अनुसार इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में लगभग 500 मरीज पंजीकृत थे, जबकि जांच दल को मौके पर 76 मरीज ही मिले। बाकी मरीजों के बारे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अनावश्यक रूप से ऐसे मरीज गहन चिकित्सा इकाई में उपचाररत पाए गए, जिन्हें भर्ती करने और गहन चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं थी। बिना जरूरत मरीजों को अधिक समय तक भर्ती रखा गया। वहीं सामान्य बीमारी के मरीजों को भी भर्ती किया गया।

मप्र में बिछेगा सड़कों-पुलों का जाल

मप्र में इस समय चुनावी मौसम धीरे-धीरे गर्मा रहा है। इस चुनावी साल में सरकार की प्राथमिकता विकास है। इसके लिए सरकार ने लोक निर्माण विभाग को बड़ा बजट दिया है। बजट में सड़क, पुल-पुलिया के साथ ही अन्य निर्माण कार्यों के लिए कैटेगिरी बनाई गई है। मप्र में 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। कुल 14 रोपवे जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी, पातालकोट के रोपवे शामिल हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4 हजार किमी सड़क, 197 पुल, 5 हजार किमी सड़क नवीनीकरण और 280 किमी सड़क उन्नयन का काम किया जाना है। इसलिए 10,182 करोड़ रुपए सड़क, पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रस्तावित हैं।

लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर मप्र के लक्ष्य की पूर्ति तथा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए पूंजीगत व्यय को लगभग 20 प्रतिशत रखा जाना राज्य शासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधोसरंचना विकास के लिए 9,408 करोड़ रुपए के प्रावधान से नवीन सड़कों, पुलों के निर्माण के साथ वर्तमान सड़कों के संधारण के लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए 1,020 करोड़ रुपए, सुदृढ़ीकरण के लिए 1,000 करोड़, वृहद पुलों के निर्माण के लिए 485 करोड़ और मप्र सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 421 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के बजट में 56 हजार 256 करोड़ रुपए का प्रावधान अधोसंरचना के लिए निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए संकल्प लिया है। मप्र इसमें 550 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। अधोसंरचना और जनकल्याण के साथ ही जीवन मूल्यों और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के पश्चात अब ओरछा में रामराज लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक, सागर में संत रविदास जी का स्मारक और सलकनपुर में देवी महालोक के विकास का संकल्प है। प्रदेश में अधोसंरचना से रोजगार बढ़ेंगे। चीता प्रोजेक्ट भी पर्यटन विकास में मददगार होगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे और अटल एक्सप्रेस-वे विकास को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश में राजस्व संग्रहण तेजी से बढ़ा है। अपने साधनों से भी राशि जुटा रहे हैं।

एफ टाईप से उच्च श्रेणी के लिए शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 1,20,00,00 हजार, केंद्रीय सड़क निधि के लिए 8,00,00,00 हजार, क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए 6,40,000 हजार, एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 60,00,00 हजार, विधानसभा तथा विधायक विश्राम गृह के लिए 1,00,00 हजार, प्रकाश तरण पुष्कर की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए 2,89,59 हजार, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए 25,00,00 हजार, एनडीबी से वित्त पोषण (पुल निर्माण) के लिए 5,00,00,00 हजार, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 10,20,44,02 हजार, भू-अर्जन हेतु मुआवजे के लिए 52,90,00 हजार, लोक निर्माण कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए 2,00,00 हजार, विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग एवं उप संभाग के स्थापना व्यय के लिए 4,46,98 हजार, सतपुड़ा-विंध्याचल में अमले के स्थापना व्यय के लिए 3,22,33 हजार, वृहद पुलों के निर्माण के लिए 4,85,00,00 हजार, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 10,00,00,00 हजार, हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 30,01 हजार, मुख्य जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 5,00,00,00 हजार, पुलों के निर्माण (नाबार्ड) के लिए 50,00,00 हजार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण (नाबार्ड) के लिए 50,00,00 हजार, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अनुरक्षण कार्य के लिए 4,00,00 हजार, राजधानी परियोजना प्रशासन के अधीन गैस त्रासदी राहत चिकित्सालयों के आवास गृहों के अनुरक्षण के लिए 1,20,00 हजार, बीओटी मार्गों के विकास व पर्यवेक्षण के लिए 12,00,00 हजार, शासकीय आवास गृहों के अनुरक्षण के लिए 2,85,00 हजार, मप्र सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण के लिए 50,00,03 हजार, विधायक विश्राम गृहों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए 7,00,00 हजार, मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 7,00,00,00 हजार, मंत्रालय भवन का निर्माण 1,50,00 हजार, नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण के लिए 1,00,00 हजार, भोपाल में स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 5,00,00 हजार, शहरी एवं नगरीय मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 6,00,00 हजार, नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 7,50,00,00 हजार का बजट रखा है।

● **जितेंद्र तिवारी**

हवा में बायपास

लोक निर्माण विभाग अब मुंबई के सी लिंक जैसा राजधानी भोपाल सहित अन्य शहरों में रिंग रोड बनाएगा। भोपाल में बड़े तालाब से लेकर खानूगांव तक 8 लेन आर्च ब्रिज बनाएगा, जो बैरागढ़ पुल से जुड़ेगा। बागमुगालिया मार्ग से एम्स तक मिसिंग लिंक मार्ग, कोलार रोड से हिनोतिया आलम मार्ग बनाया जाएगा। सागर जिले के छुल्ला बेरखेड़ी मार्ग से कोपरा नदी पर पुल निर्माण, मंडला लोहागर मार्ग पर कैथ नदी पर पुल निर्माण किया जाएगा। पन्ना, कटनी में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। शिवपुरी नगर परिषद करेरा रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। कटनी-शहडोल एनएच-78 मार्ग से जोड़ने के लिए रिंग रोड बनाया जाएगा। बजट में वैसे तो सभी जिलों में सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण के लिए बजट दिया गया है, लेकिन सबसे अधिक सीहोर, सागर, रीवा, मंदसौर आदि जिलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

मप्र की नदियों का घुट रहा दम

मप्र की नदियों का दम घुट रहा है। इन नदियों में इतना कचरा बहाया जा रहा है कि उसे साफ करने में नदियां हांफ रही हैं। उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। इनका पानी नहाना तो दूर आचमन लायक भी नहीं बचा है। यह नदियां जैविक प्रदूषण से छटपटा रही हैं। इस कारण मप्र में कई नदियों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। जीवनदायिनी नर्मदा आज देश की बड़ी नदियों में प्रदूषण के मामले में छठवें नंबर पर पहुंच गई है। 18 नदियों का पानी आचमन करने लायक भी नहीं बचा है। ये स्थिति तब है, जब हमारे राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। सरकार और जनता अब भी न चेते तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब यही आने वाली पीढ़ी को जवाब तक न दे पाएंगे। इसलिए अब कार्रवाई का वक्त है।

नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के तहत नदियों के पानी की नियमित जांच की जाती है। पानी की परख बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) के मानक के आधार पर की जाती है। पानी में अगर जैविक कचरा ज्यादा हो तो उसे नष्ट करने के लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है। यानी बीओडी जितना ज्यादा, प्रदूषण भी उतना ज्यादा। पीने के पानी में बीओडी अधिकतम दो या उससे कम होना चाहिए। नहाने के पानी में यह 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नदी में बीओडी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सीवेज का प्रवाह है। मल-मूत्र के अलावा मानव शव, पशु शव, फूल-पत्तियों का प्रवाह नदी के संतुलन को बिगाड़ता है। इन्हें नष्ट करने में भारी मात्रा में ऑक्सीजन खर्च होती है। इससे नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। नदियों के किनारे बसे बड़े शहरों में ज्यादातर में या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं, या फिर पूरी तरह पानी साफ नहीं कर रहे हैं। यह सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है।

मप्र में प्रदूषण से नदियों का दम घुट रहा है। जीवनदायिनी नर्मदा के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगह पानी पीने लायक तक नहीं है। कई नदियों में प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि उनका पानी छूने योग्य भी नहीं है। इससे जलीय विविधता खत्म हो रही है। जीव-जंतु दम तोड़ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि नदियों के संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। जल गुणवत्ता की स्थिति बदतर हुई है। नर्मदा नदी में रोजाना करोड़ों लीटर गंदगी सीवेज के जरिए पानी में मिल रही है। नर्मदा के किनारे बसे सभी शहर इसमें प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं। आलम यह है कि नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से ही दूषित है। इसके बाद मंडला, डिंडौरी में भी सीधे सीवेज का पानी पहुंच रहा है। उसकी सहायक नदियां भी गंदगी उड़ेल रही हैं। इसके बाद का प्रवाह और भी चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। केंद्रीय और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में 18 नदियों का पानी अत्यधिक प्रदूषित पाया गया है, जो छूने लायक भी नहीं है। इनमें चंबल, बेतवा, हिरन, जोहिला, मंदाकिनी, सोन, बिछिया, कलियासोत, कान्ह, माही, वर्धा, नेवज, पार्वती, तापी और कुंदा नदी शामिल हैं। इन नदियों के कई के प्रवाह क्षेत्र में बीओडी (बॉयोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और जलीय जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया है।

इधर, केंद्र के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा कछार की नदियां शामिल हैं। मप्र के आधे हिस्से की नदियां या तो सीधे गंगा में मिलती हैं या उसकी सहायक नदियों से होकर गंदगी वहां पहुंच रही है। फिर भी केंद्र ने नमामि गंगे में यहां की नदियों के लिए कुछ नहीं दिया है। केंद्र ने सर्वाधिक **प्रदूषित देश** की 13 नदियों में नर्मदा को शामिल किया है। इस मामले में नर्मदा देश में छठवें नंबर पर है। 19 हजार करोड़ की डीपीआर में सबसे अधिक यमुना के 5200 वर्ग किलोमीटर के प्रदूषित क्षेत्र का उपचार किया जाएगा। नर्मदा के 800 वर्ग किलोमीटर हिस्से का उपचार किया जाना है। इसके तहत गाद निकालने से लेकर पौधरोपण और बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित करने का प्रस्ताव है। इधर, धार जिले के खलघाट में 1.7 एमएलडी सीवेज रोजाना नर्मदा में मिल रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया है, लेकिन यह अभी निर्माण के चरण में ही हैं। अब राज्य सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तर्ज पर नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत 1042 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी के संरक्षण, प्रदूषण निवारण और परिक्रमा पथ के लिए कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत जबलपुर से किए जाने की घोषणा की गई है। पहले चरण में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है।

● **प्रवीण सक्सेना**

नालों से दूषित हो रही नदियां

नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण ने जलीय जीवों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। मंडला में छोटे-बड़े 18 नालों का गंदा पानी नदी को दूषित कर रहा है। जिले की बंजर, सुरपन, बुढ़नेर नदी में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। श्योपुर में चार नदियों का अस्तित्व खतरे में हैं। जिले के 3800 वर्ग किलोमीटर में विस्तार लिए जंगल सहित 6607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला श्योपुर जिला पानी के लिए छह नदियों पर निर्भर है। अंधाधुंध दोहन और अवैध उत्खनन ने इन छह नदियों में से चार के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया है। पार्वती और चंबल अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। इन नदियों में मौजूद जलीय जीवों का जीवन खतरे में है। सीप नदी को नगर पालिका ने गंदा कर दिया है। इसमें 18 गंदे नाले मिलते हैं। इंदौर में कान्ह और सरस्वती नदी प्रदूषित हैं। इनके शुद्धिकरण पर 15 वर्ष में 1157 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब 511 करोड़ और खर्च करने का प्लान है। यह राशि खर्च होने के बाद नदियां साफ होंगी या नहीं इस पर संशय है। नर्मदा नदी में मिलने वाली गंदगी को रोकने 2017 में 173 करोड़ रुपए की सीवरेज प्रोजेक्ट नेटवर्किंग योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक इसका काम नहीं हो सका है। यह प्लांट आदमगढ़ में प्रस्तावित है। नगरपालिका ने माचना नदी को प्रदूषित होने से बचाने अंडर ब्रिज के पास नाले में पाइप डालकर जालियां लगाई थीं, ताकि पानी के साथ आने वाली गंदगी को नदी में जाने से रोका जा सके, लेकिन जालियां टूट गईं। अजनाल नदी हरदा की जीवन रेखा है। शुरू से ही इसमें आसपास के पांच कच्चे और पक्के नालों का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे यह प्रदूषित हो रही है। आगे इसी नदी का पानी नर्मदा में भी मिलता है।

लोकसभा और विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश और प्रदेश में लोकतंत्र का मंदिर माननीयों के हंगामे का केंद्र बनकर रह गया है। मप्र में तो स्थिति यह है कि 15वीं विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चल पाया है। हाल ही में आयोजित बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र का तय अवधि से 6 दिन पहले ही समापन हो गया। हालांकि सारे सरकारी काम निपटा लिए गए, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई।

6 दिन पहले समाप्त हुआ बजट सत्र

मप्र विधानसभा का बजट सत्र 29 दिन का था। लेकिन यह सत्र 6 दिन पहले ही समाप्त हो गया। पिछले 4 साल के दौरान विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चला है। इसको लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं पर जनहित से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। गौरतलब है कि 2022 में लोकसभा वर्ष में 100 दिन, बड़ी विधानसभा 90 से 75 दिन और छोटी विधानसभा में सदन की कार्यवाही 60 दिन चलाने की बात कही गई थी। संसद हो या विधानसभा, जनता के मुद्दों पर चर्चा, सवाल-जवाब और फिर निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेंड मप्र विधानसभा में दिखाई दिया।

मप्र में 15वीं विधानसभा के 4 साल से अधिक समय पूरे हो चुके हैं। लेकिन विडंबना यह देखिए कि इन दिनों में विधानसभा का सत्र 73 दिन भी नहीं चला। 15वीं विधानसभा में इस बजट सत्र को मिलाकर 120 दिन बैठकें तय की गई थीं, लेकिन 73 दिन ही हुईं। यह आंकड़ा बता रहा है कि चर्चा का समय लगातार घट रहा है। लोकतंत्र के लिए इसे कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। 15वीं विधानसभा में तीन सत्रों को छोड़कर 4 साल में अन्य कोई भी सत्र (बजट, मानसून और शीतकालीन) अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर सका। यहां तक कि बजट सत्र की बैठकें भी समय से पहले ही समाप्त हो गईं। जबकि यह सबसे लंबा होने की परंपरा रही है।

दरअसल, सत्तापक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। पिछले मानसून सत्र में भी यही स्थिति बनी थी। इससे अध्यक्ष व्यथित भी नजर आए पर सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है। विपक्ष लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करना चाहता है पर सत्तापक्ष हंगामा करने लगता है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। हंगामा करना ही इनका मकसद रहता है। जबकि, सदन का मंच हमें जनहित पर चर्चा करने के लिए दिया है और सबकी प्रक्रिया निर्धारित है। बड़ी तैयारी के साथ विधायक विधानसभा सत्र के लिए प्रश्न लगाते हैं। एक घंटे के प्रश्नकाल में 25 प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है। जिन सदस्यों के प्रश्न इसमें शामिल होते हैं वे सदन में सरकार का उत्तर चाहते हैं और पूरक प्रश्न भी करते हैं पर हंगामे के कारण प्रश्नकाल ही पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन भी हो रहा है। अपनी बात रखने का उन्हें मौका भी कम मिल रहा है। इसे लेकर विधायक आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं। विधेयकों को लेकर भी स्थिति अलग नहीं है। इस दौरान अधिकतर विधेयक हंगामे के बीच ध्वनिमत से चंद मिनटों में पारित हो जाते हैं।

इस साल मप्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दृष्टि से विधानसभा का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस इसमें भी सरकार

स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज

मप्र विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बजट सत्र का तय अवधि से 6 दिन पहले ही समापन हो गया है। सदन में बजट भी पारित हो गया। इससे पहले स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। लंच ब्रेक से पहले स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 मार्च की तारीख दी। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे नियम विरूद्ध बताते हुए आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा स्पीकर से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा- अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। मैं भाजपा की ओर से प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाए। पूर्व अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी कहा कि संकल्प नियमों के विपरीत हो, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। पहले दिन और अंतिम दिन चर्चा नहीं हो सकती। ऐसे में स्पीकर ने भाजपा के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से हां/ना कराई। भाजपा का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। बजट भी पारित हुआ। कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले महू की घटना को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया।

को घेरने में सफल नहीं रही। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी। ऐसा एक भी मुद्दा नहीं उठा, जिसमें सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा हो। पार्टी में बिखराव भी नजर आया। विधायक जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन किसी ने उनकी बहाली को लेकर पहल नहीं की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन उसे लेकर दबाव बनाने में भी विपक्ष विफल रहा। जब प्रस्ताव पर निर्णय होने थे तो कांग्रेस के कुछ विधायक ही सदन में उपस्थित थे। बजट सत्र लंबा रहा, इसमें 12 बैठकें हुईं, पर कांग्रेस केवल हंगामा करती रही। कांग्रेस न तो किसानों पर बेमौसम आई आपदा के मुद्दे पर चर्चा कराने में सफल हो सकी, न ही 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार को घेर पाई। पीसी शर्मा सहित अन्य विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव अवश्य दिए, पर इसे स्वीकार करने को लेकर दल दबाव नहीं बना पाया।

आदिवासियों पर अत्याचार का मामला भी नारेबाजी तक ही सिमटकर रह गया। जीतू पटवारी को सत्तापक्ष ने प्रस्ताव लाकर पूरे सत्र के लिए निलंबित करा दिया, पर उनकी बहाली को लेकर दल की ओर से कोई पहल ही नहीं की गई। पटवारी ने जिन मुद्दों को उठाया था, उन पर कोई बात तक नहीं हुई। इससे संदेश गया कि पार्टी में बिखराव भी है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा विपक्ष आज तक नहीं देखा, जिसका विधायक निलंबित हो गया हो, उसकी बहाली को लेकर किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। उधर, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी मुद्दे उठाए। सरकार जब जवाब देने को तैयार ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। विपक्ष के पास बहिर्गमन कर विरोध जताने का हथियार होता है, उसका उपयोग किया गया। बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने प्रभावी तरीके से बात रखी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी पूरी दमदारी से हमने पक्ष रखा है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने भी कहा कि हमने विपक्ष की भूमिका निभाई

है। सरकार ने वित्तीय स्थिति को लेकर बार-बार पूछने के बाद भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया। अब जनता की अदालत में जवाब मांगा जाएगा।

उधर, देखा जाए तो सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने कांग्रेस से अधिक अपनी सरकार पर वार किए। इस बार सबसे ज्यादा परेशानी भाजपा को अपने ही विधायकों से झेलनी पड़ी। सदन में सरकार को जितना कांग्रेस विधायकों ने नहीं घेरा, उससे कड़े शब्दों के साथ इस बार भाजपा के विधायकों ने अपने मंत्रियों और नौकरशाही पर सवाल उठाकर सरकार की फजीहत करा दी। भाजपा के किसी विधायक ने कहा कि मैं निरीह हूं, तो किसी ने कहा, मेरी जगह कांग्रेस विधायक को जांच समिति में शामिल कर दिया जाए, ताकि जांच निष्पक्ष होगी, तो किसी को कहना पड़ा चुनावी साल है जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे। वहीं आसंदी तक ने एक मंत्री को कह दिया कि अधिकारी पर कार्रवाई कर दीजिए, क्यों सरकार की छवि खराब कर रहे हैं।

भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सहकारी बैंक में गबन का मामला उठाया। उन्होंने कहा, जिन बैंकों में लोगों के लाखों रुपए जमा हैं। उन्हें हजार रुपए दिए जा रहे हैं। बैंक ने किसानों का भुगतान करने में हाथ खड़े कर दिए। इस पर सहकारिता मंत्री ने कहा- अपेक्स बैंक स्वतंत्र बॉडी है। बैंक की ओर भुगतान को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर भुगतान कराया जाएगा। विधायक रघुवंशी ने कहा कि चुनावी साल है, हम लोगों के घर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे।

भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम एमडी के खिलाफ शिकायतों का मामला उठाया। बिसेन ने कहा, 11 शिकायतों को बिना जांच किए ही बंद कर दिया गया, क्या मंत्री फिर से इस मामले की जांच कराएंगे? इस पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जवाब दिया कि इस मामले की जांच समिति के जरिए जांच कराई जाएगी, फिलहाल जांच की जाएगी। बिसेन ने कहा कि 4 साल बाद पहली बार सवाल पूछा गया है, इसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। मंत्री जांच कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी कराएं। भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने प्रदेशभर में कुत्तों के हमले की घटनाओं का मामला उठाया। इस पर मंत्री ओपीएस भदोरिया ने कहा कि बर्थ कंट्रोल के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेशभर में यह अभियान चल रहा है। सिसौदिया ने कहा कि लोगों की सुरक्षा का विषय है। सरकार और निजी अस्पतालों में लगने वाले रेबीज के इंजेक्शन से पता लगाया जा सकता है कि कितने मामले सामने आ रहे हैं।

● **कुमार विनोद**

सवाल पूछकर सदन में गैरहाजिर रहे कई विधायक

मप्र विधानसभा का सत्र कुछ साल पूर्व तक देश की अन्य विधानसभाओं के लिए अनुकरणीय था। लेकिन अब यहां के विधायक भी विधानसभा की गरिमा का मान नहीं रख पा रहे हैं। सदन में हो-हल्ला, बात-बात पर हंगामा तो आम बात हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब माननीय सवाल पूछकर सदन से गायब होने के आदी हो गए हैं। दिलचस्प ये है कि विधानसभा में बीते 3 वर्ष में 48 विधायक सवाल पूछकर गैरहाजिर हुए। सदन में विधायकों का नाम पुकारा जाता रहा, लेकिन वे नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा में प्रथम बार के विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सदन में प्रथम बार के विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया था, लेकिन आधा दर्जन विधायक अपने सवाल पूछने के समय ही सदन से गायब रहे। गौरतलब है कि विधानसभा में प्रश्नकाल अहम अंग है। इसीलिए इसे संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहले स्थान दिया गया है। प्रश्नों के खर्च का आंकलन प्रश्न के स्वभाव के अनुसार होता है। इसमें प्रश्नों का उत्तर तहसील से बुलवाना, जिला, संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित करना शामिल होता है।

मप्र में किंगमेकर बनेंगे किसान

170 सीटों पर असर

मप्र में 230 विधानसभा सीटों में से 170 सीटें ऐसी हैं जहां किसान वोट निर्णायक भूमिका में हैं। प्रदेश की 80 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है। 20 जिलों की 51 तहसीलों में और बेमौसम की बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब बारिश और ओलावृष्टि के जरिए किसानों के बीच पहुंचने की तैयारी में है तो वहीं भाजपा सरकार जल्द से जल्द सर्वे पूरा कर किसानों को राहत राशि वितरण कर किसान हितैषी बताने की तैयारी में है। मतलब साफ है विधानसभा चुनाव से पहले जो दल किसानों का भरोसा जीतने में सफल होगा सत्ता की चाभी उसी पार्टी के हाथ में होगी।

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 और कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर काम कर रही हैं। दोनों पार्टियों के जिम्मेदार अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि मप्र में उसी की सरकार बनेगी जिसका साथ किसान देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अन्नदाता के मन की बात को परखने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के बहाने किसानों में पैठ बनाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वे बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का आंकलन करने के लिए किसानों के बीच जाएं। खेतों में जाकर फसलों के नुकसान का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपें। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि प्रदेश में किसानों की आय घट रही है। किसानों की आय दोगुना करने के दावे फेल साबित हुए। किसानों के बिजली बिल जमा नहीं होने पर जमीन के कुर्की के आदेश हो रहे हैं। किसानों को ऋण जमा करने के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं और अब कांग्रेस किसानों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांटने के साथ कमलनाथ सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे।

प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे के आदेश के बाद अब भाजपा किसानों के बीच जाने की तैयारी में है। पार्टी ने तय किया है कि सर्वे पूरा होने के साथ राहत राशि का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा और 9 अप्रैल को पूरे प्रदेश में भाजपा किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को बताने की कोशिश करेगी कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। कौन-कौन सी योजनाओं के जरिए किसानों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। 2023 चुनावी साल है। सरकार का दावा है कि पीड़ित किसानों को 15 दिन में मुआवजा मिलेगा, लेकिन किसानों को हकीकत में यह दूर की कौड़ी लग रहा है। कई किसानों का कहना है कि 6 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कोई सर्वे तक करने नहीं आया। 19-20 मार्च की ओलावृष्टि के बाद पटवारी आए थे। नजरी सर्वे कर ले गए। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि नुकसान के सर्वे के लिए राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग के मैदानी अफसरों की टीम बनाई जा रही है। यह टीम गांवों में जाकर फसलों के औसत उत्पादन की जांच करेगी। इसे राजस्व की भाषा में फसल कटाई प्रयोग कहते हैं। नुकसान का आंकलन इस प्रयोग के आधार पर ही होगा। उनकी दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजे का केस बनेगा। किसानों की चिंता है कि जब तक प्रक्रिया पूरी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो चुकी होगी। यह डर गैर जरूरी भी नहीं है। क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है तो अफसरशाही ऐसा ही करती है। अफसर ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके क्षेत्र में फसल खराब हुई है। ताजा उदाहरण ओले से सर्वाधिक प्रभावित विदिशा जिले की सिरोंज तहसील का है। यहां के एसडीएम बृजेश सक्सेना का कहना है कि उनके क्षेत्र में अधिक नुकसान नहीं हुआ है। केवल धनिया में 50 फीसदी का नुकसान है। गेहूं अभी ठीक है। सरसों चने की 90 प्रतिशत फसल काटी जा चुकी है। कुल मिलाकर नुकसान नगण्य है। किसान कांग्रेस के सचिव सुरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि प्रशासन ठीक से सर्वे नहीं कर रहा है। इसकी वजह से नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने आने में संदेह है, क्योंकि हर चीज आंकड़े पर मानी जाती है। जब रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि नुकसान नहीं हुआ है, तो कौन मानेगा।

भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर कहते हैं कि फसल बीमा का सिस्टम जमीन पर किसी किसान को समझ नहीं आया। इस पर सरकार कई बार हंसी का पात्र बनी है। पिछली बार हरदा जिले के किसानों को फसल बीमा के नाम पर 1.47 रुपए थमा दिए गए थे। इस बार जब तक सर्वे पूरा होगा, रिपोर्ट बनेगी, किसान जमीन पर दूसरी फसल बोने की तैयारी में लग जाएगा। आखिर में नुकसान के अनुपात मुआवजा राशि बहुत कम ही मिल पाती है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से फसल को क्षति पहुंचती है तो सबसे पहले पटवारी, पटेल अथवा कोटवार का जिम्मा है कि उसकी जानकारी स्थानीय राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार के उपखंड अधिकारी को देते हैं। इसके बाद अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर क्षति का आंकलन करते हैं या संभागायुक्त तक पहुंचाते हैं। इसके बाद मुआवजे की फाइल तैयार की जाती है। यानी सर्वे का काम प्रशासकीय सूचना तंत्र की तेजी पर निर्भर है। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जितनी जल्दी नुकसान की जानकारी पहुंचेगी, उतनी तेजी से सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी। सामान्य तौर पर इसमें 5 से 8 दिनों का वक्त लग जाता है। वहीं, सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद किसानों के खाते में राशि पहुंचने में करीब 15 दिन का वक्त लगता है। इस तरह अगर ठीक तरीके से काम होता है तो किसानों को नुकसान का पैसा 20 से 25 दिनों के भीतर मिल जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा होता नहीं है। प्रशासन की लेटलतीफी के चलते कई बार किसानों के खातों में महीनों तक मुआवजे की राशि नहीं पहुंच पाती। कई बार तो वर्षों तक मुआवजे की फाइल दफ्तरों के चक्कर ही लगाती रहती है। प्रदेश में सरकार बारिश और ओले से खराब हुई फसलों के आंकलन के लिए दो फेज में सर्वे करा रही है। पहले फेज में 6-9 मार्च के बीच हुए नुकसान का सर्वे हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, विदिशा, नीमच, खरगोन, राजगढ़ रायसेन, बड़वानी, भोपाल, शाजापुर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और धार इन 16 जिलों में ओले गिरे थे, लेकिन राहत सिर्फ रतलाम, साथ ही, प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर मंदसौर, विदिशा और धार में इन चार जिलों में ही दी जाएगी। इन जिलों में 25 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान दिख रहा है, अन्य 12 जिलों में नुकसान इससे कम है। दूसरे फेज की सर्वे रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।

● **डॉ. जयसिंह सेंधव**

बैंकों की मनमानी अफसरों पर पड़ी भारी

मप्र के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार ने बीते साल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की थी। लेकिन इस योजना का सफलता प्रतिशत 25 फीसदी से भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है योजना की शर्तें और बैंकों की आनाकानी। बैंकों की मनमानी का खामियाजा अफसरों को उठाना पड़ रहा है। राज्य शासन ने उन सभी जिला व्यापार और उद्योग केंद्रों के अफसरों और तृतीय श्रेणी कैडर तक के कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है, जहां इस योजना के केस स्वीकृति और राशि वितरण की प्रोग्रेस की स्थिति में 25 प्रतिशत से कम हैं।

जानकारी के अनुसार यह योजना जब से शुरू हुई है तभी से युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में फेल रही है। स्थिति यह रही है कि इस योजना की बार-बार लॉन्चिंग के बाद भी न तो योजना में युवाओं को अपेक्षित लाभ मिल पा रहा है और न ही इसकी शर्तों के आधार पर बैंक ऋण स्वीकृत करने में रूचि दिखा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि अब अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है। शासन की योजना के तहत ऋण बांटने के मामले में इंदौर पहले स्थान पर है, जबकि वहीं भोपाल दूसरे, जबलपुर तीसरे, रीवा चौथे स्थान और ग्वालियर पांचवें नंबर पर है। जिन जिलों को 25 प्रतिशत से कम परफॉर्मेंस में चिन्हित किया गया है उसमें पन्ना, रायसेन, बैतूल, झाबुआ, बड़वानी, छतरपुर, नीमच, सतना, भिंड, बुरहानपुर शामिल हैं। इसके साथ ही टीकमगढ़, अशोकनगर, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, बालाघाट, दतिया, निवाड़ी, अलीराजपुर और श्योपुर का भी परफॉर्मेंस कमजोर है और ये जिले भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 25 प्रतिशत के कम वितरण वाले जिलों में शामिल हैं। इनका परफॉर्मेंस एक साल में 24.57 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शर्तों और इसको लेकर बैंकों द्वारा लोन मंजूर किए जाने में होने वाली आनाकानी का असर अब जिला उद्योग केंद्र पर पड़ रहा है। राज्य शासन ने उन सभी जिला व्यापार और उद्योग केंद्रों के अफसरों और तृतीय श्रेणी कैडर तक के कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है जहां इस योजना के केस स्वीकृति और राशि वितरण की प्रोग्रेस की स्थिति में 25 प्रतिशत से कम है।

महाप्रबंधकों को दिए निर्देश में कहा गया है कि उद्योग संचालनालय की अनुमति के बाद ही वेतन आहरित किया जा सकेगा। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों को दिए निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 25 प्रतिशत से अधिक प्रगति करने वाले जिलों के वेतन आहरण की अनुमति एमएसएमई संचालनालय देगा। इसी माह संचालक एमएसएमई द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस योजना की समीक्षा की गई थी। इसमें कहा गया था कि ऐसे जिले जिनमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण की प्रगति 25 प्रतिशत से कम है उनके कार्यालय का माह फरवरी का वेतन (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं वाहन चालकों को छोड़कर) उद्योग संचालनालय की अनुमति के उपरांत ही आहरित होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में जिन जिलों द्वारा 25 प्रतिशत से अधिक प्रगति दर्ज कर ली गई है, उन्हें वेतन आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन जिलों में वितरण की प्रगति 25 प्रतिशत कम है तथा जिनके द्वारा फरवरी माह के वेतन का आहरण कर लिया गया था उन्हें माह मार्च का वेतन (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं वाहन चालकों को छोड़कर) उद्योग संचालनालय की अनुमति के उपरांत ही मिल सकेगा।

डीआईसी के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत 50 हजार से 50 लाख तक का लोन उद्योग श्रेणी में मिलता है। जबकि खुदरा व्यवसाय एवं सर्विस सेक्टर के लिए 50 हजार से 25 लाख तक के लोन का प्रावधान है। इस लोन पर 7 साल तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी हितग्राही को जमा करानी होती है, जिसे बैंक चाहे तो कम भी कर सकता है। पहले युवा उद्यमी योजना और स्वरोजगार योजना में यह **मार्जिन मनी शासन द्वारा** अनुदान के तौर पर दे दी जाती थी, लेकिन इन योजनाओं को शासन ने कोरोनाकाल में ही बंद कर दिया है। जबकि आवेदन जमा करने से लेकर व बैंकों के चक्कर लगाकर राशि मिलने तक में ही उसके 5 से 10 हजार रुपए की राशि खर्च हो जाती है। युवाओं का कहना है कि पूर्व में सरकार द्वारा ऋण लेने पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती थी, जिससे युवाओं को कुछ राहत मिलती थी, लेकिन अब कोई राहत नहीं मिल रही है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने योजना में हो चुका संशोधन

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने की पात्रता में संशोधन किया जा चुका है। पूर्व में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य थी, जबकि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक थी। ऐसे में बहुत ही कम आवेदन प्रदेश की सभी डीआईसी में प्राप्त हुए। फीडबैक के आधार पर शासन ने शैक्षणिक योग्यता 12वीं से घटाकर 8वीं कर दी, जबकि आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी। इस संशोधन के बाद आवेदन की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है। चूंकि योजना के अंतर्गत एकमुश्त एवं सीधी सब्सिडी नहीं मिल रही है, केवल ब्याज अनुदान मिल रहा है। जिसके कारण लोग कम ही रूचि ले रहे हैं। रोजगार राकेश खरे, शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। पहले ऋण लेने पर 30 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन उस समय महज 200 से 250 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया जाता था। जिससे विभाग में सैकड़ों आवेदन पहुंच जाते थे, लेकिन अब उद्यम क्रांति योजना में सरकार द्वारा भले ही 1800 बेरोजगारों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सब्सिडी महज 3 प्रतिशत कर दी गई है। जिससे अब इसमें बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार केवल दिखावे के लिए ही योजनाएं ला रही है।

भ्रष्टों पर मेहरबानी

150 अभियोजन की स्वीकृति जल्द देगी प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों पर कार्यवाही के मामले में कहा है कि वे आश्वस्त करना चाहते हैं कि बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाला कोई नहीं बचेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति ही रहेगी। हम लगातार कार्यवाही करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और विधायकों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अफसरों के विरूद्ध अभियोजन की अभी 70 अनुमति जारी की गई है। 150 प्रकरणों में अनुमति जारी करने की तैयारी हो रही है। कहीं-कहीं विधिक दिक्कतें होती हैं उनमें थोड़ा बहुत समय लगता है। विधि विभाग का अलग-अलग अभिमत होता है और फिर वह एक अलग समिति में आता है।

म प्र में भ्रष्ट अफसरों पर भ्रष्ट ही जमकर मेहरबान बने हुए हैं। यही वजह है कि ऐसे अफसरों को न केवल मलाईदार जगहों पर लगातार पदस्थ किया जाता है, बल्कि उन्हें पदोन्नत करने में भी कोई कोताही नहीं बरती जाती है। अब इस मामले को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाना तय कर लिया है। यही वजह है कि इसे अब सदन से लेकर सड़क तक पूरी ताकत के साथ कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनमें भ्रष्ट अफसरों पर शासन से लेकर सरकार की खुलकर मेहरबानी बनी हुई है। भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए पहले ही सरकार द्वारा कई तरह की पाबंदियां जांच एजेंसियों पर थोपी जा चुकी हैं। अब हद तो यह है कि जिन मामलों की पूर्व में जांच पूरी हो चुकी हैं और उनमें चालान पेश किया जाना है, ऐसे मामलों में भी लंबे समय से अनुमतियां नहीं दी जा रही हैं।

ऐसे भ्रष्ट अफसर सरकार के खजाने को तो चूना लगा ही रहे हैं साथ ही सरकार के सुशासन को भी पलीता लगाने में पीछे नहीं हैं। खास बात यह है कि इसकी वजह से आम आदमी भी बेहद परेशान है। बीते रोज विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि सामान्य प्रशासन विभाग **असामान्य होकर** अराजकता की भेंट चढ़ गया है, जो अफसर ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर मनमानी पोस्टिंग पा रहे हैं। संविदा पर रिटायर्ड अफसरों को बार-बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आजीविका मिशन में एक भ्रष्ट अधिकारी की लोकायुक्त जांच कर रहा है, उसे रिटायरमेंट के बाद दोबारा पोस्टिंग दी गई है, जबकि जांच करने वाली अधिकारी नेहा मारव्या को अटैच कर उनकी गाड़ी भी छीन ली गई है। बड़वानी जिले में एक युवा आईएएस अफसर ने किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार प्रमोटी कलेक्टर के भ्रष्टाचार की शिकायत की तो कलेक्टर पर कार्रवाई के बजाय युवा आईएएस को लूप लाइन में भेज दिया। उनका आरोप था कि जो घूस लेते पकड़े गए उन्हें एसडीएम से एडीएम बना दिया गया। 44 केस में 105 क्लास वन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत होने के बावजूद 5 साल से चार्जशीट तक नहीं दी गई है। इसी तरह से सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला करते हुए सरकार से पूछा गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 280 कर्मचारियों की अभियोजन स्वीकृति क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि इसके लिए 4 माह का समय तय है।

ईओडब्ल्यू द्वारा बीते सालों में पदस्थ रहे कलेक्टर, एसडीएम, सीएमओ, इंजीनियर, अस्पताल अधीक्षक, तहसीलदार, सरपंच, सचिव, लेखापाल, शिक्षक सहित 26 विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक अनियमितता के मामलों में पकड़कर 44 प्रकरण दर्ज कर 105 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। लेकिन इनके प्रशासकीय विभागों द्वारा इन मामलों में अभियोजन स्वीकृति ही नहीं दी जा रही है। जिसकी वजह से उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई ही नहीं हो पा रही है। अगर पंचायत ग्रामीण विकास की बात की जाए तो दमोह जिले के पथरिया के तत्कालीन विकासखंड अधिकारी वायएस चौहान पर ईओडब्ल्यू ने नवंबर 1999 में कार्यवाही की और जनवरी 2018 को एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें अब तक अनुमति नहीं दी गई है। इसी तरह एपीओ मनरेगा पनागर प्रशांत शर्मा, पंकज मुडिया उपयंत्री, महबूब खान सीईओ पनागर, सुधा यादव सरपंच सोनपुर, सरला यादव सचिव ग्राम पंचायत गधेरी पर 2015 में दर्ज मामले में ईओडब्ल्यू विभाग से सितंबर 2022 से अभियोजन मंजूरी मांग रहा है। तिलगंवा के सरपंच कृष्णा यादव और पनागर के एपीओ प्रशांत शर्मा के खिलाफ 2015 में दर्ज मामले में जनवरी 2021 को अनुमति मांगी है।

एपीओ पनागर प्रशांत शर्मा, उपयंत्री पंकज मुडिया, सीईओ महबूब खान, सरपंच सोनपुर बेगी बाई ठाकुर, सचिव सोनपुर मोहम्मद सलीम के खिलाफ 2015 में दर्ज मामले में सितंबर 2022 से अनुमति नहीं मिली। इसी तरह से नगरीय विकास एवं आवास में नगर पालिका रतलाम के पूर्व महापौर जयंतीलाल, संपत्तिकर अधिकारी मनोहर लाल वर्मा पर 2020 से, सीहोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी डीएस परिहार, अनुविभागीय अधिकारी हनीफ खान, सहायक यंत्री अनिल श्रोत्रिय, कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक सिसोदिया, उपयंत्री नरेंद्र सिंह चौहान, लेखापाल हरिभान सिंह बुंदेला, लिपिक श्याम सिंह चंद्रवंशी पर 2021 से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामशिरोमणि, आरसी साहू, लेखापाल विष्णुदेव, सहायक ग्रेड तीन धीरेंद्र सिंह, शाखा प्रभारी रामगोपाल मिश्रा पर 2021 से अनुमति लंबित है।

इसी तरह से रीवा के मऊगंज में एसडीएम ओएन पांडेय, एसडीएम एपी घमह के विरूद्ध 2020 से, सेवानिवृत्त कटनी कलेक्टर अंजू सिंह बघेल के खिलाफ 2011 में दर्ज मामले में 2017 से अभियोजन स्वीकृति लंबित चल रही है। बुधनी के दो तत्कालीन तहसीलदार केएस सेन और एमडी शर्मा, एके बड़कुर, लेखापाल रामचरण सिंह के खिलाफ 2019 से, विदिशा के तत्कालीन कलेक्टर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ 2020 से, खाद्य विभाग के तत्कालीन उपसचिव ललित दाहिमा के खिलाफ 2021 से, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सांवेर पवन जैन और कौशल बंसल के खिलाफ फरवरी 2023 से, कटनी की सेवानिवृत्त कलेक्टर अंजू सिंह बघेल के खिलाफ दूसरे मामले में फरवरी 2021 से लंबित है।

● **राकेश ग्रोवर**

स्कूलों में स्कॉलरशिप घोटाला

मप्र में सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर युवा साक्षर बने। इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है स्कॉलरशिप। लेकिन छात्रों को मिलने वाली इस स्कॉलरशिप का कोई दूसरा ही उपयोग कर रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में घोटाले हुए हैं।

मप्र के भिंड समेत 10 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग में स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है। ये खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है जिसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भिंड, बैतूल, आगर-मालवा, सागर, छिंदवाड़ा, देवास और उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए गए हैं। अब इन 10 जिलों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है।

स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के हक को शिक्षा विभाग के लोग ही डकार गए है। इस घोटाले की परतें खुलनी अभी बाकी हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की ओर से प्रदेशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पोस्ट व प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18 से 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराई गई। इस ऑडिट रिपोर्ट में कई खुलासे करने वाली जानकारी सामने आई है। इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा उक्त 10 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। ऑडिट विभाग की जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि स्कॉलरशिप दिए जाते समय नियम व कानून को ताक पर रखा गया।

अनुसूचित जाति के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के बताते हुए स्कॉलरशिप का लाभ दिया गया। वहीं **छात्रों के अभिभावकों** के खाते लगाए बगैर शिक्षा विभाग के लोगों ने अपने नाते, रिश्तेदारों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि डलवाकर हड़प ली। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। कई छात्रों के नाम से शिक्षा विभाग के लोगों ने दो से तीन बार स्कॉलरशिप की राशि हड़प ली। इस तरह शिक्षा विभाग में पदस्थ प्राचार्य से लेकर छात्रवृत्ति प्रभारी व क्लर्क स्तर के लोगों की सीधी भूमिका पर संदेह बना हुआ है। हालांकि स्कॉलरशिप घोटाले में शिक्षा विभाग के जिले के अफसरों पर सवाल उठना लाजिमी है। सवाल उठ रहे हैं कि जिले के अधिकारियों ने धांधली पर कैसे पर्दा डालकर रखा।

स्कॉलरशिप घोटाला की भनक लगते ही शिक्षा विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा घोटाला भिंड के बबेड़ी हाईस्कूल संकुल केंद्र पर हुआ है। ये घोटाला वर्ष 2018 से 2022 तक हुआ है। इस दौरान स्कूल में पदस्थ रहने वाले प्राचार्य रामअवतार ओझा, अवनीश सिंह भदौरिया रहे हैं। बताया जाता है कि भिंड जिले में 715 छात्रों की स्कॉलरशिप में धांधली हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा बबेड़ी हाईस्कूल संकुल पर होना पाई गई है। इस संकुल में पढ़ने वाले करीब 400 ऐसे छात्र हैं जिनके हक की राशि निगल ली गई है। ऑडिट जांच रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि शिक्षा विभाग के कुछ लोगों ने अपने नाते-रिश्तेदारों के खातों को छात्रों के अभिभावकों के तौर पर लगाए हैं। जिनके खातों में ये राशि डाली गई है। शेष छात्र जिले के अलग-अलग संकुल के बताए जा रहे हैं।

यहां तैनात प्रभारी प्राचार्य विजय वीर सिंह कुशवाह का कहना है कि मुझे 6 फरवरी 2023 में स्कूल का प्रभार मिला है। मैंने प्रभार लिया तब से अब तक स्कूल में स्कॉलरशिप की फाइल नहीं मिली। स्कॉलरशिप की फाइल न मिलने पर मैंने विभाग के वरिष्ठ अफसरों को पूरे मामले से अवगत करा दिया है।

लोक शिक्षण संचालनालय के इस पत्र से शिक्षा विभाग से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। अब विभाग के अफसर अपनी कुर्सी को बचाने के प्रयास में जुट गए है। हालांकि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों को घोटाले का धुआं दिख रहा था। परंतु सब चुप्पी साधे हुए थे। अब जांच की आंच से फंसने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक जांच दल गठित किया गया है। इस चार सदस्यीय जांच दल में डिप्टी कलेक्टर पराग जैन, शिक्षा विभाग के एडीपीसी सत्यभान सिंह भदौरिया, शासकीय हाईस्कूल खरिका के प्राचार्य एसएल पंडोलिया और शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति प्रभारी श्यामानंद तिवारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग के लोगों का कहना है कि छात्रवृत्ति प्रभारी को जांच दल में शामिल किया गया है। जबकि इनके प्रभार के समय ही घोटाला हुआ है। फिर ऐसे में जांच कैसे निष्पक्ष हो सकेगी?

● **लोकेंद्र शर्मा**

भोपाल से भेजी घोटाले की लिस्ट

ये जानकारी भी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पास मौजूद है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा उन छात्रों की जानकारी भिंड जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हरभुवन सिंह तोमर को दी गई है। छात्रों को शासन की ओर से स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति की राशि व खातों की जानकारी भी भेजी गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अफसरों को जांच रिपोर्ट कर ऐसे खातों का वैरीफिकेशन करके जांच रिपोर्ट का जवाब शिक्षा विभाग की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय को भेजना होगा। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी हरभुवन सिंह तोमर का कहना है कि यद्यपि कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी।

चीता प्रोजेक्ट को झटका!

भारत में चीते की आबादी को फिर से बढ़ाने की योजना के तहत नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इनमें से एक चीते की मौत हो गई। मादा चीता साशा अब इस दुनिया में नहीं रही। साशा की तबीयत खराब थी और वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी तबीयत में सुधार भी हुआ था, लेकिन आखिरकार उसे बचाया नहीं जा सका। साशा को उसके साथियों के साथ पिछले साल कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया था। पीसीसीएफ वन्यजीव संरक्षण जेएस चौहान का कहना है कि साशा की मौत चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका है। साशा की पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी, ये अभी नहीं बताया जा सकता है। अभी यह लैब में भेजी जाएगी। बाकी चीते स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीता की किडनी में संक्रमण हो गया था तो दूसरे चीते को भी हो। हालांकि, पर्यटकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अन्य चीतों को फिलहाल खुले जंगल में छोड़ना अभी संभव नहीं है।

मादा चीता साशा पिछले करीब 2 महीने से डिहाइड्रेशन और किडनी में इंफेक्शन की समस्या से जूझ रही थी। पोस्टमॉर्टम के बाद साशा का कूनो नेशनल पार्क में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिछले साल 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को रखा गया था। अनिवार्य क्वारंटीन के बाद सभी 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया था। पिछले 21 जनवरी को कूनो के अधिकारियों को मादा साशा के सुस्त और बीमार होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसे नामीबिया और भोपाल वन विहार के वन्यजीव एक्सपर्ट और डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया था। जरूरी ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन 27 मार्च को अचानक उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2022 को नामीबिया में साशा के खून के नमूने की जांच की गई। जांच में क्रियेटिनिन स्तर मानक से ज्यादा सामने आई थी। 22 जनवरी 2023 को साशा की तबियत बिगड़ने पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के वन्य प्राणी चिकित्सक और नामीबियाई विशेषज्ञ डॉ. इलाईवॉकर की टीम ने उपचार किया। 23 जनवरी को वन विहार नेशनल पार्क के मुख्य पशु चिकित्सक डॉ. अतुल गुप्ता की अगुवाई में चिकित्सकों के दल की निगरानी में साशा का एक्सरे सहित अन्य जांचें हुईं। जांचों में किडनी इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन की पुष्टि हुई थी। 24 जनवरी को चिकित्सा दल की निगरानी में साशा को क्वारंटीन करने के साथ-साथ प्रतिदिन की निगरानी शुरू की गई। नियमित इलाज के दौरान चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन और प्रिटोरिया विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ डॉ. एड्रियन टोर्डिफ से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सलाह ली जाती रही। 18 फरवरी को 12 चीतों के साथ आए दक्षिण अफ्रीकी दल में शामिल विशेषज्ञ डॉ. लॉरी मार्कर, डॉ. एड्रियन टोर्डिफ, डॉ एंडी फेजर, डॉ. माइक और फिंडा गेम रिजर्व के वरिष्ठ प्रबंधक से भी साशा के स्वास्थ्य को लेकर एडवाइस ली गई। 26 मार्च की रात साशा की तबियत अचानक फिर से बिगड़ गई और 27 मार्च को सुबह साशा अपने बाड़े में मृत मिली।

मौत के बाद साशा की नामीबिया के समय की हेल्थ हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि नामीबिया से लाते समय जब मादा चीता की जांच रिपोर्ट आई थी, तब उसमें उसके गुर्दों में इंफेक्शन होने की पुष्टि हुई थी। यानि साशा को नामीबिया में भी यह समस्या थी। वन अधिकारियों ने बताया कि अन्य चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं। साशा की मौत होने के बाद कूनो में चीतों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते अभी क्वारंटीन हैं। चार चीते खुले जंगल में घूमकर वन्यजीवों का शिकार करके अपना भोजन तलाश रहे हैं। तीन मादा चीता बड़े बाड़े में हैं, जिन्हें जल्द ही खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा।

22 जनवरी से साशा की मृत्यु की दिनांक तक कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पदस्थ सभी वन्यप्राणी चिकित्सकों और नामीबिया के विशेषज्ञ डॉ. इलाईवॉकर ने रात-दिन मेहनत की। साशा का उपचार किया। उपचार के दौरान लगातार चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन, नामीबिया और प्रिटोरिया विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ डॉ. एड्रियन टोर्डिफ से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहे। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए 12 चीतों के साथ आए वेटरनरी विशेषज्ञ डॉ. लॉरी मार्कर, डॉ. एड्रियन टोर्डिफ, डॉ. एंडी फ्रेजर, डॉ. माइक तथा फिन्डा रिजर्व के वरिष्ठ प्रबंधक से भी साशा के इलाज पर विस्तार से चर्चा की गई है। दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों ने तो इस बात की तारीफ की कि साशा को इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी उसकी अच्छे से देखभाल की गई।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

पर्यटकों के लिए चीतों के दीदार का इंतजार बढ़ा

मादा चीता साशा की मौत से पर्यटकों के लिए चीतों के दीदार का इंतजार और बढ़ गया है। चार चीतों को जंगल में छोड़े जाने के बाद अगले चरण में पर्यटकों को उन्हें दिखाने की प्रक्रिया ही शुरू की जानी थी, पर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन अब नए सिरे से चीतों के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हो गया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अन्य सभी चीते स्वस्थ हैं। उधर, साशा को किडनी के अलावा और क्या-क्या परेशानियां थीं, इसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम से लिए गए सैंपल वेटरनिटी लैब जबलपुर भेजे जाएंगे। चीता प्रोजेक्ट की तय प्रक्रिया के अनुसार चीतों को पहले क्वारंटीन बाड़े और फिर शिकार के लिए बड़े बाड़े में रखे जाने के बाद चार चीतों को खुले जंगल भी छोड़ दिया गया था और अगले चरण में पर्यटकों के लिए इन्हें दिखाने की प्रक्रिया तय होनी थी, इस बीच वहां साशा की मौत से कूनो प्रबंधन सकते में है। 28 नवंबर 2022 से साशा मादा चीता सबाना और सियाया के साथ पांच नंबर बड़े बाड़े में थी। 22 जनवरी को बीमार होने के बाद साशा को उनसे अलग क्वारंटीन बाड़े में लाया गया। कूनो से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कुछ समय से सबाना और सियाया के व्यवहार में परिर्वतन नजर आ रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर संदेह गहरा रहा है।

सरकारी संपत्तियों को बेचकर खजाना भर रही सरकार

मप्र में फैली राज्य शासन की ऐसी संपत्तियां जो मृतप्राय हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार उनको बेच रही है। जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रदेशभर में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेच दी हैं। शासन का मानना है कि इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। इसी के लिए सरकार ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। विभाग प्रदेशभर की अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को सूचीबद्ध कर रहा है और उन्हें बेचकर सरकारी खजाने को भरा जा रहा है। वर्तमान में मप्र सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया। विभागीय सूत्रों की माने तो इस कर्ज से उबरने के लिए संपत्तियों का विक्रय किया जा रहा है। इनमें अधिकांश संपत्तियां मप्र सड़क परिवहन निगम की हैं।

दरअसल, सत्ता में आने के बाद से ही खजाना खाली होने के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार आय के साधन को बढ़ाने में जुटी हुई है। राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आए दिन बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार प्रदेशभर में मौजूद सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। प्रदेश सरकार ने बीते **दो साल में प्रदेश की 600 करोड़** रुपए की सरकारी संपत्तियां बेच दीं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की कहां, कितनी संपत्ति है, उसका क्या व्यावसायिक या अन्य उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रबंधन करने के लिए सरकार ने एक अलग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। यह विभाग प्रदेशभर में सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग संपत्ति के रखरखाव के साथ उसके औचित्य का निर्धारण भी करेगा।

प्रदेश में तकरीबन सभी विभागों के पास अचल संपत्तियां हैं। लोक निर्माण विभाग के पास जो रेस्ट हाउस हैं, उनमें निर्माण तो एक या डेढ़ हजार वर्गफीट पर है लेकिन ढाई से सात एकड़ तक जमीन खाली पड़ी हुई है। साथ ही वो अचल संपत्ति, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उनके निराकरण की समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। ऐसी सभी संपत्तियों का उपयोग अब राज्य हित में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने के बाद अब 131 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां बेचने की तैयारी की जा रही हैं। नर्मदापुरम का पिपरिया वेयर हाउस 2.14 करोड़ रुपए, कटनी का ब्लॉक-तीन 8.19 करोड़, ट्रैक्टर स्कीम इटारसी 11.87 करोड़, छतरपुर के नौगांव की 5.51 करोड़ संपत्ति और धार का बस डिपो 25.58 करोड़ रुपए में नीलाम किया जाएगा। इसी तरह ग्वालियर की 47.92 करोड़ रुपए कीमत की तीन संपत्तियां विक्रय के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरह 131.21 करोड़ की संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में ऐसी शासकीय संपत्तियां जिनका वर्तमान स्थिति में उपयोग नहीं है उन्हें चिन्हित कर उनका विक्रय किया जाता है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इन संपत्तियों को चिह्नित करता है और उन्हें नीलाम करता है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आय अर्जित हो रही है। उप्र के झांसी में मप्र परिवहन विभाग का बस डिपो भी विक्रय किया जाएगा। हालांकि इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। इस वर्ष 65 से अधिक संपत्तियां विक्रय के लिए चिन्हित की गई हैं। बता दें कि भोपाल की प्राइम लोकेशन पर स्थित आरटीओ और मप्र सड़क परिवहन निगम की संपत्ति भी विक्रय करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में आरटीओ कार्यालय भाजपा को किराए पर दिए जाने से फिलहाल इस संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया रोक दी गई है। दिसंबर, 2020 से अभी तक 553.59 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26.96 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 282.97 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 256.71 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची गई। उपयोग में नहीं आ रही संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य शासन की संबंधित जिले में स्थित अनुपयोगी परिसंपत्तियों की नीलामी/विक्रय जिला नजूल निवर्तन समिति से प्राप्त एवं **कार्यपालिका** समिति द्वारा निर्णय के आधार पर किया जाता है। जिले में शासन की अनुपयोगी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिला कलेक्टर समक्ष अधिकारी होता है।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने सरकारी संपत्तियां बेचने की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत बस डिपो, रेस्ट हाउस, मकान, खाली भूखंड, कारखाने, ऑफिस, बिल्डिंग, रेशम केंद्र, सिल्क केंद्र आदि बेचे जा रहे हैं। इन संपत्तियों को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई संपत्तियों की बिक्री के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। कुछ संपत्तियों की बोली भी शुरू हो गई है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

प्रदेश के बाहर की संपत्तियां भी बिकेंगी

मप्र के बाहर शासकीय परिसंपत्तियों से आय बढ़ाने के लिए सरकार उनका नए सिरे से उपयोग करेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत मप्र के स्वामित्व वाली वे संपत्तियां जो अन्य राज्यों में हैं और अविवादित हैं, उन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। वहीं, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों की अनुपयोगी परिसंपत्तियों को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन और परिसरों के नए सिरे से उपयोग के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 में लागू की गई थी। इसका दायरा सीमित था लेकिन अब इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नीति में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक निगम, मंडल, प्राधिकरण और नगरीय निकायों के भवन या परिसर भूमि का नए सिरे से उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश के बाहर स्थिति अविवादित और अनुपयोग संपत्ति भी नीति के दायरे में आएगी। मप्र की उप्र, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में संपत्तियां हैं। पुनर्घनत्वीकरण के अलावा उन संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जो अनुपयोगी हैं। इसके लिए अब लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया गया है।

सजा बनी संजीवनी!

फिल्म दलाल का यह गीत आपने सुना ही होगा- ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी... कुछ इसी तरह की स्थिति इस समय भारतीय सियासत में देखने को मिल रही है। मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। राहुल की इस सियासी शहादत ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इससे विपक्ष के खेमे में उबाल आया है। उनके बीच एक होने की चाहत में खलबली मच गई है।

● राजेंद्र आगाल

आखिरकार वही हुआ, जिसकी आशंका कांग्रेस को सता रही थी। इधर मानहानि मामले में सूरत की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई, उधर लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार अगर किसी सदस्य को आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस नियम के अनुसार लोकसभा सचिवालय के कदम को सही कहा जा सकता है। लेकिन यह कदम इतने आनन-फानन में उठाया गया है कि इसको लेकर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। कई नेताओं की दावेदारी में बंटे विपक्ष को हालात ने राहुल गांधी के आसपास केंद्रित होने का मौका दिया है। अब जबकि लोकसभा चुनाव में 400 दिन से कम समय रह गया है तब देखना दिलचस्प होगा कि खंड-खंड में बिखरा विपक्ष राहुल गांधी की सियासी शहादत पर कितने दिनों तक एक रह पाता है।

राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है, उससे तो यह दिख रहा है कि विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। अपनी डफली अपना राग से सुर लगाने वाले ज्यादातर विपक्षी नेता फिलहाल एक सुर में नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर हैं और 'लोकतंत्र खतरे में है' वाली आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष के सभी नेताओं ने एकसुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का विरोध किया है। अब यह कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष की प्रतिबद्धता पर है कि वह इस मौके का लाभ कितनी देर तक और कितनी दूर तक साथ चलकर उठा पाती है। या फिर विपक्ष को राहुल गांधी के इर्द-गिर्द समेटकर सीमित कर देने वाली भाजपा इस दांव का दोहरा चुनावी लाभ ले जाती है। वह इसलिए कि राहुल गांधी पर अनिच्छा भाव से राजनीति करने के पहले भी आरोप लगते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से निरंतर विस्तार ले रही भाजपा उसका सीधा लाभ उठाती रही है। मगर यह सब जिस तरह आनन-फानन में हुआ, उससे नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि सूरत की स्थानीय अदालत का फैसला कहां तक उचित है, कि लोकसभा सचिवालय का यह नया फैसला आ गया। हालांकि सूरत की अदालत ने फैसला सुनाने के साथ राहुल गांधी को एक महीने की मुहलत भी दी थी कि इस बीच उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। मगर लोकसभा सचिवालय ने एक दिन की मुहलत देना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को सरकार पर नए सिरे से आरोप लगाने का एक और मौका मिल गया है।

भाषा पर संयम जरूरी

सूरत की अदालत के फैसले से एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं को अपनी भाषा में संयम रखना ही चाहिए। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय भी राहुल गांधी को मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुका है। गौरतलब है कि 2019 में संघ पर टिप्पणी करने के कारण राहुल को मानहानि का सामना करना पड़ा था और कोर्ट में उपस्थित होकर उन्होंने बयान दर्ज कराया था। तब जाकर कोर्ट ने उन्हें 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। उप्र में आजम खान भी इसी तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मगर देखना है कि इन फैसलों से राजनेता कितना सबक लेते हैं। राहुल गांधी के मामले में आए फैसले के राजनीतिक और न्यायिक निहितार्थ हो सकते हैं, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर राजनेताओं को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए अशोभन वक्तव्य देने की छूट क्यों मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से किसी को निशाना बनाकर अपमानजनक वक्तव्य दिया। ऐसे राजनेता हर दल में हैं।

सत्तापक्ष भी इससे अछूता नहीं है। उसके कई नेताओं के बयानों को लेकर आपत्ति जताई जाती रही है, अलबत्ता उनके खिलाफ इस तरह किसी ने मानहानि का मामला दर्ज नहीं कराया। दरअसल, राजनीति में यह मानकर चला जाता रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान या रैलियों में सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मगर राहुल गांधी के मामले से अब यह आशंका भी पैदा हो गई है कि कहीं सारे राजनीतिक दल इसे परिपाटी न बना लें। इस तरह उम्मीद की जाती है कि सभी राजनेता इस गंभीरता को समझ सकेंगे कि उन्हें सार्वजनिक मंचों और बयानों के वक्त भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इसमें बेशक सत्तापक्ष यह कह रहा हो कि राहुल गांधी को सजा अदालत ने सुनाई है और उनकी सदस्यता नियम के मुताबिक समाप्त की गई है, मगर उस पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगने शायद ही बंद हों। क्योंकि सत्तापक्ष के नेता उसी समय से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जब उन्होंने लंदन में भाषण दिया था। इस तरह उनकी सदस्यता जाने से सत्तापक्ष को कितना नफा-नुकसान होगा, यह तो समय बताएगा, मगर राजनीतिक मर्यादा की रेखा तो उसके सामने भी खिंची हुई है।

अब पूरा विपक्ष भाई-भाई

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब वे राजनीतिक पार्टियां भी कांग्रेस के साथ आ गई हैं, जो अब तक कांग्रेस से दूर भाग रही थीं। जैसे आम आदमी पार्टी और तृणमूल

18 दल आए एक साथ

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में 18 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। तो क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? इस पर हैदर अली आतिश का एक शेयर याद आता है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक कतरा-ए-खून ना निकला। कहने को 18 राजनीतिक दलों ने शिरकत की, लेकिन इन सारे राजनीतिक दलों की लोकसभा में हैसियत 144 सीटों की है। इनमें भी सिर्फ तीन दलों डीएमके, टीएमसी और जेडीयू की सीटें डबल डिजिट में है। बाकी सब सिंगल डिजिट वाले राजनीतिक दल हैं। लोकसभा में 9 सीटों वाली भारत राष्ट्र समिति और 4 सीटों वाली शरद पवार की एनसीपी को भी जोड़ लें तो कांग्रेस समेत इन सभी दलों की हैसियत 127 दलों की है। बाकी 12 दलों के सिर्फ 17 सांसद हैं। तीन पार्टियों का एक-एक सांसद है, चार पार्टियों के सांसद ही नहीं हैं। रिकार्ड के लिए इन सारे राजनीतिक दलों की लोकसभा में हैसियत देख लीजिए- कांग्रेस (51), द्रमुक (24), तृणमूल कांग्रेस (23), जनता दल यूनाइटेड (16), ये 16 सीटें वे भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन के कारण जीते थे। भारत राष्ट्र समिति (9), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (4) और बाकी 12 दलों के 17 सांसद हैं। नेशनल कांफ्रेंस (3), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (3), समाजवादी पार्टी (3), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (3), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (2), आरएसपी (1) तमिलनाडु की वीसीके (1), झामुमो (1) आम आदमी पार्टी (0), एमडीएमके (0), केरला कांग्रेस (0), राष्ट्रीय जनता दल (0)।

क्या इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे राहुल गांधी?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा व 15 हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया था। हालांकि अदालत ने उसी समय राहुल गांधी की जमानत लेते हुए उन्हें एक महीने में ऊपरी अदालत में अपील करने का समय दिया था। निचली अदालत के इस फैसले को आधार बनाकर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। राहुल गांधी को अपने बचाव में ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी तभी वह जेल जाने से बच सकेंगे एवं उनकी संसद की सदस्यता भी बच पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चाहे वह ललित मोदी, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। इसको लेकर सूरत पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने तीन बार सूरत कोर्ट में पेश होकर खुद को निर्दोष बताया था। इसी मामले में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएस वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया। मगर इसके साथ ही उन्हें जमानत देते हुए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया था। ताकि उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे।

कांग्रेस। गत दिनों इन सबने मिलकर संसद में प्रदर्शन किया। सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्य काले कपड़े पहनकर लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे थे। कांग्रेस जिस तरह संसद से सड़क तक प्रदर्शन की बात कर रही है, हो सकता है आगे चलकर विरोध प्रदर्शन के इस पूरे चक्र में सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ जाएं। दरअसल, विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि संसद सदस्यता जाने के कारण राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति उपजेगी और अगर इस सहानुभूति का कोई फायदा वोट के रूप में कांग्रेस को होता है तो ये छोटे दल भी इस गंगा में हाथ धो लेंगे। चूंकि यह साथ तात्कालिक लाभ से प्रेरित है, जैसा कि राजनीति में होता है, तो इसका कोई स्थाई परिणाम अभी से नहीं सोचा जा सकता। आने वाले दिनों में किसी एक चुनाव का परिणाम अगर कांग्रेस के विपरीत आ जाता है तो ये सभी दल फिर से अपने पुराने राग अलापने लगेंगे। कांग्रेस का साथ छोड़ने में ये फिर पलभर का भी समय नहीं लगाएंगे। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसे इस सबसे बहुत ज्यादा फर्क तुरंत तो नहीं ही पड़ने वाला है क्योंकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आम जनता से उसे सीधे तौर पर जोड़ता हो। महंगाई या पेट्रोल के दाम या गैस सिलेंडर की कीमत अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनता। लोगों को कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। अब तो हालत यह है कि रोज पेट्रोल या डीजल भराने वालों को भी इनका सही भाव पता नहीं होता। कारण साफ है- जेब से निकालकर कोई कीमत अदा करे तो भाव पता चले। सब के सब अब तो कार्ड से पेमेंट करते हैं या फोन पे, गूगल पे से।

बेरोजगारी भी अब तो ज्वलंत मुद्दा नहीं रहा। एक अडाणी के नाम से आप कब तक चिल्लाते रहेंगे। थोड़े दिन में लोग यह नाम भी भूल जाएंगे। कुल मिलाकर सारा मामला इस बात पर निर्भर है कि कांग्रेस इस विरोध को इन प्रदर्शनों को, किस हद तक और किस रूप में आगे ले जा पाती है। राजनीतिक विश्लेषक एक संस्मरण के माध्यम से कहते हैं कि आजादी के बाद से अलग-अलग मुद्दों पर कई सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। पहला मामला एचजी मुद्गल का था, जिसे मुंबई की

राहुल गांधी की तरह भाजपा विधायक की गई थी सदस्यता

मानहानि मामले में सूरत की विशेष अदालत के 2 साल की सजा सुनाने के अगले दिन लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। बिल्कुल ऐसा ही केस मप्र में 2019 में आ चुका है। दोनों केस में फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा हुई और विधायक प्रहलाद लोधी को सरकारी अफसरों के साथ मारपीट मामले में सजा हुई थी। जिस तरह अदालत के फैसले के 24 घंटे में ही राहुल की लोकसभा से सदस्यता समाप्त हुई, इसी तरह लोधी की विधानसभा की सदस्यता छिन गई थी। तब मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी। हालांकि, लोधी को सदस्यता समाप्त किए जाने के 6 दिन बाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। मप्र में लोधी के अलावा और भी विधायक हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई है। 28 अगस्त 2014 की बात है। पन्ना जिले की रैपुरा तहसील पदस्थ तहसीलदार आरके वर्मा को अवैध रेत खनन की सूचना मिली। बताया जाता है कि नोनीलाल लोधी द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। इसके रोकने के लिए तहसीलदार वर्मा वहां पहुंचे। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया। भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को यह नागवार गुजरा। वापस लौटते समय मडवा गांव के पास प्रहलाद लोधी और उनके साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप रोक दी। वर्मा के साथ मारपीट, गाली-गलौज की गई। विधायक लोधी के साथ उनके 12 समर्थक भी इस घटना में आरोपी बनाए गए। मामला कोर्ट पहुंचा। भोपाल की विशेष अदालत ने लोधी को सरकारी अफसरों से मारपीट का दोषी पाया। 1 नवंबर 2019 को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। अगले दिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने लोधी की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया। विधानसभा सचिवालय ने लोधी की सदस्यता समाप्त कर पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी। विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि को सजा मिलती है, उसी क्षण उनकी सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। ऐस में लोधी भूतपूर्व हो चुके थे। लोधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। बहस के दौरान के हाईकोर्ट में विधायक लोधी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू (27 दिसंबर 1988 रोड रेज मामला, जिसमें सिद्धू ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की थी।) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, हालांकि सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया।

कार्यपालिका से प्रश्न के बदले धन स्वीकार करने के आधार पर वर्ष 1951 में संसद से बाहर कर दिया गया था। जून 1951 में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और अटॉर्नी जनरल से समिति की सहायता करने का अनुरोध किया गया। अंतत: जब मुद्गल के निष्कासन का प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया गया, तो संबंधित सदस्य को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी गई। अपने भाषण के तुरंत बाद मुद्गल मंच पर गए और अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि, इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। इस मामले की एक खास बात यह थी कि जब मुद्गल को निष्कासित किया गया था, तब पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा के अधिकांश दिग्गज मौजूद थे। मुद्गल ने अपने निष्कासन को कभी चुनौती नहीं दी। राहुल गांधी के मामले में भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन तथाकथित विदेश की धरती पर भारत को अपमानित करने का जो आरोप है, क्या उसका उत्तर संसद में राहुल गांधी को देने का अवसर दिया जाएगा?

भाजपा के लिए मोदी-अडाणी के संबंधों के बारे में न बताना नागफांस बन गया है। अब कांग्रेस को तो संसदीय गरिमा का पालन करना ही होगा, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यों की कमेटी की और सेबी की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। कांग्रेस को रिपोर्ट का इंतजार तो करना ही चाहिए कि आखिर दोनों की जांच रिपोर्ट क्या कहती है। सच तो यह है कि कांग्रेस, अडाणी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को बेनकाब करना चाहती है। यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर यदि सरकार की मंशा साफ है, तो सत्तारूढ़ भाजपा को यह बताने में क्या परेशानी है कि प्रधानमंत्री और अडाणी के बीच कोई संबंध नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री ने देश और विदेशों में अडाणी की कोई मदद नहीं की है, तो फिर भाजपा इतना परेशान क्यों है कि संसद को बाधित कर कामकाज के समय को बर्बाद कर रही है। इस हंगामे के बाद देश की जनता की समझ में यह बात अब धीरे-धीरे आती जा रही है कि भाजपा द्वारा पिछले 9 वर्षों तक तरह-तरह के जो वादे किए गए, वे सारे के सारे चुनावी वादे ही थे और सच में कांग्रेस जिन संबंधों की बात कर रही है, उसकी दाल में कुछ काला तो जरूर है, जैसा की कांग्रेस ने आरोप लगाया है। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं हो जाता, वे संसद को चलने नहीं देंगे, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जब तक राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के लिए जो टिप्पणी की है, उसके लिए माफी नहीं मांगते, वे भी कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। अब जिन्होंने इन नेताओं को अपने हित के लिए चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है उन्हें अपने कृत्य पर पछताना तो पड़ेगा ही, उन्हें हाथ तो मलना ही होगा, सिर तो धुनना ही होगा।

मोदी का सांसदों को मंत्र लड़ाई के लिए तैयार रहो

विपक्ष की एकता और आक्रामकता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। बैठक में नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि जैसे-जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, विपक्ष के हमले और तेज होते रहेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग फाइट के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पार्टी सांसदों को नसीहत दी कि वह 9 साल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच लेकर जाएं और अपने-अपने क्षेत्रों में इनका प्रचार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 मई से 15 जून तक सभी सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता के बीच जाएं। उन्होंने इस दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर किसी भी माध्यम से प्रचार करने को कहा है। बैठक में 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर प्लानिंग हुई। पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी बीआर अंबेडकर की जयंती तक सोशल जस्टिस वीक मनाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एक साल का समय बचा है। यही वजह है कि विपक्ष जहां सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है, वहीं सरकार भी जनता के बीच अपने कामों को पहुंचाने में जुट गई है।

विवादों में कानून

मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में दो साल की कैद की सजा पाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 रीप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत की गई। राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन के बाद से इस कानून पर बहस शुरू हो गई है। 70 साल से ज्यादा पुराने जनप्रतिनिधित्व कानून के एक सेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तक दायर कर दी गई है। इस याचिका के जरिए रीप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 8 (3) को चुनौती दी गई है। साथ ही मांग की गई है कि इस सेक्शन को रद्द किया जाए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता चुके हैं। इस मामले में लीगल एक्सपर्ट की राय भी अलग-अलग है।

जनप्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि, धारा 8(3) के तहत प्रतिनिधियों को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपने आप अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। पीआईएल में कहा गया कि चुने हुए प्रतिनिधि को सजा का एलान होते ही उनका जन प्रतिनिधित्व यानी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल में कहा गया है कि अधिनियम के चैप्टर-3 के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर, गंभीरता, भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर क्या फैसला देती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्रवाई और नियम पर बहस जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता की घोषणा के बाद अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रहे हैं- पहला, अयोग्यता, जो 2013 में लिली थॉमस मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार प्रभावी हुई है और दूसरा, उनकी सजा पर रोक कैसे लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द कर देगी।

दरअसल राहुल गांधी से पहले लिली थॉमस मामले में शीर्ष अदालत ने घोषणा की कि एक सांसद या एक विधायक दोषी ठहराए जाने पर तुरंत अयोग्य हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देनी चाहिए, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है और लोकसभा से उनकी अयोग्यता से संबंधित अधिसूचना को भी चुनौती देनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि लिली थॉमस में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसकी 2018 में लोक प्रहरी मामले में फिर से पुष्टि की गई थी, यह बहुत स्पष्ट है कि दो साल की सजा होने के बाद अयोग्यता हो जाती है और लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना इसका प्रशासनिक पहलू है। लूथरा, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर गांधी की सजा पर रोक लग जाती है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के पास जा सकते हैं और दोषसिद्धि पर रोक उन्हें 2024 का चुनाव लड़ने की अनुमति देगी।

कांग्रेस के सलाहकार गंभीर नहीं

राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी यही है कि उसकी सलाहकार मंडली में गंभीर लोग कम हैं। वे बार-बार राहुल और प्रियंका को सिर्फ नैरेटिव आधारित आक्रमण का

सुझाव देते हैं। राहुल के एक सलाहकार रोजाना ट्विटर पर जिस प्रकार की सतही अभिव्यक्ति करते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस तरह का सुझाव देते होंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि राहुल की छवि भाजपा ने जानबूझकर बिगाड़ी है। दरअसल राजनीतिक मैदान में छवि बनाने और बिगाड़ने पर ही जब लोकतांत्रिक नतीजे प्रभावित होते हों तो राजनीतिक दल ऐसा करेंगे ही। ऐसे में अपनी छवि को लेकर जवाबदेह और जिम्मेदार बनना आवश्यक है। राहुल बयान देते वक्त यहीं चूक जाते हैं। उनकी यह चूक ही उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। अब तो सूरत की अदालत के फैसले के बाद यह स्थापित ही हो जाएगा कि राहुल जुबानी गलतियां करते रहे हैं। भले ही बाद में उन्हें ऊपरी अदालत से राहत मिल जाए। राहुल की संसद सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर विवाद स्वाभाविक है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं, उसकी हालिया सहयोगी बनी शिवसेना भी कह रही है कि राहुल की सदस्यता रद्द होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस इसे सियासी मामला बताते भी नहीं थक रही है। कांग्रेस कह रही है कि चूंकि संसद और संसद से बाहर राहुल निडर होकर बोल रहे हैं, इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और आनन-फानन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इस बहस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं पीछे छूट गया है। राजनीति की जो रवायत है, उसमें कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा चाहेगी कि मामला राजनीति के बजाय अदालत और राहुल की बदजुबानी पर ही केंद्रित रहे।

कुछ महीनों बाद कर्नाटक, राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि इस मामले में राहुल को राजनीतिक बलिदानी बताया जाए और मोदी सरकार के कदम को कठघरे में खड़ा किया जाए, ताकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता कायम रखने के साथ ही कर्नाटक और मप्र में भाजपा से सत्ता छीनी जा सके। इसलिए अगले कुछ दिनों तक कांग्रेस अपने देशव्यापी सांगठनिक ढांचे की बदौलत जिलास्तर तक राहुल की सदस्यता खारिज किए जाने को मुद्दा बनाती रहेगी। देश को अगले कुछ दिनों तक कांग्रेसी धरना-प्रदर्शनों के लिए तैयार रहना होगा। जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है, वहां यह विरोध तीखा हो सकता है। जहां संगठन कमजोर है, वहां विरोध धीमा दिखेगा। राहुल को उन विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है, जिनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं या जिनके खिलाफ ऐसी ही बदजुबानी को लेकर मानहानि के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं।

मप्र में भी एक नेता जेल होकर आ गए

देश में इन दिनों राहुल गांधी मामले में बवाल मचा हुआ है। उधर, मप्र में भी एक कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुशब्द बोलने के कारण जेल की हवा खा चुके हैं। ये नेता हैं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया। राहुल गांधी के बयान पर पटेरिया का कहना है कि एक बार और फिर मैं उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर एक अदालत के फैसले के लिए कुछ विचार रखना चाहता हूं। जिस वक्त उन्होंने वो बयान दिया, सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब, यह कांग्रेस पार्टी का संविधान सम्मत और पूरी पार्टी का बयान था। अतः मैं उस वक्त का कांग्रेस कार्यकर्ता होने से उस सजा का पूरा भागीदार हूं। और जो भी कांग्रेसी उस वक्त किसी भी पद पर, प्रदेश अथवा देश में थे सभी भागीदार थे। जिसे इससे आपत्ति है, वे इसे लिखित में दर्ज करें और तत्काल कांग्रेस छोड़ दें। अन्यथा, सभी कार्यकर्ता न्यायालय से गुजारिश करें कि सभी को उसी जुर्म की समान सजा दी जाए। हम सभी को जेल में डाल दिया जाए। मैं स्वयं को, इस जेल यात्रा के लिए प्रस्तुत करता हूं। आज एक लकीर खींची गई है। जो व्यक्ति, पार्टी या संस्थान अडाणी या भाजपा, संघ को वित्त पोषित करने वाले व्यक्ति या संस्थानों में निवेश करते हैं या उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ते रखते हैं, वो भाजपा के साथी हैं और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अब भी ऐसा करते है मुझे ये कहने में कोई दुख नहीं कि वे सभी फूल छाप कांग्रेसी हैं।

बढ़ती जा रही भिखारियों की संख्या

केंद्र सरकार को इन दिनों जनसंख्या से लेकर अन्य तमाम तरह के सर्वेक्षण कराने चाहिए। इससे बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति तथा लोगों की आजीविका के संसाधनों के आंकड़े स्पष्ट होंगे। कोरोनाकाल ने इस देश के सामान्य वर्ग से जो कुछ छीना है, उसने तमाम परिवर्तन ऐसे हुए हैं, जो दुखी करते हैं। अगर देश में भिक्षावृत्ति पर एक नजर डालें, तो पता चलता है कि इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। केवल दिल्ली के मंदिरों के आगे भिखारियों की स्थिति देखें, तो पता चलता है कि अक्षरधाम मंदिर, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, करोल बाग के झंडेवाला मंदिर, कालका मंदिर, यहां तक की गली-मोहल्लों में बने छोटे-छोटे मंदिरों पर भिखारियों का जमावड़ा लगा रहता है।

हाल यह है कि किसी श्रद्धालु के मंदिर में घुसने और निकलने के दौरान भिखारी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इसी तरह दिल्ली में बनी मजारों के आगे भिखारियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। गुरुद्वारों में भी भिखारियों का कब्जा कम नहीं है, लेकिन वहां उन्हें दोनों वक्त का खाना आसानी से मिल जाता है, इसलिए इनकी संख्या गुरुद्वारों के बाहर कम ही दिखाई देती है। लक्ष्मी नगर के साईं मंदिर के पंडित संदीप कहते हैं कि चार-पांच साल पहले तक हर गुरुवार को भिखारी और श्रद्धालु मंदिर के आगे प्रसाद पाने आते थे, लेकिन अब भिखारी यहां हर रोज खूब देखे जा सकते हैं। हम लोग इन्हें परेशान देखकर नहीं भगाते, पर यह पूजा-पाठ करने आने वालों को अब परेशान करने लगे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के भिखारी यहां देखे जा सकते हैं। कोरोना जबसे आया है, यह संख्या बहुत बढ़ गई है। इसी तरह अक्षरधाम मंदिर पर बच्चे को गोद में लिए फुटपाथ पर ठंड में बैठी एक महिला भिखारी से पूछा गया कि वह यहां क्यों बैठी है? तो उसने जवाब न देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यह पूछने पर कि उसका पति कहां है और क्या करता है? महिला ने खामोशी से एक तरफ इशारा कर दिया। एक दूसरी महिला, जो कुछ दूरी पर बैठी थी, उसका कहना था कि- हमार घर नाहीं है। यहीं से जो पावत हैं, उसी से ये पापी पेटवा भरत हैं।' यह कहते-कहते महिला का गला रुंध गया।

यह दशा किसी एक मंदिर के बाहर की नहीं है, बल्कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर से लेकर बस स्टैंडों और बाजारों तक की है। हर रोज गली में दरवाजे पर आकर आवाज लगाने वाले दर्जनों भिखारियों को देखा जा सकता है। भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इनकी क्षेत्र और जगह भी बंट चुकी हैं। स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन भिखारियों को कुछ बांटने के लिए पहुंचता है, तो उसे भीख मांगने वालों की एक भीड़ घेर लेती है। भीख मांगने वालों में युवाओं और बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनका जीवन बर्बाद हो रहा है। बच्चों से लेकर किशोर और युवा होते युवा-युवती जिन तरह मंदिरों, मजारों के बाहर हाथ फैलाकर दिनभर बैठे रहते हैं, वह बढ़ती भुखमरी और बेरोजगारी का स्पष्ट उदाहरण है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा बाढ़ की तरह बढ़ रही भिक्षावृत्ति देश में अराजक और आलसी लोगों की एक फौज खड़ी कर देगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान देश में चार लाख से ज्यादा भिखारी और बिना किसी काम और आय के साधन वाले लोग थे। कई लोगों के लिए तो भीख मांगना एक व्यवसाय बन चुका है और भिक्षावृत्ति को आजीविका का साधन बना चुके लोग इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि पढ़े-लिखे लोग ही भीख मांग रहे हैं, बल्कि डिग्रीधारी लोगों ने भी कई जगह भीख मांगने को पेशा बनाया हुआ है। इनमें कुछ मजबूर भी होंगे, तो कुछ शौकिया भी यह धंधा पकड़े हुए हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि भिखारियों के संगठन बने हुए हैं, जो भिक्षावृत्ति से करोड़ों रुपए सालाना कमाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस मामले पर खामोश बैठी हुई हैं और बढ़ती भिक्षावृत्ति पर किसी को कोई चिंता नहीं है। देश में बढ़ती भिक्षावृत्ति देश की आर्थिक दशा का वह आईना है, जो हर किसी को साफ-साफ बेरोजगारी, भुखमरी और देश की आर्थिक हालत की तस्वीर दिखा रहा है। पता नहीं क्यों सरकारों को यह तस्वीर दिखाई नहीं देती। जाने कितने ही लोग भीख मांगने को रोजगार का विकल्प बनाते जा रहे हैं, जो उन लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, जिनके सामने कोई हाथ अचानक भीख मांगने के लिए उठता है। इसमें एक बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, वह भिक्षावृत्ति में लिप्त माफिया राज है। सन् 2011 में सामाजिक न्याय एवं सशक्ति की 'शिक्षण स्तर और प्रमुख गतिविधि के तौर पर गैर कामगारों' के आंकड़ों में पुष्टि हुई थी कि उस दौरान के 4,13,670 भिखारियों में से 2,21,673 भिखारी पुरुष और 1,91,997 भिखारी महिलाएं थीं। हैरानी की बात है इन भिखारियों में उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे। इनमें 21 प्रतिशत 12वीं पास थे। सन् 2011 के राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा 81,244 भिखारी पश्चिम बंगाल में थे। इसके बाद उप्र में 65,000 से ज्यादा, बिहार और आंध्र प्रदेश में 30,000, मप्र में 28,000 भिखारी थे। इसी तरह दिल्ली में 23,000 भिखारी थे। आंकड़ों से पता चलता है कि आईटी हब बेंगलुरू जैसे शहर में सन् 2011 में 80 भिखारी स्नातक और 30 डिप्लोमाधारी थे। केरल जैसे शिक्षित राज्य में भी सन् 2011 में 42 प्रतिशत भिखारी शिक्षित थे।

● **विकास दुबे**

साल दर साल बढ़ रही संख्या

मार्च, 2018 में भिखारियों को लेकर लोकसभा में सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा जारी केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस समय तक देश में कुल 4,13,760 भिखारी थे, जिनमें 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिला भिखारी थे। इस रिपोर्ट में भी पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा भिखारियों का राज्य बताया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे कम केवल दो भिखारी लक्षद्वीप में बताए गए हैं। लेकिन कोरोनाकाल के बाद से जिस तरह भिखारियों की संख्या बढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि देश में 10,00,000 से कम भिखारी नहीं होंगे। भिक्षावृत्ति के आंकड़ों का सर्वे न होने के कारण खुलकर हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं।

जीत का मुद्दा किसान या रोजगार?

चुनाव आते ही कुछ मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिला सशक्तिकरण, खुद-ब-खुद ट्रेंड में आ जाते हैं। 2018 में कांग्रेस ने किसान के नाम पर ही मप्र में मतदाताओं को आकर्षित करने में सफलता हासिल की थी। इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इन्ही मुद्दों को थामे रखना चाहेगी। भाजपा की बात करें तो मप्र में पार्टी हर सर्वे में जीत से दूर नजर आ रही है।

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इन तीन प्रदेशों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने को हैं, ऐसे में यहां सभी दल अपना-अपना जोर आजमा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी दल, अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं बात केवल मप्र की करें तो यहां होने वाले ज्यादातर सर्वे में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब मौजूदा स्थिति अन्य दलों को तो उत्साहित कर रही है, वहीं भाजपा के लिए सरकार दर्द बनी हुई है, और इससे बाहर निकलने के लिए भाजपा हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार है।

यूं तो इन चुनावों के लिए सभी दल सोच-समझकर मुद्दों का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दल, इस विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं। एक तरफ भाजपा अपने लिए सत्ता तक का रास्ता चुन रही है और विकास यात्रा के साथ अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, वहीं राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस भी विधानसभा 2023 के लिए कमर कस चुकी है। इसी के साथ दोनों पार्टियां अपने-अपने चुनावी मुद्दों के चयन में भी काफी सतर्कता बरत रही हैं।

जाहिर है, चुनाव आते ही कुछ मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिला सशक्तिकरण, खुद-ब-खुद ट्रेंड में आ जाते हैं। 2018 में कांग्रेस ने किसान और कर्जमाफी के नाम पर ही मप्र में मतदाताओं को आकर्षित करने में सफलता हासिल की थी। इसलिए अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार भी इन्ही मुद्दों को थामे रखना चाहेगी। हालांकि उम्मीद है इन चुनावों में कांग्रेस, रोजगार के लिए तड़प रहे युवाओं के साथ, बेरोजगारी के मुद्दे को जमकर भुनाएगी। भाजपा की बात करें तो मप्र में पार्टी हर सर्वे में जीत से दूर नजर आ रही है। इसकी एक वजह एंटी इनकम्बेंसी को भी माना जा सकता है।

राजनीतिक रणनीतिकार अतुल मलिकराम के अनुसार, इतने सालों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद कुछ मुद्दों पर भाजपा अब भी कमजोर ही बनी हुई है। प्रदेश में जारी भाजपा की विकास यात्रा का, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहिष्कार इस बात का सबूत है कि मौजूदा सरकार से वो मतदाता खफा है जो असल में पोलिंग बूथ तक वोट देने पहुंचता है। शायद इसीलिए शिवराज सरकार साहित्य कला से लेकर महिला और युवाओं को आर्थिक लाभ लेकर लुभाने में जुटी है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस या अन्य सभी दलों का, भाजपा को घेरने के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही होगा। बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ को हथियार बनाकर राजनीतिक दल सत्ता की रेस में आगे निकलना चाहते हैं। यही एक मुद्दा है जिसे भाजपा अपना हथियार नहीं बना पा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अब कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किसानों को अपनी सीढ़ी बनाने के बजाय, ऐसा मुद्दा तलाशना चाहेगी जिसका भाजपा के पास कोई तोड़ न हो।

विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा के लिए जीत का मुद्दा पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज हो सकते हैं, वहीं कांग्रेस का मुख्य दांव केवल बेरोजगारी के रास्ते युवाओं पर ही सधा होगा। और इस बार भाजपा को घेरने के लिए और सत्ता तक अपना रास्ता बनाने के लिए कांग्रेस इस एक मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी। जो उन्हें जीत की सीढ़ी तक ले जाने का काम करेंगे।

2023 में होने वाले चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल की तरह हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। भाजपा की कोशिश होगी कि वह मोदी लहर बरकरार का संदेश देने में कामयाब रहे। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की कोशिश होगी कि वे 2024 से पहले भाजपा को हराने का संदेश दे सके। आज के समय में विपक्ष में एकजुटता की कमी दिखने के बावजूद भाजपा के लिए उत्साहजनक वातावरण नहीं बना हैं। मप्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तीन राज्य जहां चुनाव करीब हैं और भाजपा अपने लिए मुश्किलें देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही। वजह भी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय नहीं। मप्र में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 80 से कम ही रहेंगी। और इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री फेस ही नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा।

बात करें मप्र की तो यहां 2003 से लगातार भाजपा की सरकार है। बीच में 2018 में 15

हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति मप्र में न हो?

भाजपा के सामने एक डर ये भी है कि टिकट कटने से पार्टी को नुकसान न हो, कहीं हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति मप्र में न हो? कांग्रेस की बात करें तो सिंधिया के जाने के बाद पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि गुटबाजी में कमी आई है। हां, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में थोड़ा मतभेद जरूर हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को सहारा सत्ता विरोधी लहर का है। अब देखना यह होगा कि जनता को यह कितना समझ में आता है। बताया जाता है कि मप्र में करीब दो दशक से शिवराज सिंह चौहान सरकार को देख नई पीढ़ी यानी नए वोटरों को लग सकता है कि इस बार सरकार बदलकर देखो।

कर्नाटक में भाजपा के लिए कठिन चुनौती

कर्नाटक में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। 2018 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। बीएस येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने। 2021 में भाजपा ने चेहरा बदल दिया और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने। सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए सत्ता बचाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हाल ही में फरवरी में नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुए। 2 मार्च को आए नतीजों में त्रिपुरा-नगालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला। मेघालय में उसने सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी के साथ गठबंधन कर लिया। यानी तीनों राज्यों में पार्टी सरकार में है। इसके बावजूद पार्टी की ग्रोथ रुकी हुई है। अगर 2013 से देखें, जब केंद्र में पीए की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा में भाजपा का वोट शेयर 2 प्रतिशत से भी कम था। 2018 में मेघालय में पार्टी का वोट शेयर 10 प्रतिशत, नगालैंड में 15 प्रतिशत और त्रिपुरा में 44 प्रतिशत पर पहुंच गया। तब तक भाजपा केंद्र सरकार में 4 साल पूरे कर चुकी थी। 5 साल बाद यानी 2023 में भाजपा मेघालय की 60 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीती। 2018 में पार्टी 47 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब भी उसे 2 सीटें मिली थीं। तब वोट शेयर 9.6 प्रतिशत था और अब 9.33 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मेघालय में भाजपा खुद को आगे नहीं बढ़ा सकी।

महीने के लिए कांग्रेस को सत्ता मिली थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने लेकिन जल्द ही सियासी खेल हो गया। करीब 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मप्र के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के सियासी हालात के बारे में बताया जाता है कि हाल ही में भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ है। इसमें पता चला है कि 30 फीसदी सीटों पर भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है जबकि 30 फीसदी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है। बाकी 49 फीसदी सीटों पर कांटे की टक्कर दिख सकती है। ऐसे में भाजपा के लिए मप्र में कमल खिलाना पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा के सामने बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। बताया जाता है कि भाजपा के अंदरखाने यह चर्चा चल रही है कि राज्य में पार्टी का नया चेहरा कौन होगा? बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में भाजपा मुख्यमंत्री का अपना फेस बदल सकती है।

दिलचस्प यह है कि जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, उस पर पार्टी के भीतर ही आम सहमति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आए। केंद्र में उन्हें काफी तवज्जो मिली। मंत्री पद मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी भी बढ़ी। हालांकि मप्र में शिवराज के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम पर आमराय नहीं है। भाजपा मप्र में भी गुजरात फॉर्मूला लागू करने की प्लानिंग कर रही है। यहां भी 35-40 फीसदी विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। नेताओं को शायद पहले ही एहसास हो गया है और इसलिए बहुत से नेता अभी से पैंतरे अपना रहे हैं। ज्ञात रहे कि शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 30 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 तक लगातार 13 साल 17 दिन तक वे मुख्यमंत्री रहे। फिर करीब डेढ़ साल कांग्रेस की सरकार रही और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 2020 से एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज के पास आ गई। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 16 साल हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोई भी इतने समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है।

भाजपा के लिए मप्र से ज्यादा मुश्किल वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यहां वह सत्ता में नहीं, बल्कि विपक्ष में है। राज्य में वापसी के लिए भाजपा ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। तीन बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी पार्टी की नजर है, लेकिन भाजपा अब तक कांग्रेस के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग हर वर्ग के लिए स्कीम अनाउंस कर चुके हैं, इन्हें लागू भी कर दिया गया है। कर्जमाफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक इसमें शामिल है। यहां भाजपा के लिए चुनौती मुख्यमंत्री फेस की भी है। कोई नहीं जानता कि भाजपा जीती, तो मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है, इसलिए भाजपा किसी पिछड़ा वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास कार्ड खेल रही है। 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 और भाजपा के पास 14 सीटें हैं। हाल में हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस जीती है।

कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा 20 जुलाई 2019 से सत्ता में है। इन 4 साल में उसे एक बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। 28 जुलाई 2021 से यहां बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में फरवरी में आरएसएस ने एक सर्वे रिपोर्ट भाजपा को सौंपी है। इसमें उसे 70 से 75 सीटें जीतते बताया गया। बहुमत के लिए 113 सीटें जरूरी चाहिए। भाजपा की हालत ऐसी है कि जिन बीएस येदियुरप्पा को पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था और जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, अब उनके भरोसे ही इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जिनसे पता चला कि मौजूदा मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदलने में नाकाम रहे हैं।

भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। करप्शन यहां बड़ा मुद्दा है। 3 मार्च को भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। उनके बेटे को लोकायुक्त ने 40 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इससे पार्टी और ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बदल पा रही है। अब येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी बनाकर कैंपेन किया जा रहा है। येदियुरप्पा लिंगायत वोटों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन अकेले पूरे राज्य में भाजपा को नहीं जिता सकते। मुख्यमंत्री की रैलियों में लोग नहीं पहुंच रहे। प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार अभियान बहुत आक्रामक है। वह करप्शन के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। ज्ञात रहे कि 2018 में काफी जद्दोजहद के बाद भाजपा सत्ता में आई थी। कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

● **विपिन कंधारी**

खुली सुरक्षा एजेंसियों की पोल

रसूखदारों के लिए काम करता था महाठग

जेड प्लस सिक्योरिटी में घूमने वाले महाठग किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। उससे पूछताछ में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों को पता चला है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण वहां खास लोगों के लिए जमीनें और बागान तलाशने में जुटा था। इन रसूखदारों में कुछ कारोबारी, नेता और शीर्ष अफसर हैं। वहीं, गांधीनगर से नई दिल्ली तक 5 पावरफुल किरदार ऐसे हैं, जो किरण को हर तरह की मदद मुहैया करा रहे थे। जांच एजेंसियां अभी रसूखदारों के नाम बताने से बच रही हैं। गांधीनगर के एक बड़े होटल में पिछले साल सितंबर में एक खास मीटिंग में इस ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया था। इसी बैठक में पांचों पावरफुल किरदारों ने किरण को कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाकर काम की जमीनें और सेब के बागान स्कैन करने का टास्क सौंपा। ये भी तय किया गया कि घाटी में निवेश के लिए बड़े ग्राहकों को भी तलाशा जाए, ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा डील कराई जा सकें। किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि दक्षिणी कश्मीर में सेब के बागान खरीदने के लिए पार्टियां ढूंढ़ने का काम किरण को सौंपा गया था। किरण 27 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर पहुंचा। उसे बारामूला, शोपियां और पुलवामा जैसे सेंसेटिव इलाकों में जाना था।

एक तरफ भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक चीन को लगातार चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक महाठग ने भारत की सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलीजेंस की पोल खोलकर रख दी है। ठग चार महीने से खुद को पीएमओ का एडिशनल सेक्रेटरी बताकर सरकार की सारी सुविधाएं लेता रहा। जेड प्लस सुरक्षा भी पा गया। बुलेट प्रूफ एसयूवी भी हथिया ली और सरकारी अफसरों पर धौंस जमाता रहा। आखिर पकड़ा गया। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। है गुजरात का और नाम है किरण पटेल। सवाल यह उठता है कि चार महीने तक उससे किसी ने परिचय पत्र नहीं मांगा, आईडी कार्ड नहीं देखा और सबके सब उसकी बातें मानते गए, उसे तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराते गए, क्यों? अक्टूबर-नवंबर 2022 से वह अफसर के तौर पर सक्रिय था, मार्च में पकड़ा गया। तब तक हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? कद-काठी ठीक-ठाक थी और दिखने में भी रौबदार। लेकिन क्या किसी भी राज्य का प्रशासन, पुलिस, किसी को भी केवल कद-काठी देखकर अफसर मान लेते हैं?

कश्मीर में वह ठग जाने कितने खुफिया राज इकट्ठा कर गया होगा, कितनी सरकारी फाइलें उसने देख ली होंगी, कोई नहीं जानता। जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उसने अफसरों के साथ कई मीटिंग्स भी कीं। तब भी अफसरों ने उसे पहचाना नहीं। उससे कोई पूछताछ नहीं की। अगर वो सही में पाकिस्तान या किसी अन्य देश का जासूस होता तो क्या होता? कितनी संवेदनशील जानकारियां वो दूसरे देशों को भेज सकता था। वैसे तो हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, सजग खुफिया तंत्र की, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो पता चलता है, हमारे अफसर कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं। इतना ही नहीं, वह जब भी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाता, अपने ट्विटर हैंडल पर वहां के वीडियो भी पोस्ट करता रहा। कई वीडियो पड़े हैं। उनसे भी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया। आखिर पीएमओ का अफसर ट्विटर हैंडल पर वीडियो क्यों डालेगा भला?

हालांकि खुफिया एजेंसियों ने ही इस ठग के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस को अलर्ट भेजा और तब जाकर वहां की सीआईडी ने श्रीनगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दस दिन पहले ही हो चुकी थी लेकिन इसे उजागर अब किया गया है। लेकिन खुफिया एजेंसी को अगर चार महीने बाद सुराग लगे तो फिर ऐसी एजेंसियों का मतलब ही क्या रह जाएगा? निश्चित तौर पर इस ठग ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सारी पोल खोलकर रख दी है।

जम्मू-कश्मीर में फर्जी पीएमओ अफसर की मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि 2 मार्च को गुजरात के ऐसे ठग को गिरफ्तार किया गया, जो खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं वह जेड प्लस सिक्योरिटी, बुलेटप्रूफ एसयूवी के साथ चलता था और हमेशा फाइव स्टार होटल में रुकता था। पुलिस ने कहा कि ठग को सुरक्षा मुहैया कराने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसकी मदद करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा।

गुजरात के रहने वाले ठग का नाम किरण पटेल है। पीएमओ का अधिकारी बनकर वह कई जगह की यात्राएं करता था। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 2 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसे श्रीनगर के फाइव स्टार होटल से रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी जब्त किए गए। इस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि पटेल के खिलाफ गुजरात में पहले से तीन केस दर्ज थे। ठग किरण पटेल के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस को खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी। इस पर एसएसपी श्रीनगर ने उसे पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। ठग को गिरफ्तार करने के बाद 15 दिन तक मामले को सीक्रेट रखा गया, ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके। सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ ने जम्मू-कश्मीर में पिछले दो साल में हुए सभी जमीन सौदों की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहां, कितनी जमीनों के सौदे हुए या उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, उससे जुड़े लोगों के बैकग्राउंड क्या हैं, इसकी जानकारी निकाली जाएगी। ये सभी रिपोर्ट अगले 15 दिन के अंदर पीएमओ भेजने को कहा गया है।

● राजेश बोरकर

अपराधियों की सैरगाह बनीं जेलें

जेलें किसलिए होती हैं? स्वाभाविक सी बात है अपराधियों को कैद में रखने के लिए, ताकि वे सभ्य समाज के लिए खतरा न बनने पाएं। इसीलिए जेलों को बंदी सुधारगृह कहा जाता है। संभव है कभी जेलों में बंद कैदी सुधर जाते हों, लेकिन पिछले कुछ समय से यह धारणा प्रबल हुई है कि अपराधी जेल जाने के बाद और बड़े अपराधी बन जाते हैं। यह धारणा यही बताती है कि जेलें अपने उद्देश्य में सफल नहीं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अपराधियों के लिए अय्याशी का अड्डा बनती जा रही हैं। रसूख वाले अपराधियों को जेलों में हर तरह की सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें जेल में बंद रहते हुए अपराध करने का अवसर भी मिल जा रहा है।

कहा जा रहा है कि प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड की साजिश जेल में ही रची गई। दिनदहाड़े अंजाम दिए गए इस कांड में गवाह उमेश पाल के साथ उनके दो सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। इस कांड की साचिश बरेली और अहमदाबाद की जेलों में रची गई। अहमदाबाद जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल को खत्म करने की साजिश रची। इस साजिश को उनके गुर्गों ने प्रयागराज में अंजाम दिया। अतीक और अशरफ जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में इसीलिए सफल रहे, क्योंकि जेल अधिकारियों ने ही उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई। इसी कारण बरेली जेल के जेलर समेत **6 कर्मी निलंबित किए गए हैं।** उनकी मदद से अशरफ जेल में दरबार लगाता था और अपने परिचितों से बिना किसी रोक-टोक मिलता था। एक तरह से बरेली जेल में जेल प्रशासन की नहीं, बल्कि हत्या, रंगदारी समेत एक दर्जन मुकदमों के आरोपित अशरफ की चलती थी। अभी यह नहीं पता कि अशरफ अपनी मदद करने के बदले जेल अधिकारियों को कितना पैसा देता था, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्हें अच्छा-खासा पैसा दिया जाता होगा।

यह इसलिए और आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के आरोप में जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, वार्डन आदि की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहां भी जेल प्रशासन का नहीं, बल्कि अब्बास अंसारी का सिक्का चल रहा था। वह अपनी पत्नी निखत बानो से जब चाहे तब मिलता था। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का इतना जुगाड़-जलवा था कि जब उसकी पत्नी उससे मिलने आती थी, तो जेल की बिजली काट दी जाती थी, ताकि वह सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो सके। उसके जेल से निकलते समय भी ऐसा ही किया जाता था। चित्रकूट जेल प्रशासन को नतमस्तक करने के लिए अब्बास ने जेल अधिकारियों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल आदि दिए थे। यह अंधेरगर्दी के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन इसमें हैरान होने की बात इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत समय पहले वोहरा कमेटी ने यह कह दिया था कि भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों और माफिया तत्वों ने अपनी समानांतर सत्ता कायम कर ली है। यदि योगी सरकार इस समानांतर सत्ता को ध्वस्त करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होती तो अब्बास अंसारी और उसकी चाकरी करने वाले जेल अधिकारियों का बाल बांका भी नहीं होता।

जैसे अब्बास अंसारी जेल अधिकारियों की मेहरबानी से हर तरह की सुविधाओं का उपभोग कर रहा था, वैसे ही एक समय उसका पिता मुख्तार अंसारी भी पंजाब की रोपड़ जेल में कर रहा था। मुख्तार पर केवल रोपड़ जेल प्रशासन ही नहीं, बल्कि तत्कालीन पंजाब सरकार भी मेहरबान थी। यहां यह भी अवश्य याद रखें कि इस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। 2019 में मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल से पंजाब लाने के लिए मोहाली में उसके खिलाफ कथित रूप से एक फर्जी एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर के बहाने उसे पंजाब लाकर रोपड़ जेल में रखा गया। मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार की मिलीभगत का पता इससे चलता है कि एफआईआर की जांच के नाम पर कुछ नहीं किया गया। मुख्तार ने भी जमानत की मांग नहीं की। वह रोपड़ जेल में जब चाहे तब अपनी पत्नी अफशां अंसारी से वैसे ही मिल सकता था, जैसे उसका बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी निखत बानो से मिला करता था।

● **अक्स ब्यूरो**

जेल में अय्याशी कर रहे कैदी

उप्र सरकार यह समझ चुकी थी कि मुख्तार को समस्त सुख सुविधाओं के साथ जेल में रखने के लिए ही रोपड़ जेल लाया गया है। उसके खिलाफ उप्र में दर्जनों मुकदमे थे। इनकी सुनवाई के लिए उप्र पुलिस ने जब-जब पंजाब पुलिस से मुख्तार को अपने हवाले करने को कहा, तब-तब किसी न किसी बहाने उसे मना कर दिया जाता। उप्र पुलिस ने कम से कम 25 बार मुख्तार को राज्य में लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। रोपड़ जेल के डॉक्टर मुख्तार को कभी अवसाद का मरीज बता देते, कभी मधुमेह का और कभी यह कह देते कि उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है। इस बहानेबाजी से तंग आकर उप्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां तब की पंजाब सरकार बड़ी बेशर्मी से यह दलील देने में जुट गई कि मुख्तार को उप्र पुलिस को क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। उसकी दाल नहीं गली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को उप्र पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया। कैदियों के जेल में अय्याशी करने का यह इकलौता मामला नहीं। सभी को पता होगा कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद जैन की तिहाड़ जेल में किस तरह मालिश होती थी और महाठग सुकेश किस प्रकार अपनी बैरक को ऑफिस का रूप देकर वीडियो कॉल करके लोगों को झांसा देता था।

भारी पड़ेगी कर्मचारियों की नाराजगी

2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान?

इस मामले में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के पीछे कांग्रेस के वचन-पत्र यानी घोषणा-पत्र की अहम भूमिका रही है। क्योंकि तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र में उन सभी समस्याओं को ग्राउंड में जाकर समझा था। इसके बाद अपने घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को कांग्रेस ने रखा। इसके बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल बाद रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लेकिन आज वही वर्ग फिर सड़कों पर है और सामने विधानसभा चुनाव है तो इसका कांग्रेस पार्टी चुनावी अभियान पर असर पड़ सकता है। हालांकि कोई खास नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस ने राज्य के किसानों को पकड़ कर रखा है। ये कांग्रेस के सबसे बड़े वोटर हैं।

एक काफी लोकप्रिय मुहावरा है- लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। इसका मतलब सही मौके का इंतजार कर वार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में माहौल भी ऐसा बना है कि आंदोलनकर्मी सरकार पर लगातार बरस रहे हैं। ये साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के लिए अपने वादे पूरे करने का आखिरी मौका है। इसलिए प्रदेशभर से आंदोलनकर्मी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भूपेश सरकार के बजट में सभी को कुछ न कुछ जरूर मिला। एक बेहतर छत्तीसगढ़ गढ़ने की भूपेश सरकार की शानदार कोशिश रही। लेकिन फिर भी सभी की मुरादें पूरी करना भूपेश बघेल के सामने बजट में सबसे बड़ी चुनौती थी। वैसे राजनीति के जानकार कहते हैं, इनकी मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए था। क्योंकि ये एक बड़ा वर्ग था, जिसे कांग्रेस को साध लेना था। कम से कम नियमित करने का वादा कर सकते थे।

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब साढ़े पांच लाख अनियमित कर्मचारी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5 लाख कर्मचारियों से करीब 30 लाख जुड़े हैं। वहीं इनके संबंधों को जोड़कर देखा जाए तो इनकी भूमिका से करीब 2 करोड़ वोट विपक्ष के खाते में जा सकता है। यही कारण भी है कि भाजपा इनके साथ खड़ी है। वह भी वादे के साथ अगर सत्ता में आई तो इन्हें नियमित करेगी। इधर, संघ ने निर्णय लिया है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के विरोध में गुप्त रूप से प्रचार करेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। ऐसे में जाहिर है कि ये वर्ग कहीं न कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम करेंगे। इसमें तमाम विभागों के संघ भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कर्मचारियों की निराशा को व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को कम से कम अपने जनघोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना था जिसमे उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ता प्रदान किया जाएगा किंतु अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया गया। पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत्ति प्रदान करने का भी वादा था पर यह भी पूर्ण नहीं हुआ। विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने का वादा था किंतु इसका तो उल्लेख ही बजट में नहीं किया गया। हम लगातार पूर्व सेवा गणना कर समस्त लाभ दिए जाने की मांग कर रहे है किंतु इसकी भी अनदेखी की गई है। दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवा बहनों से अनुकम्पा नियुक्ति का किया गया वादा भी पूर्ण नहीं किया गया। प्रदेश के समस्त कर्मचारी अत्यंत निराश हैं कि आज बजट में उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और प्रांतीय प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार का अंतिम बजट था, कर्मचारियों की विभिन्न अपेक्षाएं सरकार से थी किंतु वह सभी अधूरी रह गई जिससे कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। कम से कम जनघोषणा पत्र में किए वादों को पूर्ण करना था। उम्मीद जताते हैं कि मुख्यमंत्री यथासमय अनुपूरक बजट लाकर हमारी मांगों को पूर्णता प्रदान करेंगे। पर जो भी वादे पूरे किए जाने हैं जल्द ही किए जाने चाहिए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। प्रदेश के समस्त प्रांतीय, जिला, ब्लॉक पदाधिकारियों तथा समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग ने जल्द ही सभी मांग पूर्ण करने की मांग मुख्यमंत्री से की है।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के चुनावी साल में राज्य के बड़े वर्ग को इस बजट में बड़ा झटका मिला है। राज्य के लाखों अनियमित कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल राज्य में 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है। इनको कांग्रेस सरकार से बड़ी उम्मीद थी। ये कर्मचारी लंबे समय नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन बजट में अनियमित कर्मचारियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक गोपाल साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट हमारे जैसे कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। सरकार ने अपनी अंतिम बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान न कर इनके अधिकारों और सपनों को कुचलने का काम किया है। इसलिए हमारा सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए कहा कि इस बजट में 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी निराश हो गए हैं। उनमें बजट को लेकर आक्रोश है। चुनावी घोषणा पत्र के समय एक हाथ में गंगाजल और एक हाथ में चुनावी मेनिफेस्टो लेकर कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पहला साल किसान का होगा। दूसरा साल कर्मचारियों का होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में लिखित जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 2019 में ही प्रमुख सचिव, वाणिज्य और उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इस समिति की पहली बैठक 2020 में हुई थी। उन्होंने बताया कि इसमें शासन के सभी 44 विभागों से प्रदेश के अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन अब तक 38 विभागों से ही जानकारी मिली है। अभी 8 विभागों से जानकारी बाकी है इसलिए नियमितीकरण करने का समय बताना संभव नहीं है।

● रायपुर से टीपी सिंह

महाराष्ट्र में करवट ले रही राजनीति

महाराष्ट्र में आए उपचुनाव के नतीजों ने आगामी चुनावों में भाजपा को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। कसबा सीट पर 28 साल पुराना किला महाविकास अघाड़ी ने तोड़ दिया है। कसबा पेठ सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे, इन नतीजों की खास बात यह है कि भाजपा अपना परंपरागत वोट कसबा और चिंचवड, दोनों ही सीटों पर बचाने में सफल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिले-जुले गठबंधन के वोटों की बदौलत उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यह केवल महाराष्ट्र नहीं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उप्र के बाद 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहां हुई गड़बड़ देश के स्तर पर परेशानी का सबब बन सकती है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को दोनों उपचुनाव में 47 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े हैं। आमतौर पर इतने वोट किसी भी सीट पर निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काफी होने चाहिए। मगर एनसीपी, कांग्रेस के वोट और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की छिपी ताकत चिंता की लकीरें बढ़ाने का कारण बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू महाराष्ट्र में भी असर करता दिखाई पड़ रहा है और शिवसेना (उद्धव) का साथ छूटने के बाद अपने खुद के वोट बैंक में इजाफा करने में भाजपा काफी हद तक सफल भी रही है। बावजूद इसके महाविकास अघाड़ी का मजबूत किला भेदने में भाजपा असफल रही। यह भी कड़वा सच है कि उद्धव ठाकरे के बिछड़ने की कोई पूर्ति महाराष्ट्र में होती दिखाई नहीं दे रही। तभी एक के बाद एक उसे झटके लगते रहे हैं। विपक्ष में दूरियां बनाने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कार्रवाई का उतना फायदा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तीनों पार्टियों का मिलकर भाजपा को पछाड़ने का एकत्रित संकल्प राजनीतिक पटल पर कहीं ज्यादा कारगर दिखाई दे रहा है।

वैसे भी, पार्टी ने जबसे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुखिया बनाकर सरकार खड़ी की है, तब से राज्य में कोई निर्णायक राजनीतिक जीत दर्ज कराने में पार्टी असफल रही है। मई 2021 में पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट भाजपा ने झटकी थी। तबसे देगलूर (नांदेड़), कोल्हापुर उत्तर और अंधेरी (मुंबई) के विधानसभा उपचुनावों में पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। हाल में विधानपरिषद उपचुनाव में भी शिक्षक व ग्रैजुएट सीटों पर एकमात्र कोंकण शिक्षक सीट जीतने में सफल रही। इनमें भी नागपुर और अमरावती के गढ़ गंवाने की टीस उसे झेलनी पड़ी है। ताजा उपचुनाव में 28 वर्षों से गढ़ रही पुणे की कसबा पेठ विधानसभा सीट की हार पचाना आसान नहीं होगा। चिंचवाड़ सीट बच तो गई, मगर शिवसेना का बागी उम्मीदवार 42 हजार वोट न खींचता, तो मुश्किल बढ़ सकती थी। एनसीपी उम्मीदवार को दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी ने 32 हजार वोटों से हराया है। वैसे देखा जाए तो कसबा पेठ विधानसभा उपचुनाव का नतीजा बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। इस चुनाव में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं था कि केवल भाजपा ही क्यों सफल नहीं होगी, लेकिन यह आज स्पष्ट हो गया है। इसी तरह राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में हुए चुनावों में भाजपा की नाकामी का कारण पार्टी की गलत प्लानिंग है।

दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद भाजपा को कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। बावनकुले के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद स्थानीय स्वशासन चुनाव, शिक्षक स्नातक विधान परिषद, अंधेरी विधानसभा उपचुनाव, पुणे उपचुनाव हुए। उसमें हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वह हमें दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि बावनकुले प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हर फैसला बावनकुले नहीं ले सकते, इसमें कोई न कोई दखलंदाजी करता है। इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि फ्री होल्ड का फैसला नहीं लिया जा सकता। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले कुछ चुनाव बावनकुले के नेतृत्व में हुए थे और भाजपा नागपुर की सीट बरकरार नहीं रख पाई थी जो उसका गढ़ है। 5 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है और भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले की स्थानीय स्वशासन के चुनावों में नागपुर सीट जीतने में नाकामी उन्हीं की वजह से है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि बावनकुले का प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद प्रदेश के कई नेताओं पर कोई पकड़ नहीं है। हाल ही में हुए कसबा और चिंचवाड़ उपचुनाव में भाजपा ने प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों जैसे शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारा था। सारी ऊर्जा दांव पर लग गई लेकिन एक जगह जो कई वर्षों से हाथ में थी वह खो गई। कसबा की गरिमामयी सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया।

● **बिन्दु माथुर**

महाविकास अघाड़ी पार्टी ने कसी कमर

महाविकास अघाड़ी पार्टी में शामिल तीनों दल राज्य में हर जगह भाजपा को मात देने के लिए कमर कस चुके हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण शिक्षकों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के साथ-साथ चिंचवाड़ और कसबा उपचुनावों में भी देखने को मिला। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां भाजपा को हराने और राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए आपस में समन्वय बनाकर लड़ रही हैं। लेकिन अगर चिंचवाड़ में राहुल कलाटे उम्मीदवार नहीं होते तो भाजपा उस सीट को भी गंवा देती। ध्यान देने योग्य बात है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद माना जा रहा था कि विपक्ष पूरी तरह बिखर जाएगा, लेकिन सरकार गिरने के बाद गठबंधन और मजबूत हो गया है। कुछ समय पूर्व 16 दिसंबर को आजाद मैदान में महाविकास अघाड़ी ने हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले भी शामिल हुए थे। रैली में सभी नेताओं ने कर्नाटक-महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद और कोश्यारी को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह रैली महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन था, जिसकी कामयाबी अब दिख रही है।

चौथी बार सीएम का सपना...!

राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ महीनों का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस में चल रहा नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा भी खत्म सा हो गया है। यह तय हो गया है कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट ने भी अब मान लिया है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का समय निकल चुका है। इसीलिए उनकी नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी बंद हो गई है। अब सचिन पायलट कहने लगे हैं कि पार्टी के सभी लोगों की एकजुटता से ही अगला विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मालूम है कि सरकार चाहे कितने ही विकास के कार्य करवाए। जनता हर 5 साल के बाद सत्ता बदल देती है। राजस्थान के लोगों का मानना है कि सत्ता बदलने से प्रदेश में और अधिक तेजी से विकास कार्य होते हैं। अशोक गहलोत ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सचिन पायलट को तो मात दे दी है। मगर अब उनके समक्ष विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं। जहां उन्हें सभी विपक्षी दलों को परास्त कर फिर से सरकार बनानी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी हर चाल बहुत सावधानी से चल रहे हैं। उन्हें पता है कि एक तरफ उन्हें भाजपा सहित अन्य विरोधी दलों से मुकाबला करना होगा। वही पार्टी में व्याप्त अंदरूनी गुटबाजी को भी काबू में कर उन्हें चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाना होगा। तभी उनका चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा।

गहलोत को पता है कि कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते आम जनता में पार्टी के प्रति अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अशोक गहलोत प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत के सोच की झलक इस बार राजस्थान के आम बजट में भी देखने को मिली है। गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के **अंतिम बजट** को पूरी तरह आमजन का विकासोन्मुखी बजट बनाया है। बजट में प्रदेश के आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके हित की बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका गहलोत पूरा राजनीतिक लाभ उठाएंगे। गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं, विकलांगों, अनाथ बच्चों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर उन्हें बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है। जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री बनते ही गहलोत ने उक्त सभी लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की थी। अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही साथ ही 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परियोजना को केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर पूरा करवाने की बात कही थी। मगर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को आज तक अपने हाथ में नहीं लिया है। इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े जोर-शोर से उठा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर आदि 13 जिलों में राजस्थान की एक तिहाई से अधिक आबादी रहती है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, साथ ही उन्हें आने वाले लंबे समय तक पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इन 13 जिलों में विधानसभा की 83 सीट आती हैं। जिनमें से अभी कांग्रेस के पास 49 और भाजपा के पास 25 सीटें हैं। राजनीतिक रूप से भी इन 13 जिलों में अभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री गहलोत इस नहर परियोजना के मुद्दे पर इस क्षेत्र में अपनी पार्टी की पकड़ को और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने इस परियोजना को गति देने के लिए हाल ही में 14 हजार 200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

गहलोत सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में भी इस परियोजना के लिए 9 हजार 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी। इस तरह प्रदेश सरकार इस परियोजना पर अब तक 23 हजार 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर चुकी है। इससे उक्त परियोजना में नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध, रामगढ़ एवं महलपुर बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज, मेज एनीकट तथा गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने तथा बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकेंगे। इसके साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर बढ़ाने तथा 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा वर्ष 2040 तक जयपुर, अजमेर, टोंक जिले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं तथा जयपुर जिले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16.82 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के कार्य किए जा सकेंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

लोगों को चुनावी राहत

प्रदेश के गरीब लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत ने इस बार के बजट में 19 हजार करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें उज्ज्वला योजना में शामिल प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने व प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े एक करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके तहत हर पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिस पर राज्य सरकार 3 हजार करोड़ खर्च करेगी। गहलोत की यह योजना 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह व कृषि उपभोक्ताओं को 2 हजार यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार की सुविधा देना शामिल है। प्रदेश में सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में युवाओं से अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह बेरोजगार अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। बेरोजगार युवकों के लिए आगामी वर्ष में 1 लाख नई भर्तियां करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी लुभाने का काम किया है।

बुलडोजर भी नहीं रोक पा रहा अपराध

अपराध को रोकने के लिए यदि अपराध का सहारा लेना पड़े, तो इसे उचित नहीं माना जा सकता। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। बुलडोजर नीति पर कुछ लोग यही कह रहे हैं। मगर कुछ लोग प्रसन्न हैं कि योगी राज में अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। होली पर बुलडोजर बाबा से लेकर राम राज्य के गुणगान वाले गाने बजाकर लोग अति प्रसन्न हैं। मगर इन लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि उप्र की योगी सरकार जिस अपराध को समाप्त करने के लिए लगातार हुंकार भर रही है, वो अपराध अगर समाप्त हो रहा होता, तो हर दिन अपराधों की दर्जनों खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां नहीं बन रही होतीं।

जघन्य हत्याकांड जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के लोहिंदा बाजार में घटी घटना ने किसका दिल नहीं दहला दिया होगा, जहां बदमाशों ने एक पंचर मिस्त्री की हत्या कर उसकी पत्नी की दोनों आंखें निकाल लीं। विवाद दुकान के सामने बोलेरो खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ। पंचर जोड़ने वाले छोटे से दुकानदार कमालुद्दीन (45) ने बदमाशों से उसकी दुकान के आगे से बोलेरो हटाने को कहा। बस बदमाशों ने योगी के राम राज का नमूना पेश करते हुए पहले दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी, फिर उसे गोली मार दी। इस बीच थोड़ी सी तू-तू, मैं-मैं हुई, जिसमें बीच-बचाव के लिए उतरी पंचर मिस्त्री की पत्नी की **आंखें फोड़ने का घिनौना कृत्य** करते हुए बदमाशों के हाथ नहीं कांपे और न बाजार में किसी की हिम्मत हुई कि वह बदमाशों का विरोध कर सके। इतने पर भी बदमाशों का जी नहीं भरा, तो उन्होंने पंचर मिस्त्री की आठ महीने की बेटी को उठाकर पटक दिया। प्रश्न यह उठता है कि कुछ दिन पूर्व माफिया को मिट्टी में मिलाने की घोषणा विधानसभा से करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इन बदमाशों को भी मिट्टी में मिलाएंगे? सरकारी धमकी बना बुलडोजर उप्र में बुलडोजर कानून के चर्चे हैं। एक प्रकार से बुलडोजर सरकारी धमकी बन चुका है। प्रश्न यह उठता है कि क्या अब अपराध रोकने के लिए बुलडोजर कार्रवाई कानूनी रूप से उचित है? क्या अपराधियों के अतिरिक्त विरोधियों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है? योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप तो ऐसे ही लगते रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके साथी जफर की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों के घरों पर बुलडोजर उप्र सरकार ने चला रखा है। आरोप है कि अपराधियों एवं आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार न्यायालय की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझती है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री जेपीएस राठौर ने भी अपराधियों को संकेतों में कानपुर के विकास दुबे कांड की याद दिलाई। उन्होंने चेतावनी की तरह उमेश हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर होने के संकेत दिए। मंत्री राठौर ने कहा कि माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोजकर लाएंगे। जब ये पकड़े जाएं, तो गाड़ी में बैठते समय हाय-तौबा न करें। ऐसा न हो कि ड्राइवर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। प्रश्न यह उठता है कि क्या अनर्गल भाषा के इस्तेमाल से अपराध रुक सकते हैं? आपराधिक आंकड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन प्रदेश में अपराधों के कम होने के दावे करके अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, मगर जब भी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े सामने आते हैं, उन्हें गलत बताया जाता है। 2022 के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों की मानें, तो उप्र में महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ी है। हालांकि महिला एवं साइबर अपराधों के आरोपियों से निपटने में उप्र पुलिस का स्थान पहला है। वहीं सन् 2022 की अपेक्षा सन् 2019, 2020 एवं 2021 में अपराधों में कमी देखी गई।

विदित हो कि पहली बार उप्र की सत्ता जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई में 81 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। वहीं सन् 2017 में 28 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सन् 2019 में 34 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। सन् 2020 में 26 अपराधी मारे गए। सन् 2021 में 26 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया एवं सन् 2022 में 14 अपराधी मुठभेड में मारे गए। वहीं अगर इस वर्ष दो महीने एक सप्ताह में 9 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक 63 अपराधी मेरठ में एनकाउंटर में मारे गए हैं। उप्र में अब तक कुल मुठभेड़ों में 1416 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मगर प्रदेश पुलिस ने पिछले 6 वर्षों में 23,000 से भी अधिक अपराधियों को जेल भी भेजा है। मगर हाथरस कांड के आरोपियों का बरी हो जाना इस ओर संकेत करता है कि उप्र में जघन्य अपराध के आरोपी आराम से बरी भी होते हैं। लखीमपुरखीरी के मुख्य आरोपी नेता पुत्र को लेकर भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि अगर सत्ता में रहकर कोई अपराध करता है, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज

प्रश्न यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों में भी भेद करते हैं? क्या वे अपराधियों को एक समान दृष्टि से देखते हैं? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर संकेत करते हुए कहा था कि एक पार्टी अपराधियों को पालती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम जल्द सामने आएंगे। जो ये अपराधी हैं, माफिया हैं, पाले किसके द्वारा गए हैं? जिस माफिया के खिलाफ परिवार ने आरोप लगाए हैं, क्या सपा ने उन्हें सांसद नहीं बनाया था? आप अपराधियों को माल्यार्पण करेंगे, उन्हें प्रश्रय देंगे, गले का हार बनाएंगे और फिर दोषारोपण भी करेंगे? मगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) एवं उप्र इलेक्शन वाच ने योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित 53 मंत्रियों में से 45 की पड़ताल में पाया कि इनमें 22 अर्थात् 49 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अपने ही जाल में उलझ गए सुशासन बाबू

अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने रातोंरात एनडीए का दामन छोड़ राजद का हाथ थाम लिया और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी। कांग्रेस को साथ लेकर महागठबंधन की सरकार बना ली। तब उन्हें उम्मीद थी कि उनको विपक्ष से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आसानी से बना लिया जाएगा। इसमें उनके राजनीतिक गुरु रहे लालू प्रसाद यादव भरपूर मदद करेंगे। उनकी साफ छवि के पीछे कदमताल करती हुई कमजोर पड़ी कांग्रेस पार्टी आसानी से खड़ी हो जाएगी। इस तरह विपक्ष का सिरमौर बनकर वह भाजपा को महज 100 सीटों के अंदर समेटकर सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन राजनीति तो जोखिम का खेल है।

नीतीश कुमार ने जोखिम तो उठाया, लेकिन जोखिम का मतलब जरूरी नहीं कि बिसात पर जो दांव चला जाए वह सटीक ही बैठ जाए। ऐसी ही कुछ गड़बड़ विपक्षी एकता को लेकर होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार के सपने भंग होते दिख रहे हैं। बिहार में भाजपा ने मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुई ज्यादती को मुद्दा बना रखा है। उत्साही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चेन्नई जाकर इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की जन्मदिन की पार्टी में शिरकत की है। नीतीश आशंका से चौंक उठे हैं। उन्होंने तेजस्वी की गैर मौजूदगी में भाजपा नेताओं के साथ विधानसभा कार्यालय में बंद कमरे की बैठक की है। तेजस्वी की व्यक्त राय से इतर जाकर उन्होंने भाजपा की राय के अनुकूल काम करना शुरू किया है। इसे लेकर बिहार की राजनीति में फिर से बदलाव का जिक्र होने लगा है।

राजनीतिक उथलपुथल मचाने में पाटलिपुत्र धुरी रही है। 2013 में एक चर्चा यह भी थी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए गए नरेंद्र मोदी को उप्र में काशी की जगह बिहार में भाजपा के लिए अजेय रही पटना की सीट से लोकसभा पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए तैयार होने के बजाय एनडीए छोड़ यूपीए का दामन थामना कबूल कर लिया। अब तक विधानसभा तक का चुनाव लड़ने से बचने वाले नीतीश कुमार अपनी तिकड़म के बल पर 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं। विपक्ष की गणित से इन सीटों के साथ कांग्रेस संग लालू-नीतीश की जोड़ी का असर पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उप्र में फलीभूत हो सकता है। झारखंड से 14 सीटें हैं। यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने भाजपा का हौंसला पस्त कर रखा है। भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े इल्जाम के बावजूद झारखंड की सरकार को बर्खास्त कर पाना भाजपा के लिए दिवास्वप्न बना हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार कोटे की राज्यसभा सीट जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को देकर पर्याप्त इशारा कर रखा है। पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। इन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर हाल में जीतना चाहती हैं। कांग्रेस से उनका छत्तीस का आंकड़ा है। कांग्रेस अगर विपक्षी एकता के लिए त्याग करती है, तब ही तृणमूल उसमें फिट बैठेगी। शायद यही नीतीश कुमार के लिए मुस्कुराने की वजह रही होगी।

इसी तरह सबसे बड़े राज्य उप्र से 80 सांसद आते हैं। प्रतिपक्ष में समाजवादी पार्टी है। जेडीयू का समाजवादी पार्टी में विलय करने का फैसला पुराना है। वह नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की धुरी बनाए जाने के फैसले के साथ अमल में आ सकता है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा को हाशिए पर धकेलकर अपनी जगह बनाई है। पारिवारिक संबंधी लालू प्रसाद यादव यदि उन्हें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने में जुटने के लिए कहें, तो संभव है कि बात बन जाए। समाजवादी एकता के आसरे नीतीश कुमार को ओडिशा में नवीन पटनायक और कर्नाटक में देवगौड़ा को पटा लेने की उम्मीद है। ओडिशा से लोकसभा के 21 सांसद हैं। उसका विस्तार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पड़ोसी मप्र तक में भाजपा को बांधकर मुश्किल में फंसा सकते हैं। छत्तीसगढ से 11 और मप्र से लोकसभा की 29 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र के भीष्म पितामह शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस को अंदरूनी चुनौती दे रखी है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में एनसीपी कांग्रेस को साफ करने में भाजपा की मदद कर रही है या यूपीए का पार्टनर बन कांग्रेस के साथ है, यह राजनीति का घाघ से घाघ जानकार भी बता नहीं सकता। पवार की तिकड़म वाली राजनीति से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे समान रूप से परेशान हैं। इस दुष्चक्र में फंसी कांग्रेस विपक्ष से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी किसी गैर कांग्रेसी लड़ाके को बना सकती है। नीतीश कुमार की उम्मीद को इससे बल मिलता है, लेकिन उम्मीद पर अमल के फैसले के साथ ही नीतीश कुमार राजनीतिक झंझावात में फंसे नजर आ रहे हैं। एक तो जबसे नीतीश कुमार ने पाला बदला है कांग्रेस की ओर से उन्हें अपेक्षित तवज्जो नहीं मिल रही है। न ही विपक्ष के नेता पहले की तरह उनको भाव दे रहे हैं और न ही भरोसेमंद मान रहे हैं। विपक्षी एकता की नाउम्मीदी के बीच कांग्रेस ने खुद में उम्मीद जगाने की कोशिशें तेज कर रखी है।

● **विनोद बक्सरी**

प्रधानमंत्री की इच्छा पालने वाले नीतीश अकेले नहीं

साफ है कि 2024 में विपक्ष से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने की इच्छा पालने वाले नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं। बल्कि अब एक अनार सौ बीमार वाली हालत है। भला पहली बार कठिन मेहनत करते नजर आ रहे राहुल गांधी को पीछे करने हेतु वंशवादी कांग्रेसी कैसे मान सकते हैं। मौका आने पर दावेदारी में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, के चंद्रशेखर राव, एमके स्टालिन, एचडी देवगौड़ा या कोई अन्य राजनेता चुप क्यों बैठेंगे। वह भी तब जब संयुक्त मोर्चा की सरकार में जनसमर्थन वाले देवगौड़ा को हटाकर आई के गुजराल को और 40 सांसदों के समर्थन से चार महीने तक चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू छोड़ना नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा सियासी झटका है? फिलहाल विपक्ष का नेता बनने के लिए उभरे अनेकों नामों के बीच अपने आप को इकलौता मानने वाले नीतीश कुमार का नाम गुम होता जा रहा है। अब तो उन्हें भी लगने लगा है कि विपक्ष की अगुवाई करने की उनकी मंशा कहीं धरी की धरी न रह जाए।

पाकिस्तान के हाल बेहाल

पाकिस्तान इस समय दक्षिण एशिया का सबसे गया बीता देश बन गया है। यूं तो श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश की भी हालत अच्छी नहीं है। इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इस कदर छलांग मार रही है कि आम लोगों का रोजाना का भरण-पोषण भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल 275 रुपए लीटर, गेहूं 125 रुपए किलो, टमाटर 250 रुपए किलो और चिकन 750 रुपए किलो हो गया है। लोग घी-तेल की छीनाझपटी पर उतारू हो गए हैं। सरकार ने अपने लघु बजट में नागरिकों पर तरह-तरह के नए टैक्स ठोक दिए हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार भी लगभग खाली हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज देने को तैयार है लेकिन उसकी शर्त है कि पाकिस्तान की सरकार पहले अपनी आमदनी बढ़ाए। कर्ज में डूबी सरकार का अब एक ही नारा है- मरता, क्या नहीं करता? वित्तमंत्री इशाक डार ने (जो कि मियां नवाज शरीफ के समधी हैं) जो अभी पूरक बजट पेश किया है, उसमें **170 बिलियन रुपए** के नए टैक्स उगाहने का वादा किया है। इधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतने भयंकर संकट में है यानी वह किसी युद्ध की स्थिति से भी बदतर है लेकिन पाकिस्तान की राजनीति का हाल बिल्कुल बेहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इमरान की गिरफ्तारी की खबर आंधी की तरह लाहौर को घेरे हुए है। इमरान समर्थक हजारों लोग उनके घर पर जमा हो गए थे, ताकि उन्हें कोई गिरफ्तार न कर सके। सरकार का जितना ध्यान अपने देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उबारने में लगा है, उससे ज्यादा इमरान के साथ दंगल करने में लगा हुआ है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस्लामाबाद को बलूच, पठान और सिंधी लोग घूंसा दिखाने लगे हैं। वे पाकिस्तान से अलग होने का नारा लगाने लगे हैं। जिन तालिबान को टेका देने में पाकिस्तान की फौज ने जमीन-आसमान एक कर दिए थे, वे ही तालिबान अब डूरंड लाइन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि जिस चीन पर तकिया था, वही अब हवा देने लगा है। चीन ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। चीन अपनी रेशम महापथ योजना के तहत पाकिस्तान में सड़कें, रेल, पाइपलाइन और बंदरगाह बनाने पर लगभग 65 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। लेकिन चीनी कंपनियां कुछ भी माल भेजने के पहले अग्रिम भुगतान की मांग कर रही हैं। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। वह अग्रिम भुगतान कैसे करे? चीनी नागरिकों की हत्या से भी चीन नाराज है। पाकिस्तान को अन्य मुस्लिम देश भी उबारने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि इस मौके पर शाहबाज सरकार में दम हो तो पाक-भारत व्यापार फिर से शुरू करे और मोदी से मदद मांगे तो एक पंथ, कई काज सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहा पाकिस्तान कंगाल हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग दो वक्त ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। आर्थिक संकट का असर अब पाकिस्तान की सेना पर भी पड़ रहा है। सेना के जवानों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। जवानों के लिए होने वाली फूड सप्लाई कम हो गई है।

पाकिस्तान में सेना सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से यहां अधिकतर समय **प्रत्यक्ष और परोक्ष** रूप से सेना का शासन रहा है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि उसे अपने सैनिकों को खाना खिलाने में भी परेशानी हो रही है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रहीं हैं, जिनके अनुसार पाकिस्तान की सेना को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कटौती हो रही है। इसके चलते मेस में जवानों के लिए भोजन की कमी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ फील्ड कमांडरों ने जनरल हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफिस को पत्र लिखा है, जिसमें सेना के सभी मेस में सैनिकों के भोजन की आपूर्ति में कटौती की बात की गई है। क्वार्टर मास्टर जनरल ने लॉजिस्टिक स्टाफ के प्रमुख और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ खाद्य आपूर्ति और रसद के मुद्दों पर चर्चा की है। इस मुद्दे को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सामने भी उठाया गया है। महंगाई बहुत अधिक बढ़ने और स्पेशल फंड्स में कटौती के चलते पाकिस्तान की सेना अपने जवानों को दो वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से चुनौती मिल रही है। इसके चलते अफगानिस्तान से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। डीजी-मिलिट्री ऑपरेशंस ने कहा है कि सेना रसद और आपूर्ति में अधिक कटौती करने की स्थिति में नहीं है। सैनिकों को अधिक भोजन और विशेष धन की जरूरत है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पीओके के लोगों में पाकिस्तान को लेकर भारी नाराजगी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उठ रहा है। बता दें कि जिनेवा में 52वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई और आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठे। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने जॉन नोक्स सेंटर में इस बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने पीओके में बढ़ रहे कट्टरपंथ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, लोगों को अगवा करने जैसे मुद्दों पर चिंता जाहिर की। यूकेपीएनपी के अध्यक्ष अमजद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब है। पाकिस्तान पूरे इलाके पर कब्जा किए हुए है और वहां अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिन्हें स्थानीय लोगों से कोई हमदर्दी नहीं होती। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान धीरे-धीरे पीओके की संस्कृति और इतिहास को खत्म कर रहा है। आरोप है कि पाकिस्तान ने कई किताबों, नक्शों पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों को अपने इतिहास के बारे में पढ़ने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों का उत्पीड़न कर रही है।

एक साल में कौन जीता-कौन हारा!

एक साल से ज्यादा समय से रूस-यूक्रेन जंग जारी है। कहां तो उम्मीद की जा रही थी कि रूस युद्ध को 24-48 घंटे में निपटा देगा और अब इसका अंत ही दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की अध्यक्षता में दुनियाभर की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई लेकिन रूस और चीन में साझा बयान पर सहमति नहीं बनी, जिसका मूल कारण रूस-यूक्रेन युद्ध ही रहा। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटरेस इस युद्ध के दरमियान दूसरी बार यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात में ब्लैक सी के जरिए फूड एक्सपोर्ट जारी रखने पर जोर दिया गया। युद्ध के दौरान सिर्फ राहत की बात यह रही है कि सात महीने पहले दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि ब्लैक सी से गुजरने वाले किसी ऐसे जहाज पर दोनों देश हमला नहीं करेंगे, जिसमें खाद्य पदार्थ हों। लेकिन मामला सिर्फ इससे हल नहीं होने वाला।

हाल ही में फ्रांस ने यूक्रेन को और हथियार देने का फैसला किया है लेकिन इस बार उसे अपनी जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर आए। लोगों का कहना था कि हथियार देने से जंग बढ़ती जाएगी। अगर सरकार मदद करना चाहती है तो उसे रूस को हमला करने से रोकना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में बैनर थे, जिस पर लिखा था, फॉर पीस (शांति के लिए), नो टु थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह का मार्च जर्मनी के बर्लिन में भी निकाला गया। वहां, लोगों ने रूस से बातचीत कर मसले का हल निकालने की मांग की। ब्रिटेन में कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ब्रिटेन युद्ध रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इतना तो तय है कि रूस और यूक्रेन दोनों देशों को इस युद्ध से भारी नुकसान हो रहा है लेकिन पीछे हटने को दोनों देशों में से कोई राजी नहीं। हां, बीच-बीच में ऐसे बयान जरूर आते हैं जिनसे लगता है कि शायद युद्ध अब रुक जाए लेकिन फिर कुछ ही समय में हमले शुरू हो जाते हैं। इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार, अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।

इस लड़ाई की वजह से पिछले एक साल में दुनिया बुरी तरह से बंट गई है। पश्चिमी देश खुलकर रूस की निंदा करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और यूक्रेन के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन सारे व्यापारिक रिश्ते अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। **एशियाई देशों खासकर भारत और चीन** ने बीच का रास्ता निकाला है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमरे के सामने पुतिन के साथ मुलाकात के वक्त कहा कि आज के दौर में युद्ध कोई समाधान नहीं है लेकिन किसी भी अतंरराष्ट्रीय मंच पर रूस की निंदा करने से बचते रहे। रूस से कच्चे तेल के आयात पर विदेश मंत्री ने भी कहा कि हम पहले अपने देश के हित का ख्याल रखेंगे और अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो खरीदना जारी रखेंगे। नतीजा यह है कि युद्ध से पहले जहां भारत रूस से अपनी कुल जरूरत का महज 2 फीसदी कच्चा तेल आयात करता था वहीं आज रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

उधर, चीन नया चौधरी बनने के चक्कर में शांति पहल के नाम पर कूटनीतिक झांसा देने में लगा हुआ है। चीन ने कुछ दिन पहले अपने जाने-माने राजनयिक वांग यी को यूरोप दौरे पर भेजा और दौरे का समापन मॉस्को में हुआ, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वांग यी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद चीन ने अपनी तरफ से दो दस्तावेज जारी किए। पहले दस्तावेज में युद्ध खत्म करने के उसके अपने फॉर्मूले का जिक्र है, वहीं दूसरे में विश्व शांति की योजना है। उसमें लिखा है कि किसी भी देश (यूक्रेन) की संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है और हर देश (रूस) की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले की रक्षा भी होनी चाहिए। चीन ने इसमें एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध भी किया है। जाहिर है, इस फॉर्मूले पर पश्चिमी देश तैयार नहीं होंगे और चालाक चीन का यह मकसद भी नहीं दिखता। वह तो बस अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। सवाल यह है कि अब आगे क्या? एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अचानक यूक्रेन पहुंच जाते हैं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अचानक लंदन पहुंच जाते हैं लेकिन न तो यूरोपीय संघ, न ब्रिटेन और न ही अमेरिका समेत दूसरे नाटो देश खुलकर **यूक्रेन को सैन्य मदद** दे पाते हैं। हालांकि रूस समेत पूरी दुनिया को यह मालूम है कि हर तरह की मदद यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही है, सिर्फ सैनिक नहीं भेजे जा रहे हैं। फिर भी रूस को अभी तक पीछे धकेल पाना संभव नहीं हो पाया है।

● **कुमार विनोद**

50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान

रूस ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। अभी तक पुख्ते तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि दोनों देशों को मिलाकर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। यूक्रेन से पलायन पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन को अब तक 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उधर, युद्ध के शुरुआती दिनों में ही यूरोपीय देशों ने रशियन सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का 324 अरब डॉलर फ्रीज कर दिया था। तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए और अपनी जरूरत को दूसरे देशों से पूरा करने की कोशिश करते रहे। अब साल बीतते-बीतते वे इस नतीजे पर आ गए कि पूरे यूरोपीय संघ ने रूस से समंदर के रास्ते आने वाले तेल की खरीद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ समय बाद ही ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया कि वे रूसी कच्चे तेल और उसके उत्पादों पर पांच दिसंबर को प्रतिबंध लगा रहे हैं और उन्होंने वैसा कर दिया। मतलब आने वाले दिनों में सही मायनों में रूस को आर्थिक प्रतिबंधों का असर दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि जब क्रीमिया पर हमले के वक्त रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उसी वक्त से पुतिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। 2014 से 2022 के बीच आठ साल में रूस ने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार जमा किया, पेट्रोलियम पदार्थों की खूब बिक्री की और उसका इस्तेमाल और अधिक पाइपलाइन बिछाने में किया।

कोयला खदानों में सेंध लगाती महिला कामगार

कोयला खनन ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी पुरुषों का ही बोलबाला है, लेकिन अब इस क्षेत्र में महिलाओं ने भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है। यह सेंधमारी देश के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्र यानी आसमनसोल और धनबाद में आसानी से देखी जा सकती है। एक बारगी इन इलाकों को देखें तो लगेगा कि यह कोई बीहड़ है लेकिन इस बीहड़ में केवल पलाश के फूल ही इस की भयावहता को कम कर रहे होते हैं। इस बीहड़ में रात-दिन रह-रहकर विस्फोटों की आवाजें जब-तब आती रहती हैं। ये आवाजें आ रही हैं महिला कामगारों के हाथों से तोड़े जाने वाले कोयले के पत्थरों की। इस क्षेत्र में वर्तमान में 3,227 महिला कामगार कोयले की खनन में लगी हुई हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र जहां महिलाओं की भागीदारी विगत में न के बराबर थी, लेकिन अब पिछले डेढ़ दशक में यह तस्वीर बदल चुकी है। और अब इन कोयला खदानों में जहां-तहां महिला कामगार कंधों पर फावड़ा-गैती रखे और सर पर हेलमेट लगाए खदानों में कोयला खनन करती हुई दिख जाएंगी। इनमें अधिकांशत: महिलाएं पश्चिम बंगाल और झारखंड से हैं। आसानसोल और धनबाद की इन बदरंग खदानों के बीहड़ को केवल पलाश के फूल ही थोड़े बहुत रंगीन दिख पड़ते हैं। अब इस रंगीनियत के बीच इलाके की कठोर कोयले की चट्टानों को भारी मशीनरी के द्वारा तोड़ती महिलाएं समाज की लैंगिक रूढ़िवादिता को भी तोड़ती नजर आ रही हैं।

ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड (ईसीएल) कंपनी पश्चिम बंगाल और झारखंड में काम करती है। यह कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी है। ध्यान रहे कि सीआईएल लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार देती है और अपनी इस संख्या के बल पर यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में महिलाओं की शीर्ष नियोक्ता कंपनी है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के कुल 2.4 लाख कार्यबल का यह मात्र 8 प्रतिशत है। और सही अर्थों में देखा जाए तो ऑन फील्ड खनन गतिविधियों में पारंपरिक रूप से पुरुषों की भागीदारी हमेशा से अधिक रही है, इस हिसाब से महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी कम ही आंकी जाएगी। लेकिन इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि पुरुषों का यह गढ़ अब धीरे-धीरे टूट रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड्स ओपन खदान में सोनपुर बाजारी के विशाल क्षेत्र में जहां एक खुले गड्ढे से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहां पर 49 वर्षीय बिंदु पासवान एक विशाल मशीनरी पर चढ़कर कड़ी मेहनत मशक्कत से कच्चा कोयला निकाल रही है। क्षेत्र के अधिकारी ने बताया कि यह अकेले 20 मिनट में 60 टन का एक डंपर भर देती हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि इस महिला कामगार की हमारे सबसे अच्छे कर्मचारियों में गिनती होती है। बिंदु पासवान खुली कोयले की खदानों में से कच्चा कोयला निकालने वाली कई ऑपरेटरों में से एक हैं, जो भारी मशीनरी का उपयोग करके कोयला निकालती हैं। सीआईएल के अधिकारी कहते हैं कि कंपनी के पास कई ऐसी महिला कामगार हैं जो भारी एचईएमएम (हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी) जैसी मशीनरी को बतौर ऑपरेटर आपरेट करती हैं।

बिंदु केवल नौवीं कक्षा पास हैं लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद आसनसोल स्थित ईसीएल में काम शुरू किया। उन्हें यह नौकारी अपने पति की मृत्यु होने के कारण दी गई थी और चार बेटियों की मां ने अपने पति की तरह कंपनी के कार्यालय में नौकरी करने के बजाय खदान में काम करना अधिक मुनासिब समझा। बिंदु कहती हैं कि उनकी बेटियों को उन पर गर्व है। 2010 में उन्हें नौकरी देने के तीन साल बाद ही उनके हाथों में फावड़ा थमा दिया गया और उनकी ड्यूटी कोयला खदानों में लगा दी गई। अपने इस काम पर वह कहती हैं कि यह काम मुझे स्वतंत्रता प्रदान करता है और एक पहचान भी देता है। हालांकि बिंदु अकेली ऐसी महिला नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के धनबाद जिले के बरमुरी खुली खदान में लगभग छह महिला ऑपरेटर और ड्रिल ऑपरेटर काम कर रही हैं। अमोती मेझियान और मालती मेजियान दोनों की उम्र 30 के आसपास है और ये खुली खदान में **कठोर चट्टानों** पर लगातार बेलचे चला रही हैं। यही नहीं बीच-बीच में भारी मशीनरी भी ऑपरेट करती नजर आती हैं। वह अपने इस काम पर कहती हैं कि शुरुआत में इतनी भारी मशीनरी को चलाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब सालों साल के अभ्यास के बाद हमें इसकी आदत सी पड़ गई है। इसी खुली खदान में कोई सौ मीटर की दूरी पर साड़ी पहने सरस्वती मेझियान और बबानी भुनिया एक विशाल ड्रिलिंग मशीन चला रही हैं। यह मशीन कठोर सतह को खोदने में मदद करती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां अधिकतर महिलाएं सुबह की शिफ्ट में काम करना पसंद करती हैं। यह शिफ्ट सुबह छह से दोपहर दो तक की होती है। मालती, सरस्वती और अन्य कई महिलाओं ने 2019 में तो भारतीय खनन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का रास्ता खोला। ध्यान रहे कि 1952 के भारतीय खान अधिनियम ने भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। यही नहीं शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच खुली खदानों में महिलाओं की तैनाती पर रोक लगा दी गई थी। यह प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं और महिला खनन इंजीनियरों को भी प्रभावित करता था, जिसके परिणामस्वरूप काम के स्तर पर यह जेंडर पूर्वाग्रह होता था।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

भूमिगत खदानों में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रही महिलाएं

महिला कर्मचारियों ने खनन गतिविधियों जैसे क्रेन, फावड़ा, ड्रिल, पंखा संचालक सहित और अन्य में विभिन्न चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को न केवल निभाया है बल्कि अपनी क्षमता को भी साबित किया है। भूमिगत खदानों में काम करने से विभिन्न चुनौतियां सामने आती हैं। पोलोमी मुसिब कोलकाता के पास भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से खनन में बीटेक पास करने वाली पहली महिला खनन इंजीनियर थीं। वह 2011 में सीआईएल में भर्ती की गई पहली महिला खनन इंजीनियर भी थीं। मुसिब वर्तमान में बतौर एक खनन इंजीनियर, अंतरा मुखर्जी और प्रियंका चौधरी के साथ नरसमुडा कोलियरी क्षेत्र में स्थित एक भूमिगत खदान में कार्यरत हैं। ध्यान रहे कि कानूनी प्रतिबंध हटने के बाद मुसिब को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए नरसमुडा कोलियरी में तैनात किया गया था। नरसमुडा एक भूमिगत खदान है, जहां सतह से 170 मीटर नीचे से कोयला निकाला जाता है। वह अपने काम के बारे में कहती हैं कि मुझे रोज खान के नीचे जाना पड़ता है और भूमिगत खदानों के अंदर मंद रोशनी वाली सुरंगों में गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं ऊपर आती हूं और हेलमेट हटाती हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर घड़ों से पानी उड़ेल दिया हो।

श्रीमद्भगवत गीता में सफलता का रहस्य

धर्म हठधर्मिता का विषय नहीं है, बल्कि किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, सर्वोत्तम को संभव करने का विषय है। धर्म आस्था से जुड़ा है जो सीधे आपके सूक्ष्म मन तक दस्तक देता है और यह दस्तक हमें श्रीमद्भगवत गीता से मिलती है।

सनातन धर्म की धर्म पुस्तक, भगवान श्रीकृष्ण के शब्दों का पुष्प, जीने की कला और सर्वोत्तम ज्ञान की पवित्र पुस्तक ऐसे अनेकानेक नामों से सुसज्जित श्रीमद्भगवत गीता वह पुस्तक है जिसे भारत की राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में सबसे सुंदर शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। सदियों से, वर्तमान तक गीता सबसे लोकप्रिय, अमूमन पढ़ी जाने वाली, दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित और भारत की संस्कृति के अनुसार जीने के शिक्षा पर आधारित है। यह प्रतिस्पर्धा से परे है।

भारत को जानना है तो श्रीमद्भगवत गीता को पढ़ना होगा। इस पुस्तक की गहराई और जीवन के बारे में इसके गंभीर निर्देश, मानवीय बातचीत, मानव मनोविज्ञान के रहस्यों और उच्च चेतना की कुंजी को समझना होगा। गीता, भारत की सभी जटिलताओं, विरोधाभास, रहस्य और सुंदरता को दर्शाती है, यह शाश्वत और अनंत है। यदि हम गीता पढ़ रहे हैं तो इसके सभी स्तर के ज्ञान को आत्मसात कर जटिलताओं से भरा जीवन जीना चाहिए ऐसा करने पर पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफी हद तक जीवन सरल होने की संभावना बनती है। श्रीमद्भगवत गीता, भगवान श्रीकृष्ण का ज्ञान है जो शब्दशः पुस्तक में मौजूद है। श्रीकृष्ण ईश्वर का रूप हैं और धरती पर एक ऐसे महामानव के रूप में जन्म लेते हैं जो दुनिया में, भारत की गहन योग संस्कृति और सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में आज भी मौजूद हैं। वो दिव्य अवतार, योगावतार, और उच्चतम क्रम के ऋषि के रूप में पहचाने जाते हैं, जो लोगों के सभी स्वभावों को कई तरह से रास्ता सिखाने और दिखाने में सक्षम हैं, उन्होंने मानवता को अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। श्रीकृष्ण दिव्य व्यक्तित्व हैं एक अतुलनीय करिश्मा जो हम सभी के भीतर परमात्मा के अंश को प्रेरित करने का काम करते हैं, वो हमें बड़ी स्पष्टता और सटीकता से जीने की कला सिखाते हैं।

युद्ध के मैदान में श्रीमद्भगवत गीता की उत्पत्ति, सम्मोहक है। यह बताती है कि सारा जीवन प्रकृति, मानवता, विशेष रूप से धर्म और अधर्म की शक्तियों के भीतर और आसपास के कई द्वंद्वों के बीच का संघर्ष है। इतना सबकुछ होने के बाद भी, यह जीवन अच्छाई और बुराई के बीच एक साधारण और समान नहीं है। जीवन प्रकाश और अंधकार जैसा है यानी यहां सुख और दुख दोनों ही हैं, यह दोनों ही आते-जाते रहते हैं। यहां नैतिक संघर्ष है, जिसमें सच और झूठ के विकल्प में से एक को चुनना होता है, यही आपकी जीवन की दिशा तय करता है।

जीवन विपरीत प्रभावों को लेकर, कई दिशाओं में चलता है। यह प्रतिस्पर्धी ताकतों के चक्रव्यूह में, आगे बढ़ने का संघर्ष है। गीता की शुरुआत में अर्जुन की तरह, दर्द और जटिलताओं से बचने के लिए, 'संघर्ष नहीं करना' हमारे लिए आसान है। हम जीवन को हमारे पास से गुजरने देते है। उसकी सीमाओं की निंदा करते हैं, और जो हम पहले ही तय कर चुके हैं, लेकिन यहां तय करने जैसा कुछ नहीं है। सबकुछ अनिश्चित है। जीवन संघर्ष है, सफलता इसी में है कि आप आगे चलते जाएं, रुकें नहीं।

श्रीमद्भगवत गीता हमें रास्ता दिखाती है कि जब हमारे जीवन रूपी युद्ध में आदर्श परिस्थितियां कम हों तब सफल होने के लिए इसे सर्वोत्तम और संभव कैसे बनाया जा सकता है। गीता कहती है कि आपके पास मन यानी चेतना जैसा शक्तिशाली हथियार है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो केवल नकारात्मकता और जड़ता की ताकतें हावी होंगी, यही आपकी जीवन की दशा और दिशा तय करेगी, इसीलिए चेतना जागृत कीजिए।

यदि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं और उन पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम कमजोर रह जाते हैं और इस तरह अपने भीतर मौजूद ईश्वर के अस्तित्व को खोजने में असफल हो जाते हैं। हम जीवन में अपने सर्वोच्च कर्तव्य की सेवा किए बिना, व्यक्तिगत स्तर पर तृप्ति नहीं पा सकते हैं। गीता हमारे व्यक्तिगत सार को दिखाती है लेकिन सार्वभौमिक होने के हिस्से के रूप में भगवान श्रीकृष्ण हैं।

गीता का अंतिम संदेश है कि मृत्यु नहीं है। कोई भी वास्तव में पैदा नहीं होता है या मर जाता है। हम शुद्ध चेतना के रूप में, आंतरिक दिव्य प्रकृति में अमर हैं। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं और आत्मा के लिए जीवन-मृत्यु केवल वस्त्र हैं। हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्म-ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमारे अस्तित्व के मूल में है, बस इसे जागृत करना है ताकि बाहरी ताकतें आपको परेशान न कर पाएं। महाभारत युद्ध मैदान में, अर्जुन की दुविधा, जीवन में हमारी आवश्यक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम सभी अपूर्ण हैं, लेकिन एक उच्च पूर्णता की भावना रखते हैं जिसे हम बड़े प्रयास से जागृत कर सकते हैं। यदि हम अपने अंदर के अर्जुन को अपने भीतर जागृत कर लेते हैं तो जीवन में हमारी सफलता की कुंजी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम उनके असंख्य रूपों में भगवान श्रीकृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन का ज्ञान यानी नियमित श्रीमद्भगवत गीता का अध्ययन करें।

● **ओम**

झूठी इज्जत

पार्टी पूरे जोरों-शोरों पर थी। शीना की सभी सहेलियां और अड़ोस-पड़ोस की औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थीं। आखिर आज के मॉडर्न जमाने में घर के बड़े बुजुर्गों को कौन इतना मान-सम्मान देता है भला, और तुमने तो अपने ससुरजी के 70वें जन्मदिन की इतनी बड़ी पार्टी आयोजित की, कहते हुए सामने वाली आंटी जी ने शीना को ढेरों आशीर्वाद दिए। जमकर फोटोशूट भी हुआ। ससुरजी के चरण स्पर्श कर शीना और पति श्याम ने आशीर्वाद लिया। उनके पैर बहुत गर्म थे, शायद उनको तेज बुखार था। पार्टी खत्म होते ही उन्हें स्टोर रूम में सोने को भेज दिया गया। शीना ने तुरंत सभी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की और ससुरजी को दवाई दिए बगैर ही सोने चली गई।

- पिंकी सिंघल

एमर्जेंसी ड्यूटी

यह इत्तेफाक ही था कि जिस दिन उसे सावधि जमा योजना के पैसे मिले, उसी दिन गांव से पिताजी का तार आया- 'तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब है, अच्छा होगा कि उसे इलाज के लिए शहर ले जाओ।'

वह सोच ही रहा था कि पत्नी ने कहा- 'देखो जी अब तो कुछ पैसे इकट्ठे मिले हैं, क्यों न किसी अच्छी जगह घूम आएं।'

'लेकिन।'

वह कुछ कहता, इसके पहले ही पत्नी बोल पड़ी- 'उनको यहां लाने से पहले मुझे मेरे मायके छोड़ देना। मैं आखिर कब तक तरसती रहूंगी। उनकी बीमारी के कारण ही आपने मुझे एक बार भी कहीं बाहर नहीं घुमाया, अब बड़ी मुश्किल से चार पैसे हाथ आए हैं तो तुम फिर वही सब।' और वह रो पड़ी।

'अच्छा बाबा, अब चुप भी करो, मैं पिताजी को लिख देता हूं कि दफ्तर में इमर्जेंसी ड्यूटी के कारण मैं नहीं आ सकता।' और फिर दोनों पर्यटन के लिए कुल्लू-मनाली चले गए। एक महीने बाद जब वापस आए तो पिताजी का तीन दिन पुराना संदेश मिला- 'तुम्हारी मां गुजर गई। समय मिले, तो अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए आ जाना।'

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

सीमाएं

सीमाओं में बंधकर सृष्टि,
रूप अनेकों पाती है,
बंधन ही तो मुक्ति की सीमा,
गर्वित हो कह जाती है।

जब-जब सीमाएं टूटी हैं,
दुख के वारिद बरसे हैं,
उजड़ी संस्कृति और सभ्यता,
प्रगति हेतु पल तरसे हैं,
इच्छाएं सीमा में रहकर,
मंगल ध्वज फहराती हैं,
बंधन ही तो मुक्ति की सीमा,
गर्वित हो कह जाती है।

सूर्य, चंद्रमा, धरती, अम्बर,
सिमटे सब सीमाओं में,
सीता ने विश्वास किया ना,
लक्ष्मण की रेखाओं में,
ये नन्हीं त्रुटियां ही नभ को,
धरती पर ले आती हैं,
बंधन ही तो मुक्ति की सीमा,
गर्वित हो कह जाती है।

नियम नीतियां प्रतिपालक है,
सज्जनता शुभदाई है,
वाणी, वचन, कर्म की परिधी,
मर्यादा फलदाई है,
गगन धरा का हरित छोर ले,
चुनर हरी लहराती है,
बंधन ही तो मुक्ति की सीमा,
गर्वित हो कह जाती है।

- सीमा मिश्रा

आईपीएल के 16वें संस्करण का आगाज

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 16वां संस्करण 31 मार्च से शुरू होकर 28 मई तक चलेगा। लगभग 2 महीने चलने वाली दुनिया की इस लोकप्रिय लीग में 74 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 70 लीग मुकाबले हैं जबकि 4 अन्य मैचों में प्लेऑफ और फाइनल शामिल है। खास बात यह है कि आईपीएल खेलने का सपना हर किसी खिलाड़ी का होता है। लेकिन इस बार लीग पर चोटों का साया इतना गहरा है कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने कप्तान बदलने पड़े। दिल्ली ने पंत की जगह पर इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को कप्तान बनाया है।

आईपीएल में इस साल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये सभी टीमें प्लेऑफ तक पहुंचने का दमखम रखती हैं। ऐसे में खेल-प्रेमी और विशेषज्ञों के दिमाग में एक बात चलने लगी है कि इस बार वे कौन सी टीमें होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। इन टीमों में सबसे पहला नाम है पिछले सीजन में ही लीग में जुड़ी गुजरात टायटंस का, जिसने खिताब जीतकर तहलका मचा दिया था। लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर सबकी नजरें रहेंगी। इसका पहला कारण है कोहली अपनी फार्म में लौट आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस सूखे को आरसीबी इस बार आईपीएल का खिताब जीतकर खत्म कर देगी।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वह बड़ी टीम है जिसके पास हमेशा बड़े-बड़े खिलाड़ी रहे हैं और फैन फॉलोइंग भी काफी रही है। लेकिन यह टीम आईपीएल के इतिहास में आज तक खिताब नहीं जीत पाई है। खिताब जीतने के लिए जरूरी है प्लेऑफ खेलना और इस सीजन में आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। विराट कोहली जहां फॉर्म में लौट चुके हैं, वहीं दिनेश कार्तिक, फॉफ ड्यूप्लेसी, वानिंदू हसरंगा, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी इस बार टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेल चुकी है लेकिन चैंपियन एक बार भी नहीं बन पाई है।

चेन्नई सुपर किंग्स: चार बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली और सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड रखने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स इस साल एक बार फिर से खिताब जीत सकती है। धोनी अपनी करिश्माई कप्तानी और बेहतर टीम संयोजन के दम पर अपनी टीम को चैंपियन बनाने की क्षमता रखते हैं और संभवत: अपने आखिरी सीजन में वे अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहेंगे। कप्तान धोनी के लिए टीम के सभी खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जडेजा के टीम में बने रहने, दीपक चहर के उपलब्ध होने, अजिंक्य रहाणे और बेन स्टोक्स के टीम से जुड़ने के बाद टीम मजबूत भी हुई है। चेन्नई 2010, 2011, 2018 और 2021 में चैंपियन रह चुकी है।

गुजरात टायटंस: हार्दिक पंड्या की कप्तानी में गुजरात टायटंस ने आईपीएल का अपना पहला सीजन (2022) जीतकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद टीम इंडिया के टी-20 फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए भी हार्दिक ने काफी प्रभावित किया है और टीम को लगातार जीत दिलाई है। गुजरात के पास हार्दिक पंड्या के अलावा, राशिद खान, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, केन विलियमसन और अल्जारी जोसेफ जैसे खिलाड़ी हैं जिनके दम पर यह टीम एक बार फिर से प्लेऑफ खेल सकती है।

दिल्ली कैपिटल्स: दिल्ली कैपिटल्स को खेल शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत चोटिल हैं और पूरे सीजन से बाहर रहेंगे। इसके बावजूद दिल्ली को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। दिल्ली के पास कप्तानी कर रहे डेविड वार्नर के अलावा, मिचेल मार्श, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, एनरिक नॉर्तजे, लुंगी एंगिडी, अक्षर पटेल, रिली रुसो और रोवमन पॉवेल जैसे खिलाड़ी हैं जो टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। आईपीएल में दिल्ली का बेस्ट प्रदर्शन 2020 में आया दिखा था। इस साल टीम फाइनल में पहुंची थी लेकिन मुंबई से उसे हार का सामना करना पड़ा था।

लखनऊ सुपर जायंट्स: आईपीएल 2022 में गुजरात टायटंस के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी एंट्री मारी थी। केएल राहुल की कप्तानी और गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम ने खिताब जीतने में तो सफलता नहीं पाई लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और टीम प्लेऑफ में पहुंची थी। लखनऊ के पास केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, क्रुणाल पंड्या, डेनियल सैम्स, काइल मेयर्स और निकोलस पूरण जैसे खिलाड़ी हैं जो टीम को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। इन खिलाड़ियों के दम पर टीम आईपीएल 2023 का खिताब भी जीत सकती है।

राजस्थान रॉयल्स: आईपीएल का पहला सीजन (2008) जीतने वाली और पिछले सीजन में संजू सैमसन की कप्तानी में गुजरात टायटंस के साथ फाइनल खेलने वाली राजस्थान रॉयल्स भी इस साल खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है। कुमारा संगरकारा के नेतृत्व में टीम का मैनेजमेंट जहां काफी शानदार है वहीं टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतर तालमेल भी है जिसका असर पिछले सीजन में दिखा था। पिछले सीजन में ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों अपने नाम करने वाली राजस्थान रॉयल्स में कप्तान संजू सैमसन, जोस बटलर, युजवेंद्र चहल के अलावा शिमरोन हेटमायर, एडम जाम्पा, ट्रेंट बोल्ट, जेसन होल्डर, ओबेड मैककॉय यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, कुलदीप सैन, रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस टीम को एक बार फिर चैंपियन बनाने का माद्दा रखते हैं।

● **आशीष नेमा**

करिश्मा कपूर संग होने वाली थी अक्षय खन्ना की शादी, एक्ट्रेस की मां को मंजूर नहीं था रिश्ता

अक्षय खन्ना का नाम बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों की लिस्ट में शामिल है। इस एक्टर ने हमेशा अपने अभिनय से ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी काफी इम्प्रेस किया है। अक्षय खन्ना दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे हैं। बेशुमार टैलेंट और स्टारकिड होने के बावजूद इस एक्टर को वो स्टारडम और सफलता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। अक्षय खन्ना ने 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म को एक्टर के पिता विनोद खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया था। भले ही हिमालय पुत्र बॉक्स-ऑफिस पर कोई खास कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन इस फिल्म ने एक्टर के लिए इंडस्ट्री में राह बना दी थी। इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे।

अगर इस एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अक्षय खन्ना ने आज तक शादी नहीं की। कैरियर के शुरुआती दिनों में इस एक्टर का नाम कई एक्ट्रेसेज के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ शादी की बात नहीं हो पाई। बहुत कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे की रणधीर कपूर अपनी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से कराना चाहते थे। कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने इस बारे में विनोद खन्ना से बात भी कर ली थी, लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दरअसल, उस दौर में करिश्मा कपूर अपने कैरियर के पीक पर थीं, जबकि अक्षय खन्ना की फिल्में कुछ खास सफल नहीं हो पा रही थीं। इसके बाद, अक्षय खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह शादी करना ही नहीं चाहते हैं।

संजय दत्त की दोस्ती से मुश्किल में फंस जाते थे सुनील शेट्टी, कई बार हुए परेशान, बोले- होटल से भागना पड़ता था

हेरा फेरी 3 में परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी तो होंगे ही, इस बार संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। कॉमेडी फिल्म के इस सीक्वल में संजय भी एक नए किरदार के तौर पर एंट्री ले रहे हैं। सुनील और संजय ने पहले भी साथ काम किया है। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में हेरा फेरी के सीक्वल में संजय दत्त की एंट्री पर खुशी जताई। इतना ही नहीं एक्टर ने गारंटी दे डाली कि संजय दत्त की वजह से फिल्म एक अलग स्तर पर जाएगी। संजय की वजह से ये फिल्म लोगों को और हंसाएगी, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज यूनिक है।

संजय की दोस्ती सुनील पर पड़ जाती थी भारी

जब दोनों की आपसी बॉन्डिंग पर सवाल किया गया तो इसके जवाब में सुनील ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि संजय की वजह से वे कई बार मुश्किल में पड़ जाते थे। दोस्ती ऐसी भारी पड़ती थी कि कई जगहों से भागना तक पड़ जाता था। सुनील ने कहा- संजय हमेशा से एक कूल पर्सनैलिटी रहा है, उसमें लड़कपन बहुत है और वह हमेशा ऐसा ही रहेगा भी। संजय एक बेहद अच्छे दोस्त हैं पर उतने ही ज्यादा शैतान और बदमाश भी हैं।

मशहूर अदाकारा के प्यार में दीवाने थे शोले के ठाकुर, एक्ट्रेस ने किया शादी से इनकार, तो जिंदगी भर रहे कुंवारे

फिल्म शोले का बिना हाथ वाला ठाकुर तो आपको याद ही होगा, जी हां, इस फिल्म में अपने उम्दा अभिनय से एक्टर संजीव कुमार ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। संजीव कुमार अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्खियों में बने रहते थे। इस एक्टर ने अपने दौर में कई बड़ी एक्ट्रेसेज के साथ काम किया और दो मशहूर एक्ट्रेसेज के साथ तो उनका नाम भी जुड़ा था, लेकिन किसी के साथ भी उनका इश्क मुकम्मल न हो सका।

जिंदगीभर नहीं की शादी

बॉलीवुड के गलियारों में यूं तो अक्सर ही सेलेब्स की लव लाइफ के चर्चे होते रहते हैं। लेकिन संजीव कुमार बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के इश्क में कुछ इस कदर कैद हुए थे कि फिर उन्होंने पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की। संजीव कुमार और हेमा मालिनी त्रिशूल, शोले, सीता और गीता जैसी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे थे। एक्टर ने तो ड्रीम गर्ल के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

आखिर ऐसा क्यों होता है

आज बेटी का जनम पाने का अफसोस हो रहा है। कई दिनों से मैं इस गहन चिंता में थी कि मेरा हीरा जनम, कौड़ी बदले क्यों जा रहा है? मेरे संगी-साथी नहीं, जूनियर भी, कहां से कहां से पहुंच गए और मैं ख्याली पुलाव पकाती, जहां की तहां बैठी हूं। आत्ममंथन, आत्मज्ञान आदि-आदि के बाद आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मेरा बेटी, पत्नी, मां अर्थात् कुल मिलाकर स्त्री होना, मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है।

हमारे यहां बेटियां पांव नहीं छूतीं। विवाह के समय बेटियों के पांव छुए जाते हैं। नवरात्रों में कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं। एक उच्चाधिकारी के सामने दो प्रतिभाएं होती हैं। एक बालक, एक बालिका। गुण-योग्यता बराबर। बालक श्रद्धानत होकर उच्चाधिकारी के चरण आते-जाते छू लेता है। बालिका खींसें निपोरती रह जाती है। परिणाम क्या? सेवा का फल बालक की झोली में जा पड़ता है। चरण-स्पर्श बराबर वजन पर पासंग का काम करता है।

दृष्टांत को दफ्तर के दुधारे गलियारे से निकाल साहित्य की सरस गली में ले जाती हूं। तुलसी की कविता पूजा में स्थान पा गई और मीरा की विष का प्याला। कारण साफ है। तुलसीदास शुरू ही चरण वंदना से हुए- श्री गुरु चरण सरोज रज। मीरा को चरण कमल प्राप्त ही नहीं हुए। गुरु के चरणों में शीश नवाए बिना रचना सफलता को प्राप्त हो ही नहीं सकती। अगर पांव परसने बेटी आती तो पाप लगता। बहन-बेटी से पांव छुआते नहीं। मां के पांव छुए जाते हैं। रह गई बीवी सो चरणदासी और प्रियाओं का वास हृदय में।

साहित्यकारों ने अपनी श्रीमतियों को साहित्य में प्रोत्साहित नहीं किया। मुकाबला हो जाता। जहां टक्कर कांटे की थी, वहां डगर भी कंटकाकीर्ण ही रही। प्रियाओं को अलबत्ते लोगों ने प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहन था, पर इतना ही था, जिसके चलते प्रिया अनुगामिनी और वामांगी रहे। आगे निकलने को हुई तो बता दी रहस्य की बात। उनके लिए हम ही लिखते थे! अब कौन दुष्ट हस्तलेख का विशेषज्ञ से परीक्षण कराने जाएगा? कह दिया सो सिद्ध! वो झूठ बोलेगा मुझे लाजवाब कर देगा। मैं सच बोलूंगी तब भी हार जाऊंगी। वह भाईसाहबों और भाभीजियों के पांव छू-छूकर साहित्य में दाखिल हुए और जगह छेककर बैठ गए। बेचारी बहनें भाईसाहबों के स्वेटर ही बुनती रह गईं। आदमी का असली चेहरा पहचान ही न सकीं।

असलियत न चेहरा बताता है, न वस्त्र। बोली तो होती है धोखा। आंखें देती हैं दगा। ऐसे में इंसान का असल रूप जानने का जरिया है उसकी चरणपादुकाएं। चेहरा न देखिए, सिर्फ चरणों पर निगाहें जमाकर बैठें। पादुकाएं इंसान का पूरा हाल बताती हैं।

जो सड़कों पर चलते हैं, (चलना और टहलना अलग है)। द्वार से वाहन तक चलना और वाहन से उतरकर बिल्डिंग से सामना, चलना नहीं है। चलना वह, कि जहां इंसान का सफर पांवों के भरोसे ही पूरा होता हो। ऐसे सड़क अनुरागियों के पैर में पादुकाएं होती हैं।

बेचारी पादुकाएं!

घिसते जाना और घिसटते जाना ही उनकी नियति है, स्त्रीलिंग जो ठहरी।

जो शान से चमकता है और काटता भी है वह होता है जूता यानी यहां भी शान मर्द की। वह बड़े-बड़े रईसों के पैर की शोभा बढ़ाता है। मेहनतकश इंसान के पैरों में घिसती है चप्पल। यह भेदभाव सिर्फ मर्द के पैरों में नहीं होता, औरत की दुनिया में भी होता है। रोज रसोई और बाजार में खटती है चप्पल और पार्टी में जाते हैं चमचमाते सैंडल। सैंडल पहने जाते हैं, उतारे जाते, संभाल कर रखे जाते हैं यानी व्याकरण की दुनिया में भी पुलिंग का ही बोलबाला है।

अब जरा गहने जेवर की बात करें...हार, कंगन, झुमके...सबके सब ऊंचे पदों पर बैठने वाले गहने पुरुष हैं और सोने में बने हैं लेकिन पायल बिछिया जैसे स्त्रीलिंग गहनों को चांदी से ज्यादा कुछ नसीब नहीं। जगह भी उनकी पैरों में ही है।

सब्जियों में आलू, गोभी और टमाटर मर्दों के नाम पर रजिस्ट्री ले चुके हैं। आलू छोटा है। गोभी ताजा है और टमाटर बड़ा है यानी सबसे लोकप्रिय सब्जियां पुरुष के खेमे में शामिल हो चुकी हैं। हर दावत में, शादी-ब्याह उत्सव में मांग और पूछ सिर्फ उनकी है। बेचारी लौकी-तोरी रजिस्टर की गई है महिलाओं के नाम पर। लौकी मोटी है, तोरी पतली है जैसे महिलाओं के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाक्यों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उन बेचारियों को छोड़ दिया जाता है बीमारों और बूढ़ों की सेवा के लिए। बेचारी खटती रहती है। औरत का नसीब ही ऐसा है मरने खटने वाला।

सड़क पर निकलो तो गाड़ियों को देखो, लोगों को भर-भर कर दौड़ रहीं हैं। लोग हैं कि ऐश कर रहे हैं। सड़क है कि घिस-पिट रही है और पेड़ हैं कि लहलहा रहे हैं। यही क्यों? बगीचे में देखिए- घास बेचारी आम आदमियों की तरह रौंदी जा रही है और फूल हैं किनारे क्यारियों में ऐश कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं।

मानो न मानो स्त्री का दुर्भाग्य सिर्फ इंसान का रचा हुआ नहीं है, लगता है कि भगवान भी पुरुष के साथ मिला हुआ है...क्यों नहीं, क्यों नहीं आखिर भगवान भी तो पुरुष ही है न? तो फिर जो ये कहते हैं कि दुनिया पुरुषों की बनाई हुई है उसमें कोई संदेह नहीं। खुद दुनिया बनाके थक गया तो इंसान के निर्माण का काम स्त्री के सिर पर डालकर हवा खाने चल दिया। और अब आधी दुनिया बेचारी बैठी हैं इंतजार में कि ऊपरवाला लौटे और देखे कि उसकी बेटियों के ऊपर कैसे-कैसे दुख के पहाड़ टूट रहे हैं और बाकी दुनिया मजे लूट रही है। किसी को कोई अफसोस ही नहीं!

● **अलका पाठक**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687